पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 10 अंक 28 प्रति सोमवार इंदौर, 22 से 28 फरवरी 2016 पृष्ठ 12 मूल्य 2/- रुपए

1970 से पाक को धन देकर आतंकवाद की फैक्ट्री बना दिया दुनिया में

दुनिया पर अमेरिकी दादागिरी का व्यवसाय आतंकवाद

पूरे विश्व में हो रहे आतंकवाद के तांडव से न केवल आतंकवादी, आतंकियों के समर्थक, वरन आतंक से पीड़ित पूरी दुनिया के भारत, फ्रांस समेत सीरिया, इराक, अफगानिस्तान के साथ ही अमेरिका ब्रिटेन जैसे दुनिया के दिग्गज राष्ट्र भी सहमे हुये और पीड़ित नजर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण 1970 से लेकर सन् 2000 तक इन आतंकी संगठनों को पाल पोसकर बड़ा करने में ही इन जालसाजों की ही भूमिका रही है। अब जब वो आतंकी समझदार हो चुके हैं तो इन्हीं के गले का फंदा बन चुके है।

प्रकृति का सिद्धांत है कि जो मकड़ी दूसरी छोटे कीट-पतंगों को फांसने के लिए जाला बुनकर केन्द्र में उंघती बैठ शिकार करती है वही हाल अंत में वहीं फंसी रहकर मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी उस मृत देह उसी जाल में फंसी रहकर सड़ती रहती है। ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस व अन्य हथियार उत्पादक देशों ने अपने हथियारों की बिक्री के

समयमाया 1998 से अमेरिकी हथियार बैचने, द. एशिया में आतंकवाद का तांडव करवाने के बारे में लिखता रहा, आतंकवाद व युद्ध है नाटो का पेशा, भारत की विरोध के बाद भी पाक को एफ-16 लड़ाकू विमान दे रहा आतंकी अमेरिका

लिए जो विपणन व्यवस्था चुनी और मार्गदर्शिका तैयार की थी उसके केन्द्र बिंदुओं में ईराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र दक्षिण एशिया में आतंकवाद को बढ़ावा देकर अपने हथियारों की बिक्री भारत, पाकिस्तान, चीन, उत्तरी, दक्षिणी कोरिया, ईरान, ईराक, कुवैत अरब आदि देशों में अरबों डॉलर की कमाई कर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चलाया गया बदले में अपने हथियार बैचने के लिये इन देशों में विकास और नगरीय संरचनाओं के विकास के नाम पर खूब कर्ज एशियन विकास बैंक, विश्व बैंक से बंटवाकर वहां की प्रशासनिक मानव संसाधनों को भ्रष्ट बनाकर पुनः कर्ज के नाम पर गुलाम बनाने की रणनीति पर अभी भी कार्य चल रहा है।दक्षिण एशिया में भारत जैसे राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व बनाये रखने अपने हथियारों से लेकर हर माल तकनीकी, ऊर्जा, औषधियां, संचार वैमानिकी, कृषि, स्वास्थ्य उपकरण, मशीने आदि का सबसे बड़ा बाजार है। (शेष पेज 5 पर)

गुलाम खुश हुये कि राष्ट्रगीत को सं.रा. ने श्रेष्ठ राष्ट्रगीत बताया

जन-गण-मन गुलामी का गीत अधिनायक, आधीनता का परिचायक

राष्ट्र को 99 वर्ष के पट्टे की आजादी को 69 वर्ष पूरे होने जा रहे है। हमारे देश को औपनिवेशिक गणराज्य भी बने 66 वर्ष 26 जनवरी को पूरे हो गये, परंतु हम उस अंग्रेजों के चाटुकार रविन्द्र नाथ ठाकुर जिससे 1911 में लिखे गुलामी के गीत जन-गण-मन अधिनायक जय है, जो कि जार्ज पंचम की 1919 में ब्रिटेन से भारत की अगवानी में लिखा गया था, जिसका अर्थ था, भारत के जन उनके गण, मन से उसे अधिनायक अर्थात हम जिसके अधीन है और जो हमारे नायक हैं, कि उनकी जय करता है। जो कि हमारे भारत के पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविण अर्थात दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिल, केरल, आंध्र प्रदेशों की धरती प्राकृतिक संपदा, उत्कल अर्थात उड़ीसा, बंग अर्थात बंगाल, भारत की दो श्रेष्ठ पर्वत श्रंखलायें, विंध्य और हिमाचल, भारत की दोनों, महान पौराणिक

राष्ट्रगीत में ही गुलामी का गीत गाकर अपनी गुलाम मानसिकता का परिचय देकर, गुलामी का आव्हान करेंगे तो चारों तरफ से गुलाम होंगे ही

नदियां गंगा और जमुना की उछलती हुई जल की तरंगे आदि शुभ नाम को जागते ही प्रतिबद्ध अपने ब्रिटानी आकाओं से शुभ आशीष देने की मांग करती है। जब-जब आपकी अर्थात आकाओं की जयगाथा गाई जाती है, जन उनके गणों को मंगल देती है, ऐसे ब्रिटानी आकाओं की जय हो, जो हमारे भारत के भाग्य विधाता है, उनकी जय हो, जय हो, जय हो। वाह रे, अनादिकाल से भारत की धरती श्रेष्ठतम ज्ञान का केंद्र रही है, जिसने दुनिया को चार वेदों ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और आयुर्वेद का ज्ञान तो क्या समझ पाए आज तक वरन आधारभूत भाषा अक्षरो, अंकों का ज्ञान भी तो विश्वभर को भारत से ही मिला। ऐसे महान देश के सभी गौरव जन, उसके गण, उसकी पावन धरती, पर्वत शृंखलाएं, उसकी महान नदी गंगा जिसे स्वर्ग से धरती पर पीढ़ियों की तपस्या के बाद धरती का ज्ञान, जीवन, पर्यावरण को पावन करने लाया गया हो, अगर वो जन अपने ब्रिटानी म्लेच्छों की इस तरह वंदना करते हो, तो क्यों न ऐसे गुलामी के गीत लिखने वाले को गीतांजलि जो कि तिब्बत में रखे गीता के संस्कृत भाषा का हिंदी, अंग्रेजी रूपांतरण था, नोबल पुरस्कार दिया जाये। (शेष पेज 2 पर)

फेसबुक आतंकियों का मंच- सरकार, युवा पीढ़ी संभलों, सारी जानकारियां आतंकियों को

जुकरबुर्ग आतंकियों का संरक्षक- तत्काल बंद हो फेसबुक

भारत संचार मंत्रालय भ्रष्ट, निकम्मा, गूगल, फेसबुक, ट्वीटर, पूरा इंटरनेट अमेरिका से संचालित, पहले सारी जानकारियां अमेरिकी सर्वर को जाती है, 15 वर्ष बाद भी सरकारी स्वयं के सर्वर और संचालन की व्यवस्था नहीं, फिर भी मूर्ख कामकाज ऑनलाइन करने पर तुले है

आधुनिक संचार माध्यमों यथा इंटरनेट, मोबाइल सेवायें आदि ने बेशक आम लोगों की जिंदगी को जहां एक तरफ सुविधायें प्रदान की है, तो दूसरी तरफ आम आदमी से लेकर सरकारों तक की सारी गोपनीयता न केवल भंग की है, वरन् इस इंटरनेट ने हर उपयोग करने वाले की जिंदगी को ऑनलाइन बाजार में खड़ा कर दिया है। हालात ये है कि वर्तमान में मोबाइल कंपनी ही हजारों करोड़ का उपभोक्ताओं का डाटा व्यावसायिक कं. के साथ ही यौनाचार का अवैध व्यापार करने वे व्यावसायिक फर्मों को बैचकर कमा रही है। कहानी यहीं नहीं थमी है। जिस वाट्सएप के करोड़ों उपयोगकर्ता है, वाट्सएप उनके डाटा से ही करोड़ों की कमाई कर रही है। यहां तक कि न केवल केंद्रीय, राज्य सरकारें, क्षेत्रीय प्रशासन भी अपनी बत्तदमीजीयों, भ्रष्टाचारों, जालसाजियों के समाचारों को उड़ाने, न भेजने, रोकने तक के लिए हजारों-करोड़ रुपए खर्च करने से नहीं चूक रही है। बेशक सरकारें इससे यथार्थ जानने, आतंकवादी व अन्य अवैध कृत्यों को रोकने के लिए इसका उपयोग करें, परंतु इसके विपरीत वे ये कार्य न करके अपने भ्रष्टाचारों, जालसाजियों के बारें में जानकारियों का प्रेषण और प्रचारों पर ही रोक की व्यवस्था करने में लगी है। जबकि अकेले इंदौर में ही सिमी के 8 दिसम्बर 2015 के प्रदर्शन में ही वाट्सएप ने सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। प्रशासन सबकुछ जानने के बाद भी नियंत्रण करने में नाकाम रहा।

(शेष पेज 2 पर)

365 दिन के वेतन पर शास. कर्मचारी करते है मात्र 180 दिन काम

समाप्त करो छुट्टियां शनिवार की, बंद करो जन-धन की बर्बादी

साढ़े दस के समय की अपेक्षा पहुंचते है 11 बजे तक, भोजन अवकाश आधे घंटे की अपेक्षा 1 से डेढ़ घंटे तक चलता है, पुलिस को साप्ताहिक तो दूर माह में भी छूट्टी नहीं, ये दो गलापन क्यों?

मप्र में सत्ता की तीसरी पारी में राज करने वाला मु.मं. शिवराज जानता है कि शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों को खुश रखना ही सत्ता पाने और चलाने की सत्ता की चाबी है। इसलिए भले ही शासन का खजाना खाली पड़ा हो, वरन् वेतन बांटने के लिये भी न केवल ओवर ड्राफ्ट, महंगाई बांटने, छटवा वेतन मान बांटने के लिये आंखभींच कर न केवल आदेश जारी करता है वरन् अब हर शनिवार को भी स्थाई अवकाश की स्वीकृति की तैयारी की जा चुकी है। जबकि अभी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को 365 दिन के वेतन पर कार्य मात्र औसतन 200 दिन ही करते है। वर्ष में 52 रविवार, 24 शनिवार और 24 से ज्यादा छुट्टियां त्यौहारों को मिलाकर ही सौ दिन हो जाते हैं। इसके बाद 13 आकस्मिक अवकाश, 33 अर्जित अवकाश, 15 दिन के चिकित्सा अवकाश पूर्ण वेतन के साथ वैधानिक तौर पर एक शासकीय कर्मचारी अधिकारी लेने का पात्र होता है। यह अंग्रेजों की व्यवस्था आजादी के बाद से अभी तक चली आ रही है।

जबकि दशहरे पर अधिकांश कर्मचारी, अधिकारी 21 अक्टूबर से गायब होकर 26 अक्टूबर को कार्यालय पहुंचे। वही हाल दीवाली पर भी हुआ कि 9 से गायब होकर सीधे 16 नवम्बर 15 को कार्यालय पहुंचे। अधिकांश राजधानी के कार्यालयों से लेकर दूरदराज के जिलों, संभागीय मुख्यालयों से लेकर दूरदराज गांवों तक में 90 प्रश में ताले तक नहीं खुले और जहां खुले वहां केवल चपरासी ही नजर आये। यही हाल होली और नवरात्रों अर्थात मार्च व अप्रैल के महीनों में भी होता है, जबकि दीवाली पर इस बार मात्र घोषित रूप से 11 नव. की ही छुट्टी थी।

(शेष पेज 8 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

सत्ता बाप की जागीर

पूरे विश्व में लोकतंत्र पूर्णतः लूटतंत्र में परिवर्तित हो चुका है। अब लोकतंत्र की परिभाषा लोक से लोक के लिए, लोक द्वारा, बदलकर लूट से, लूट के लिए, लूटेरों द्वारा हो चुकी है। राजाओं के शासन में भी जनता का इतना घोर शोषण नहीं किया जाता होगा, जितना लोकतंत्र के नाम पर चुनकर, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा होने का ढोंग करने वाले ये नंगे, भूखे की फौज, जनता से हर कदम सड़कों पर चलने का कर वसूलने से लेकर, आटा, दाल, चावल, स्वास्थ्य, शिक्षा तक हर कदम लुटेरों का जमावाड़ा है। यही कारण है कि दुनिया में भारत में पेट्रोल पर 400 प्रश तक वसूली की जाती है, इस वसूले गये करों की राशि से उस मजदूर के बेटे को प्रधानमंत्री जैसा पद मिलते ही रुपए 40 लाख करोड़ से ज्यादा की विदेश यात्रा करने चला जाता है, तो प्रदेश का मुख्यमंत्री जो किसान का बेटा होने का ढोंग करने वाला पाखंडी एक तरफ देश में सबसे ज्यादा उत्पादन करने का कृषि कर्मणा पुरस्कार खरीद कर जनधन के अरबों रुपए प्रसार माध्यमों को सच न छापने और अपनी प्रशंसा में बर्बाद करता है। दूसरी तरफ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि से किसानों की फसलों की बर्बादी के लिये केंद्र से धन लाकर हड़प जाता है। बदले में किसानों को उनकी लागत का भी 10 प्रश क्षति पूर्ति नहीं होती, इतना होने पर भी कृषक अपनी जमीन पर खेती करने की जोखिम उठाता है, इस पर भी इन सत्ताधीशों को चैन नहीं पड़ती और अपने काले धन का उपयोग उद्योगों में करने के लिये उसकी जमीन हड़प ली जाती है और उसे औना-पौना मुआवजे देकर दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अपनी मोटी कमाई और मोटे कमीशन के लिये पूंजीपतियों, उद्योगपतियों की कमाई और लूट के लिये कानून तक बना दिये जाते हैं। गरीबों, छोटे व्यापारियों, घरेलु, उद्योगों को कानून के मकड़जाल में उलझाकर उन्हें बेरोजगार बना दिया जाता है, फिर अपने ही उद्योगों में उनके शोषण के लिये 10-12 घंटे काम करवाने के बाद भी न्यूनतम मजदूरी जिससे उसका व उसके परिवार को दो वक्त की रोटी मिल सके, वेतन भी नहीं दिया जाता, सरकार में बैठे धूर्त सत्ताधीश, सत्ता, कानून को अपनी दलाली, के लिये सब बलाये ताक रख देती है। भाजपाई बनाम मुखेरे जनपार्टी में अपनी जमीन मजबूत करने और भू-माफिया, उद्योगपतियों को उनके वैध-अवैध कारोबार करने के लिए भू-कानूनों में भारी फेरबदल कर दिये आने वाले समय खेती के लिये जमीन बचे न बचे परंतु ये मुखेरे किसानों की जमीन, चरनोई, नजूल, नदी, तालाबों, सार्वजनिक उपयोग की भूमि को आसानी से नामांतरण या अपने नाम करवा देंगे। ऐतिहासिक महल के किलों, सरकारी लो.नि.वि. के पुराने विश्राम गृहों, सरकारी चिकित्सालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, सब निजी क्षेत्र में सौंप रहे हैं। बेशक बदले में मोटा कमीशन हजम कर रहे हैं। सत्ताधीश है। इन्हें इनकी औकात मालूम है कि 5 वर्ष के बाद इनकी औकात क्या होगी, इसलिये जब तक सत्ता में है। बाप की जागीर समझ लूटो और लुटाओ, कल इन भेड़ियों की मृत देह को अग्नि भी मिले न मिले, क्योंकि आज ये जिन पूंजीपति सपोलों को पाल रहे हैं। उनके इशारों पर नाच रहे हैं। उनके लिये लाखों-करोड़ों को बेरोजगार कर रहे है। कल के दिन वे ही सपोले, इन्हें डसेंगे। सत्ता से बाहर करने, विरोधियों को तन, मन,धन से सहयोग कर खदेड़ने में भी नहीं हिचकिचा पायेंगे।

जुकरबुर्ग आतंकियों का संरक्षक- तत्काल बंद हो फेसबुक

पेज 1 का शेष

यही हाल इंटरनेट के सबसे खतरनाक मंच फेसबुक का है। फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग ने खुले में स्वीकार किया कि वो मुसलमान है और मुसलमान का खुला समर्थन करते हैं। सवाल मुस्लिमों के समर्थन तक सीमित होता तो कोई परेशानी नहीं थी, परंतु वो शूकर जुकरबर्ग ही यथार्थ में आईएस, आईएसआईएस का सबसे ठोस मंच सिद्ध हो रहा है। इन दोनों संगठनों ने दुनिया में हिंसा, हत्याओं का तांडव मचा रखा है। पुरी दुनिया से ये संगठन मुस्लिम व अन्य युवाओं को भर्ती कर रहे है। अपनी इसी फेसबुक खातों से युवाओं को आकर्षित करने, गैर मुस्लिम लड़कियों को मुस्लिमों, जेहादी संगठनों, सिमी के सदस्यों को जानकारी उपलब्ध करवाने, उनको फंसाने का कार्य भी इसी फेसबुक से संपन्न किया जा रहा है, जिसकी जानकारियां हर दिन समाचार पत्रों में छाई रहती है। दंगे भड़काने, दंगाईयों को इकट्ठा करने के काम को न केवल भारत में वरन फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे राष्ट्रों में भी इसी फेसबुक के मंच को ही माध्यम बनाया गया, परंतु वर्तमान में भी हमारे देश की केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, उनका गृह विभाग, क्षेत्रीय पुलिस सबकुछ जानने के बाद भी न केवल जागने, देश की जनता को जगाने, इसके मंच पर कड़ी निगरानी, चौकसी करने की तो दूर उल्टे ही इसका उपयोग कर रही है। जबकि फेसबुक के माध्यम से उच्च स्तरीय सेक्स रैकेट, ड्रग रेकेट्स व अन्य अनेकों तरह के अवैध कुकृत्यों के कार्यों में भी उपयोग किये जा रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों के गृह मंत्रालय को चाहिए यह था कि वो इस फेसबुक की साइट की 24 घंटे हर नगर में हर पन्ने की निगरानी कर सभी प्रकार के अवैध कृत्यों यथा आतंकवादियों, सिमी, आईएस, आईएसआईएस के मुस्लिम युवाओं को भ्रमित करने जैसे राष्ट्रद्रोह के कृत्यों से लेकर सभी अवैध कृत्य यथा सेक्स, ड्रग, अवैध वसूली के रेकेट्स पर नजर रखने के साथ ऐसे अपराधी को तत्काल गिरफ्तार करती। फेसबुक से आसानी से चालाक और शिक्षित अपराधियों को तत्काल पकड़ न केवल आईटी एक्ट 2000 वरन् आईपीसी की अन्य धाराओं का उपयोग कर बड़ी सजा देती तो फेसबुक अपराधियों का मंच नहीं बनता परंतु वह सब जानकर भी इसलिए आंखे भींचे बैठी है कि स्वयं मोदी ने भी 25 लाख डॉलर से ज्यादा खर्च करके, अपने भाड़े के उपयोग कर्ताओं को बैठाकर देश की जनता को भ्रमित कर ही तो चुनाव जीता है। झूठे अच्छे दिन के वादे किए है। अपने विरूद्ध चल रही हर उपयोगकर्ता के खातों को या तो रोक दिया गया या उसकी यथार्थ की प्रस्तुती को न तो स्वयं के पेज पर चलने दिया, न दूसरे को भेज दिया गया, ऐसी हर प्रस्तुति को रोकने का भी मोदी ने चुनाव के समय मोटा धन बांटा, ये मोदी का ही धन था, जिससे जुकरबर्ग के हौंसले इतने बुलंद हुए कि वह भारत के 900 नगरीय कस्बों से लेकर 6 लाख से ज्यादा गांवों में भी मुफ्त इंटरनेट सेवायें देने के लिए उतावला हुआ जा रहा है। बदले में 125 करोड़ जनता का डाटा एकत्रित करके बड़ी व्यवसायिक कं. को बैचे। उनका माल फेसबुक के माध्यम से बिकवायेगा, उससे वह सैकड़ों गुना कमा लेगा, कमा रहा है। जिसने अपनी बेटी के जन्म होने पर ही 390 करोड़ डॉलर दान किए तो उसने कितना धन कमाया इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी कमाई कितनी होगी। जबकि मियां जुकरबर्ग विश्वभर में आतंकी घटनाओं, आतंकी संगठनों को अपने फेसबुक से फैलाने को जिम्मेदार है। रिलायंस जैसी कंपनी ने मुफ्त आधारभूत इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक चलाने की सेवायें अपने उपभोक्ताओं को दे रहे ह, तो क्यों ताकि वो देश का सबसे बड़े जालसाज और डकैत अंबानी बंधु अपना माल बैच सके। उपभोक्ताओं की अधिकतम जानकारियों को एकत्रित कर पूरी दुनिया की दवा कं., कास्मेटिक कं., राजनीतिक पार्टियों, उपभोक्ता सामान उत्पादक कं., ऑनलाइन फिल्पकार्ट जैसी सैकड़ों कं. से लेकर यौनाचार करवाने वाले, नशे का व्यापार करने वाले, ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोहों को न केवल आधारभूत जानकारियों से लेकर बैंक खातों, आधार कार्ड की जानकारियां, बैंकों के एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तक जानकारियां तक बैचकर हजारों करोड़ जनता से लूट सकें, लूट रहे हैं। पिछले 15 वर्षों से मोबाइल सेवा के बदले 30 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को ये गिद्धों का गिरोह अंबानी बंधु और उसकी कं., हमारी सरकार को मोदी और उसका गिरोह जिन वादों और दिवा स्वप्न दिखाकर और जालसाज आईएएस अधिकारियों को खरीदकर सत्ता हथियाई है। उसके सभी मंत्रालयों जिसमें संचार मंत्रालय जहां अभी भी हजारों करोड़ की जालसाजियां और भ्रष्टाचार चल रहा है। मंत्री बदले है। धूर्त मक्कार इंडियन एव्यूसिंग सर्विसेज के महाजालसाज अधिकारियों ने जनता को डिजिटल टीवी के माध्यम से 30 करोड़ उपभोक्ताओं को लगभग रुपए 2 लाख करोड़ से लुटवाकर सेटअप बॉक्स लगवाने को मजबूर कर दिया। अब हर सेवा कार्य, सरकारी कार्यों, परीक्षा फार्म भरने से लेकर, सब्जी खरीदी आदि तक को ऑनलाइन करने पर तुली है। यहां तक कि गरीबों को राशन भी ऑनलाइन दुकान से खरीदना पड़ रहा है। जबकि इंटरनेट सेवाओं की गति के साथ शासकीय विभाग के सर्वर, साइटें ही या तो बैठ जाती है या अत्याधिक मंद गति से चलती है। जिससे सरकारी कर्मचारी अधिकारी स्वयं ही परेशान रहते हैं। दूसरी ओर

जिस गूगल की साइट, ईमेल आदि के साथ पूरा इंटरनेट दुनियाभर में अमेरिका से चलाया जाता है, अर्थात इंटरनेट पर किया जाने वाला ईमेल से लेकर सभी ऑनलाइन कार्य पहले अमेरिकी सर्वर में पहुंचते हैं। अर्थात सारा डाटा अमेरिका के पास पहुंचता है। कैसी शासकीय और निजी गोपनीयता। हमारे सरकारी अधिकारी भले ही जनता या सूचना के अधिकार में जानकारी देने के नाम पर गोपनीयता का तांडव करें पर न केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह, रक्षा आदि महत्वपूर्ण कार्यालयों की सभी जानकारियां जो इंटरनेट के माध्यम से विनिमय की जाती है। पहले अमेरिकी सर्वर में ही पहुंचती है। बड़ी-बड़ी सुरक्षा की बातें करने वाला मोदी अभी तक इस संचार व्यवस्था में भारत का स्वतंत्र इंटरनेट नहीं ला पाया। फिर भारत में बढ़ रहे आतंकवाद, दंगे, हिंसा आदि को रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि तत्काल फेसबुक पूरे भारत में प्रतिबंधित कर दे, 25-50 दिन हल्ला मचेगा, आसानी से भारत में गुणोत्तर वृद्धि कर आतंकवाद के फैलाव पर भी रोक लग जावेगी। फेसबुक के बंद होने से न तो लोग भूखे मर जायंगे, न ही बेरोजगारी बढ़ जायेगी बेशक अवैध कार्यों और व्यवसायों के गिरोह जरूर बेरोजगार हो जाएंगे, यह तो जनता और सरकार दोनों ही चाहते हैं।

जन-गण-मन गुलामी का गीत अधिनायक आधीनता का परिचायक

पेज 1 का शेष

यथार्थ में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन और अमेरिका की ही संस्था है। कभी अमेरिका की गुलाम राष्ट्र हुआ करता था, अपने साम्राज्यवादी विचारों को स्थापित करने विश्व के अन्य राष्ट्रों को अपने इशारों पर नचानें, वहां के प्राकृतिक और मानवीय स्त्रोतों का अपने लाभ के लिए दोहन करने का कार्य करती है। विभिन्न नियमों और कानूनों के सहारे, ताकि उन नियमों और कानूनों की आड़ में अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कं. दवायें, खाद्य वस्तुयें, विद्युत, विद्युताग्रसंचार, युद्ध सामग्री,वाहन, कृषि आदि का व्यापार पूरी दुनिया में कर सकें और इसके बहाने तरीके से शोषण कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ यथार्थ में संयुक्त शैतान संघ है, जिसका ये दुनिया के शैतान, राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन व उनके अन्य साथी फ्रांस रूस और जर्मनी अपने तरीके से उपयोग करते हैं।

ये वही राष्ट्र है जिन्होंने अपनी शैतानियत और हथियार बैचने के लिए पाकिस्तान को आतंकियों का उत्पादन उद्योग बनाया, अब जब उसके उत्पादन इस्लामिक स्टेट ने अपना सिर उठाना शुरू किया तो अब अपने जंग खा रहे लड़ाकू विमानों, सैन्य जलपोतों, पनडुब्बियों आदि से सीरिया तुर्की पर बम बरसा रहे है। पाकिस्तान को भिखारी राष्ट्र बना वहां के आम नागरिकों का जीवन बर्बाद कर आतंक की स्थाई आग में झोंक दिया। अब यदि ब्रिटेन, अमेरिका व अन्य का संयुक्त शैतान संघ जिसकी छोटी सी बानगी का वर्णन का ऊपर न्युनतम शब्दावली में कर दिया है। भारत के गुलामी के इस गीत का दुनिया का श्रेष्ठतम राष्ट्रगीत घोषित करके यथार्थ में सिद्ध किया जा रहा है कि तुम अपने आप में कितने भी महान बन जाओ भारत के जन और जनों का राष्ट्र नायक गण मोदी दुनिया के हर उस देश की जनता में जहां मोदी ने जनता का धन विदेशों में बांटकर अपने लिए तालियां भले ही पिटवा ली हो, पर तुम्हारे राष्ट्रगीत में हम अब भी भाग्य विधाता है। तुम्हारे देश के जन गण उसके मन के साथ ही सभी प्रदेशो, विश्व की महान पर्वत श्रृंखला हिमालय से लेकर स्वर्ग से उतारी पावन गंगा तक हमे नमन कर आशीष मांगती है और हमारी जय गाथा सुनाती है और बार-बार हमारी जयकारे लगाकर 125 करोड़ गुलामों तुम्हारे गुलाम होने का अस्तिल बोध कराती है।

बहुनारी गमन करने वाले अय्याश नेहरू, गांधी व अन्य सभी कांग्रेसी व अन्य नेता जानते थे। इस घोर गुलामी के गीत का यथार्थ। जवाहर लाल नेहरू अपनी राजनीति और अय्याशी में मस्त रहते थे, इसलिए अपनी पुत्री इंदिरा को उसने स्व. रविंद्र नाथ टैगोर के शांति निकेतन में पढ़ने बंगाल भेजा था। स्व. इंदिरा बिना मां की बेटी और अय्याश बाप की उच्श्रृंखलता की बेटी थी। इस उच्च श्रृंखला से परेशान होकर जब रविन्द्र नाथ ने जवाहर लाल को बताया कि कैसे उसकी बेटी ने पूरे शांति निकेतन को बर्बाद कर दिया हैं तो जवाहर लाल ने देश का प्रधानमंत्री घोषित होते ही रविन्द्र नाथ ठाकुर के इस अंग्रेजों के पसंदीदा गुलामी के गीत को राष्ट्र गीत कर रविन्द्र नाथ ठाकुर को राष्ट्र कवि का दर्जा दिलवाकर मुंह पर सदा के लिए ताले लगाकर बंद करवा दिया था।

मनुष्य के पृथ्वी पर समृद्ध, मस्तिष्कीय क्षमताओं युक्त प्राणी बनाया है जिसमें मन में भावनायें औ परवर्तित करने की क्षमता प्रकृति जन्य है। अब जैसी मन मस्तिष्क में भावनायें आयेगी, प्रार्थना करेगा, स्वाभाविक है उसे वैसा ही प्राप्त होगा, अब यदि भारत की आबादी 125 करोड़ में से 40 करोड़ युवा होती पीढ़ी अपने विद्यालयों, महाविद्यालयों से लेकर छवि गृहों तक में यदि ये गुलामी का गीत गायेगी, गुलामी की कामना करेगी, तो गुलामी ही आयेगी, चारों तरफ से कागजों के अमेरिकी डॉलर और युरो विश्व बैंक, एशियन विकास व्यापारी संघ के माध्यम से, बहुराष्ट्रीय कं. के माध्यम से राष्ट्र के मानव निर्मित और प्राकृतिक स्त्रोंतों को। पुनः कब्जे में लेकर, जनता को गुलाम बन रहा है।

मंडलों कों बंद कर विद्युत कं. बना, जनता से फर्जी बिलों और कीमतें बढ़ाकर लूट

विद्युत वितरण कं. को रुपए 4.43 लाख करोड़ के जन-धन से पैकेज क्यों?

समय माया वर्षों से लिख रहा है, हजारों करोड़ हजम करते हैं, बर्बाद कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था, ग्रिड सेप्रेरशन, ग्रामीण ज्योति योजना और नई लाइनों के नाम के साथ ही, दोगुने से लेकर हजार गुना तक मन माने बिल, रखरखाव के फर्जी बिलों से पावर जनरेटिंग कं. ने सारणी और सिंग्गजी की इकाईयों के निर्माण में भी स्तरहीन निर्माण करवाकर अरबों रुपए के घोटाले किये

विश्व व्यापार संगठन के गिद्धों ने दुनिया के विकसित, विकासशील, अर्द्ध विकसित और विकास की राह पर अग्रसर देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लूटने, बर्बाद करने, उनको विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के माध्यम से विकास के लिए कर्ज बांटकर, वहां की अर्थव्यवस्था में सेंध लगाकर वहां के सत्ताधीश प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को ऋण लेकर घी पिलाकर भ्रष्ट बनाया, वरन उनके राष्ट्रों के प्राकृतिक, मानव निर्मित अच्छे उत्पादक संसाधनों को चंगुल में फंसाने के लिए सरकारी निगम, मंडलों, उपक्रमों से बाहर निकलकर उनकी निजीकरण की योजना के अंतर्गत उन्हें व्यावसायिक कं. में परिवर्तित किया गया ताकि उनकी अंशपूंजी खरीदकर कब्जे किए जा सकें। इसके अंतगर्त सन् 2000 के बाद से ही पूरे राष्ट्र के राज्यों के विद्युत मंडलों को पहले वितरण, उत्पादन और विद्युत प्रेषण कं. में परिवर्तित कर, देश की सबसे धूर्त, महाभ्रष्ट निकम्मी प्रशासनिक लॉबी के शूकरों को उन कं. का प्रबंध संचालक बनाकर उन कं. को अपनी हजारों करोड़ की लूट का तांडव मचवाकर घाटे में लाने के लिए युद्ध छोड़ दिया गया। इन जालसाजों की लूट से उत्पन्न कुकर्मों की वैधानिकता प्रदत्त करने, जनता को भ्रमित करने, सरकार द्वारा लुटेरों को संरक्षण देने मंत्रियों-संत्रियों द्वारा मोटा कमीशन हजम करने, जनता के इस लूट के तांडव से उत्पन्न आक्रोश को दबाने अपने खास सिपहसालारों, इन धूर्त, मक्कार इंडियन एव्यूसिंग अधिकारियों द्वारा एक तरफ उन मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों की लूट और जालसाजियों को दबाये रखने के लिए तो दूसरी तरफ उन्हें उपकृत कर अपने एहसानों का बदला चुकाने के एक विद्युत या ऊर्जा नियामक का गठन कर दिया, उनमें पुराने सबसे धूर्त, मक्कारों, जिनका इतिहास बहुत ही घिनौना रहा है, जैसे राकेश साहनी की वर्षों तक इस नियामक आयोग का अध्यक्ष बना के रखा गया।

उस आयोग में बैठकर इस गिद्ध ने कभी जनता की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया, उल्टे ही सभी मंडल को खंडित कर बनाई गई कं. के प्रबंध संचालकों की लूट, जालसाजियों, हजारों करोड़ हर वर्ष हजम कर एक तरफ पूरी मंडल की विद्युत वितरण व्यवस्था चौपट की, अनावश्यक रूप में मोटा कमीशन हजम करने, उपभोक्ताओं से चौगुने से लेकर सौ गुने तक बिल करने मेकेनिकल मीटरों का हटवाकर हर वर्ष दो वर्ष में इलेक्ट्रानिक मीटर बदलवाये, उनकी खरीदी में सैकड़ों करोड़ का उनको बदलवाने में दिये गये ठेकों में भी सैकड़ों करोड़ का पुराने मजबूत खंभे हटाकर घटिया स्तर के खंभे, लाइनें और केबल बिछाई जाती है। ट्रांसफामर्स की खरीदी, सुधार, रखरखाव, उप विद्युत, निम्न दाब, उच्च दाब वाले सेवा व वितरण केंद्रों के रखरखाव वहां के ठेका श्रमिकों से न्यूनतम मजदूरी से कम पर अप्रशिक्षित कर्मियों की पदस्थापनायें, इलेक्ट्रानिक मीटरों की मौसम, मीटरों के गर्म होने पर, भार बढ़ाने पर मीटर में विद्युत उपभोग के भी ज्यादा जो चौगुने से लेकर 100 गुना तक कुछ भी हो सकती है, को उपभोक्ताओं पर बिल लादकर, गुंडों व लठैतों से वसूली करवाने, पुलिस में एफआईआर लिखवाकर न्यायालयों में घसीट कर प्रताड़ित करने, कारावास में भेजने, सजा दिलवाने, रखरखाव के नाम पर इंदौर जैसे बीच शहर में नियमित कटौती करने का तांडव करके भी, जबकि गांवों में सिंचाई के विद्युत की भारी आवश्यकता होने पर कहीं 6 से 12 तो कहीं 18 घंटे की आपूर्ति की जा रही है, जबकि वो मुखेरा जन पार्टी उर्फ भाजपा का मु.मं. शिवराज न केवल प्रदेश के वरन् देश और दुनिया के हर मंच पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति और पारदर्शी प्रशासन देने की ताल ठोंकता फिरता है, जबकि रुपए 10000 करोड़ से ज्यादा हजम किये जाते हैं। सारणी के ताप विद्युत केन्द्रों का न तो समयानुसार आवश्यक रखरखाव नहीं किया, उचित मात्रा और गुणवत्ता का कोयला आपूर्ति नहीं की गई, जानबूझकर ताप विद्युत के उत्पादन केन्द्रों में इसी प्रकार इन हरामखोर गिद्धों ने हर कदम पर लूटपाट की और भ्रष्टाचार का तांडव किया, यहां तक कि प्लांट की नियमित आवश्यक रखरखाव सामग्री मे भारी कमीशनखोरी घटिया स्तर की माल घटिया स्तर की कं. से खरीदा, अधिकांश कार्य ठेका कर्मचारियों अधिकारियों से करवाया जाने के कारण, अच्छे खासे चलते हुए प्लांटों को पुराना होने की आड़ में रुपए 5000 करोड़ से ज्यादा की मशीनरी को मात्र रुपए 74 करोड़ में सौदा कर दिया गया ताकि टाटा, रिलायंस, अडानी, गडकरी के पावर प्लांटों से बिजली खरीदी कं. मोटे कमीशन पर मार्ग प्रशस्त किया जा सके। दूसरी ओर जैसा कि मु.मं. शिवराज मिट्ठू मियां दावा करता है कि जब उसने पद संभाला था मात्र 4500 मेवा बिजली बनती थी प्रदेश में और अब 15500 मेवा बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो यक्ष प्रश्न ये है कि भ्रष्टों और राक्षसों के पूजनीय महाराक्षस रुपए 9000 करोड़ की बिजली खरीदी क्यों की गई, दूसरा फिर 24 घंटे आपूर्ति करने की ताल ठोंकने वाले चौहान जब इंदौर जैसे शहर में एमआईजी, एलआईजी अंबेडरकर नगर में ही हर दिन 24 घंटे बिजली नहीं रहती, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मात्र 6-12-18 घंटे ही आपूर्ति की जाती है तो बिजली सस्ती दरों पर बाहर क्यों बेची जा रही है। तीसरा सभी विद्युत वितरण कंपनी ने 4 से 10 गुना तक तेज मीटर लगाकर 4 से गुना तक ज्यादा राशि वसूल करने के बाद भी हर विद्युत वितरण 5 से लेकर 20000 करोड़ के घाटे में क्यों चल रही है। चौथा परमाणु बिजली घरों से सभी विकसित राष्ट्र यथा अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे राष्ट्र परेशान है। फिर भी मंडला जिले में परमाणु बिजली घर की स्थापना फ्रांस, रूस के कबाड़ा बन चुकी मशीनों को पुर्नस्थापित कर उत्पादन की तैयारी क्यों की जा रही है। पांचवां हर वर्ष ये विद्युत वितरण कं. हजारों करोड़ के घाटे दिखाकर अपने चिट्ठों में वर्ष में दो से तीन बार विद्युत दरों में भ्रष्ट जालसाजों के अड्डों नियामक आयोग से कीमतें क्यों बढ़वाकर वसूली करती है। छठवां सागर, उज्जैन, ग्वालियर में आपने निजी कं. के हाथों में जो व्यवस्था सौंपी थीं। उन सबने हर कदम जनता को और कर्मचारियों को लूटा मनमाने बिल थोपकर वसूली की साथ ही पूरी वितरण व्यवस्था चौपट कर दी। इसके बाद भी आपका दिल नहीं भरा, इसके बाद भी आपका निजीकरण करने का इरादा नहीं खत्म हुआ। सातवां आप अपनी मोटी कमाई और कमीशन के लिए हर विद्युत कंपनी में ऐसे ही इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों को बैठाते हैं, जो घोर भ्रष्ट तो होते ही है साथ ही उन्हें विद्युत की एबीसीडी में वॉट, वोल्टेज, एचटीएल की परिभाषा भी नहीं आती। आठवां ग्रामीण विद्युतीकरण नई लाइनें बिछाने सब स्टेशन बनाने के लिये हर वर्ष आपको हजारों करोड़ केन्द्र से और अपने बजट में भी हजारों करोड़ की व्यवस्थाएं की, आखिर कहां गया वह सारा पैसा, क्योंकि प्रदेश के हजारों गांवों में विद्युत नहीं है दूरदराज के क्षेत्रों में।

नौवों,ग्रिड सेपरेशन जिसका उद्देश्य था कि छोटे-छोटे ग्रिडस को अलग-अलग कर आसानी से अपने भाई, भतीजों, रिश्तेदारों, मंत्रियों,उद्योगपतियों, अधिकारियों को, उस क्षेत्र की जनता को लूटने के लिए सौंपा जा सके, जिसमें रुपए 950 करोड़ खर्च किए गए, क्या काम हुआ उसमें, सारा पैसा हजम कर लिया गया, दसवां रुपए 1250 करोड़ की दीनदयाल योजना में खर्च किया गया पैसा कहां गया क्या कार्य हुआ उसमें, जनता का क्या लाभ हुआ।

ग्यारवां- विद्युत वितरण कं. में बिल बनाने का ठेका प्रति बिल की कीमत पर देने की अपेक्षा,बिलों की राशि पर कमीशन देने से क्यों तयकर किया गया, ताकि बिल बनाने वाला अधिकतम राशि के झूठे सच्चे बिल बनाकर अधिकतम कमीशन हड़प कर आपकी कं. जनता को लूट सके।

बारहवां- है भ्रष्टों के संरक्षक शिवराज, मंडल को भंग कर कंपनी बनाने का उद्देश्य ही था हर कदम-कदम लूट का तांडव करवाया जाये, इसलिए लाइन मेन, मीटर रीडर्स, वस्तुओं से लेकर उपयंत्री तक जो वर्षों से जहां जमे हैं। वे अभी भी वहीं जमे रहकर बिजली चोरी करवाने, रीडिंग कम लिखने, बिल न देने और देने पर न्यूनतम का बिल देने का तांडव अभी भी कर रहे है। हजारों रुपए महीना डकार कं. को लाखों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके विरूद्ध क्या कार्यवाई की गई,ऐसे हजारों कर्मचारी हर जिले के विद्युत कं. के कार्यालयों में बेखौफ सेवायें दे रहे हैं।

तेरहवां- सभी ताप विद्युत केंद्रों में 25 से 40 प्रश कोयले की चोरी की जाकर बाहर बैच दिया जाता है, उसमें बैचने वाले के साथ उपयंत्री से लेकर प्रबंधक संचालक मंत्री राजेंद्र शुक्ल, सचिव और आपका भी हिस्सा होता हैं। जबकि आप बाहर ताप विद्युत केंद्रों में कोयले की कमी का वर्षों से रोना रोते आ रहे हैं। सिंगाजी का ताप विद्युत केन्द्र चोरी और जुगाड़ के कोयले से ही वर्षभर तक चलाया जाता रहा। अभी 1-2 माह पहले ही वे.को.लि. को समझौते पर हस्ताक्षर नियमित कोयले की आपूर्ति शुरू की गई।

14वां- जल विद्युत केंद्रों यथा इंदिरा सागर, औंकारेश्वर, सरदार सरोवर में प्रदेश की कृषि, वन व रहवासी क्षेत्र डूबे, इसके विद्युत उत्पादन में 49 प्रश आपका प्राथमिक और 51 प्रश विद्युत उत्पादन पर प्रथम अधिकार क्रय करने का है। इंदिरा सागर और औंकारेश्वर में, 25 प्रश सरदार सरोवर में है। इसका उपयोग करने की अपेक्षा आम ताप विद्युत 3 से रु. 4.50 और पवन विद्युत रुपए 5 से 6 प्रति युनिट में और अब सौर विद्युत खरीदने के महंगे सौदे कर क्यों जनता का धन बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि महंगी खरीद से अंदर, और सस्ती बैचने में ऊपर से कमीशन हजम करें, यह हाल देश के हर राज्य में विद्युत कं. वितरण के घाटे का है, और इसी घाटे की या लूट की भरपाई के लिए, मोदी सरकार ने रुपए 4.43 लाख करोड़ जो जनता से लूट की भरपाई के लिए मोदी सरकार ने रुपए 443 लाख करोड़ को जनता से लूटे और उसमें से दिये जा रहे है, ताकि मोटा कमीशन मिल सके, वित्त सचिव मप्र ने इस विद्युत वितरण कं. के घाटे की भरपाई के लिए घोषित धन में से कुछ न मिलना बताया है। अर्थात कं. को बनाने का उद्देश्य चारों तरफ से हर कदम धन लूटना था, जो पूर्णतः सफल रहा, जहां जनता का सवाल है तो वह लूटने के लिए ही पैदा हुई है।

सारणी की पुरानी 1 से 5 तक की इकाइयों को तोड़कर कबाड़ा मैं बैचने की पहली बोली रुपए 105 करोड़ की आई थी, पर अपने मोटे कमीशन के लिए हरामखोरों ने उसे रद्द कर पुनः निविदा बुलाई और दूसरी निविदा में रुपए 77.75 करोड़ में बैचकर रुपए 27.25 करोड़ के वारे-न्यारे किये जाकर शासन को हानि पहुंचाई, जब शिकायत की गई तो मंत्रालय से लेकर प्र.सं. तक सब चुप। उसी प्रकार सिंगाजी और सारणी की 10-11 इकाई के निर्माण में भी स्टील अथॉरिटी का फ्रेश स्टील लगाने की शर्त के बाद भी बाजार से बने लोहे का निर्माण कार्यों में प्रयोग किया गया, जिसे मंत्री से लेकर प्र.सं., मु. अभियंता तक ने मोटा पैसा हजमकर शिकायत को दबा दिया गया, सिंगाजी व सारणी की ताप विद्युत की नई ईकाइयों में डीपीआर के अनुसार काम न किया जाकर भारी फेरबदल कर सैकड़ों करोड़ रुपए हजम किया गया। जबकि रुपए 10500 करोड़ की इस परियोजना में हजारों करोड़ का कमीशन डकारने के लिए। परिणाम यह हुआ कि इकाइयों के प्रारंभ होते ही वे ध्वस्त हो गई।

मप्र पश्चिम विद्युत वितरण कं. लि. में बिलों को बनाने का ठेका जालसाजी से चुनाव जीतकर लोक सभा में पहुंची सांसद सुमित्रा महाजन के बेटों को दिया गया है। जिसमें प्रति बिल तैयार करने की दरों का भुगतान नहीं किया जाता, वरन् हर बिल की कुल राशि का एक निश्चित प्रतिशत भुगतान किया जाता है। बदले में वहां बैठे हर भ्रष्ट और जालसाज कर्मचारी को एक वेतन पूरा अधिक का भुगतान किया जाता है, इसको वहां बैठा हर जालसाज धूर्त बाबू से लेकर सहा. यंत्री तक सारी जालसाजीयां पकड़े जाने के बाद भी बिल की राशि कम करने को तैयार नहीं होते क्योंकि उन हरामखोर गिद्धों को उपभोक्ता से येन-केन वसूली करने के फर्जी अनाप-शनाप बिल बनाकर जनता को लूटने का मेहनताना मिलता है। इस संबंध में एक छोटा सा उदाहरण इनकी जालसाजी का देखिये- उपभोक्ता प्रवीण कुमार का एक मकान 30 ×10 के प्लाट पर है। जिसमें दो कमरे 10×10 के नीचे, 20×10 के प्रथम तल पर और तृतीय तल 15×10 के कमरा है। अधिकांश समय ये खाली रहे, बीच-बीच में किरायेदार रहे, जिनके पास टीवी, कूलर तक नहीं था। 18 वाट के 2 सीएफएल नीचे, 20 वाट की सीएफएल और जब किरायेदार रहे तो 1-1 पंखे का उपयोग किया गया, परंतु ये शूकरों की फौज लगातार 6 माह तक औसतन 100-100 यूनिट का बिल भेजती रही और किरायेदारों से बिल जमा करवाया जाता रहा। परंतु नवम्बर व दिसम्बर 15 में किरायेदारों के न होने के कारण बिल जमा करने आया जो रुपए 4480 का था तो बिल में पाया कि पिछले माह से 584 यूनिट की खपत के बाद लगातार 100-100 यूनिट का औसत देने के बाद फिर अक्टूबर में 115 यूनिट, नव. में 99 और दिस. में इकट्ठा 399 यूनिट का बिल ठोक दिया गया है। जब परदेशीपुरा में बैठे सहा. यंत्री बिंदल से कहा गया और पहला आवेदन 20/01/2016 को दूसरा 500 यूनिट, न के समायोजन के लिए 27.01.2016 को दिया गया, परंतु वहां बैठे हरामखोर सहायक यंत्री बिंदल और बाबुओं ने मात्र रुपए 4436-1498 रुपए 3018 का बिल जमा करने को कहा, जब उससे कहा गया कि आपने 399 यूनिअ का ऊर्जा प्रभार ही रुपए 1992-76 उस पर नियत प्रभार रुपए 510/- विद्युत शुल्क रुपए 261 जो कुल रुपए 2463.76 तो जो जोड़ा है वह कम कीजिए जबकि आप को 500 यूनिट के समायोजन में रुपए 3000 लगभग कम होंगे। जिसकी शिकायत संभागीय यंत्री गजेन्द्र कुमार विजय नगर में भी की गई उनके कहने पर भी उसने वह रुपए 3000 लगभग कम नहीं किये, पहले तो वह इस बात के लिए तैरूार ही नहीं था कि बिल में कोई गल्ती है। जब कहां गया कि बिल ज्यादा हैं, तो समझाने लगा कि टुकड़ों में कर देते हैं।

पाठक उपभोक्ताओं को इन हरामखोर जालसाजों की इस चाल के बारे में प्रत्यक्ष उदाहरण इसलिए दिये गये हैं ताकि वो देख सकें कि अरबों रुपए हजम कर जो इलेक्ट्रानिक मीटर जो दोगुने से लेकर 10 गुने तक तेज मीटर रीडिंग बताते हैं। ये शूकर जालसाजों की फौज उपभोक्ताओं को लूटने इसके बाद भी पहले औसत, फिर इकट्ठा बिल देकर लूटती है। हर बिल भरने से पहले मीटर रीडिंग और बिल का बारिकी से अध्ययन कर ही बिल जमाकर करें, औसत बिलिंग ज्यादा बिलिंग, बिना मीटर रीडिंग बिलिंग पर तत्काल शिकायत करें, इसके विपरीत यदि पाठक संपन्न हैं तो पर्याप्त स्थान है। या निवास स्थल पर भी यदि 7-8 घंटे पर्याप्त धूप मिलती हैं तो सोलर विद्युत ऊर्जा उत्पादन की पट्टीकाओं का उपयोग करें व इन मक्कारों के चंगुल से मुक्ति पाये, विद्युत नियामक आयोग में भुखेरों की फौज बैठी हैं, इन्हें इनका विद्युत वितरण कं. सै पैसा मिलता है वो शूकरों की फौज लाख जन सुनवाई की नौटंकी करें, बिजली की कीमतें, अवश्य बढ़ायेंगे हीं।

जैसा कि इतिहास गवाह है। इन हराखोरों के खिलाफ बिलों में जालसाजी मिलने पर उपभोक्ता भी न्यायालय में धारा 120बी, 420 में प्रकरण नामजद लगायें ये उपभोक्ता को लूटने की नियत रखते हैं। उपभोक्ता को भी हक है कि भा.दंड संहिता, उपभोक्ता न्यायालयों में इन्हें खड़ा करें, क्योंकि ऊपर चाहे सांसद सुमित्रा महाजन हो, पं. वि.वि. लि. का वर्तमान सीएम आकाश त्रिपाठी, जिसने जालसाजियों से चुनाव जीतने में मदद की, सब जनता को नोंचने पर तुले हैं। न्यायालय का नाम सुनकर ही इन जालसाजों के दिमाग पर सिलवट आ जाती हैं। वैसे जिस बिल की चर्चा की गई है उस हरामखोर सहा. यंत्री बिंदल ने फर्शीवाली गली में 20 फर. 16 तक भी बिल दिया हैं। ताकि बाद में ये धूर्त सबको परेशान कर सकें।

साप्ताहिक समय माया

पहले सफाई की ठेकेदारी प्रथा समाप्त करो और अनु.जाति व जनजाति अधि.समाप्त करो

गंदगी फैला, ड्रेनेज चौक कर वसूली करना है, पूरा व्यवसाय

हर वार्ड में 100 से 150 कर्मचारी सफाई करते है, 20 से 30 प्रश बाकी की हाजिरी में पार्षद से सुपरवाइजर की हिस्सेदारी, क्या खाक सफाई होगी, जनता कुछ बोले तो उल्टे ही झूठी रिपोर्ट एट्रोसिटी अधि. में लिखवाते है

सफाई अभियान में उलझा कर मोदी यथार्थ में अपनी नाकामियों की, जनता के दिमाग से सफाई करना चाहता है। अपने उन वादों की सफाई करने में वह कामयाब भी रहा है, जिन अच्छे दिनों के वादे कर उसने और भाजपा ने वोटिगं मशीनों की जालसाजियों से सत्ता हथियाई थी, से पंचायतों तक

यथार्थ में पूरे भारत में नगर निगमों, पालिकाओं में सफाई न केवल वैध-अवैध तरीके से जनता को लूटने, परेशान करने और पंचों-सरपंचों से लेकर नगर-निगमों, पालिकाओं में पार्षदों, सुपरवाइजरों हाजिरी भरने वले ठेकेदारों से लेकर सचिवों, महापौरों,निगमायुक्तों तक को सफाई के नाम पर खर्च किए जा रहे कुल धन का 25 प्रश से 50 प्रश तक भ्रष्टाचार की बंदरबांट से ही हजम कर लिया जाता है, जिसमें 50 से 70 प्रश तक फर्जी सफाईकर्मियों की झूठी हाजिरी लगाकर, कचरा ढोने वाली गाड़ियों के 90 प्रश मरम्मत और रखरखाव के बिल लगाकर 25 से 50 प्रश डीजल, पेट्रोल की चोरी और झूठे बिलों, कचरा निपटान में, इंदौर में ही गाड़ियों में 2-5 क्विंटल के पत्थर रखकर कचरे का वजन बढ़ाकर ठेका कं. के साथ मिलकर तो पिछले 50 वर्षों से ज्यादा समय से भ्रष्टाचार कर सब ही निगम पालिक कर्मचारी, पार्षद, अधिकारी, महापौर तक हर वर्ष करोड़ों की कमाई करते हैं। सन् 2006 में भी प्रोजेक्ट उदय के नाम पर कचरा ढोने की, हाथ ठेला गाड़ियों, रिक्शों से लेकर जिसमें 8 सिंटेक्स की बाल्टीयां लगी थी, क्रेन-ट्राले, कचरा ढोने के लिए मझौले ट्रकों से लेकर बड़े टैंकर युक्त सवशन ट्रकों की खरीदी, कई गुना दामों पर की गई थीं, वह सामान मूसाखेड़ी के नर्मदा जल यंत्रालय में महीनों पड़ा रहा और धीरे-धीरे कर सारा सामान गायब होता चला गया, कई बार सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई जिसमें सूत्रों के अनुसार रुपए 200 करोड़ की सामग्री इंदौर आई थी। परंतु परियोजना क्रियान्वयन इकाई में बैठे धूर्त एसई प्रभात सांखला, का.यं. अशोक बघेल आदि ने नगर निगम इंदौर के बीच झुलाते हुए नहीं दी, न ही उस सामान का इंदौर की सड़कों पर सफाई के नाम पर प्रयोग होते मिला, यही प्रोजेक्ट उदय के नाम पर इंदौर के साथ उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, सागर में भी ऐसे ही सफाई के लिए अरबों रुपए की सामग्री पहुंचाई गई थी, परंतु सारी गाड़ियां मशीनें कहां गायब हो गई, किसी को भी पता नहीं जबकि सूत्रों के अनुसार कुछ पैसा जेएनआरयूएन व एडीबी का अरबों रुपए का सामान खरीदी का बिल्कुल भी उपयोग साफ-सफाई में मप्र के संभागीय स्तर के नगरों में कहां हुआ, जबकि उसके माध्यम से हर घर के द्वार से कचरा इकट्ठा करने की योजना थी। जिसकी घोषणायें बार-बार अवश्य हुई परंतु घर-घर से कचरा उठाने की योजना ठेकेदारी प्रथा और भ्रष्टाचार के चलते कभी अपना वास्तविक स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकी, साफ-सफाई और घरों से कचरा उठाने की योजना कभी भी जब तक पूर्ण रूप से कारगर नहीं हो सकती जब एक तरफ एससीएटी अधि. समाप्त नहीं हो जाता और दूसरा सफाई के हर मोहल्ले में चल रहे ठेकेदारों की ठेकेदारी व्यवस्था जो पूर्णतः अवैध वसूली और रहवासियों के घरों के स्नानागारों, शौचालयों की नालियों, टंकीयों को तोड़कर पत्थर भरकर पहले चौक किए जाते हैं। जब शिकायतें करो तो सफाईकर्मी आकर खुले में न्यूनतम छोटे क्षेत्रों में रुपए 500 की मांग करते हैं। तो वहीं जिस स्तर की कॉलोनी होती है रुपए 5000 से लेकर रुपए 20000 तक की मांग रखते हैं। यदि दूसरे से साफ-सफाई करवाने की व्यवस्था करवाने की रहवासी अगर कोशिश करता है तो घर की महिलाओं बच्चों को गंदी गालियां तो बकी ही जाती है। साथ में यदि किसी महिला ने भी उसका जवाब देने की कोशिश भी की तो सफाईकर्मी इकट्ठे होकर महिलाओं के साथ मारा-पीटी करने, अश्लील हरकतें तक करते हैं।यदि बात बढ़ी तो फिर आसानी से एट्रोसिटी के अंतर्गत झूठा जाति सूचक शब्दों की थानों में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। स्वाभाविक है थोड़ा भी समझदार, सभ्यों और संभ्रांतों की तो दूर, अपनी बेइज्जती, बदनामी, मारापीटी, पुलिस और न्यायालयों की मानसिक और शारीरिक, आर्थिक सामाजिक प्रताड़नाओं से बचने के लिए चुपचाप रुपए 500 से 10-20000 तक देने के लिए विवश हो जाता है, जब इसको सामने देखने, भुगतने के बाद जब अलग क्षेत्रों में जाकर मालूम किया तो ज्ञात हुआ कि पूरा वर्षों का जमा हुआ वसूली का जाल है, जिसमें सभी हिस्सेदार है। इसमें पार्षद भी हिस्सा डकारकर चुप रहना ही बेहतर समझता है, क्योंकि सामान्य वर्ग के हर व्यक्ति को चाहे वो पार्षद हो निगम कर्मचारी, अधिकारी से लेकर महापौरों, आयुक्तों तक को एससीएसटी अधि. में रिपोर्ट लिखवाकर उसे हर तरह से जलील किया जाता है। इसलिये सब कानून की बत्तमीजियों और वोटों की राजनीति के सामने बिना कुछ किये घरे भी सफाईकर्मियों से उलझने से अभिशप्तों की भांति जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं। ये हाल केवल इंदौर ही नहीं वरन् उज्जैन, भोपाल, जबलपुर से लेकर हर जिले का न केवल प्रदेश में वरन् पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और मुंबई से लेकर कोलकत्ता, इंफाल तक है। सामान्य वर्ग का हर कदम, हर दिन उसके अपने ही नेता दलित वोट बैंक की खातिर सरकारी पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों पर चलने से लेकर साफ-सफाई के नाम पर भारी वैधानिक तरीकों से अवैधानिक घोर शोषण में जुटे हैं।

भारत में सामान्य वर्ग ही सबसे ज्यादा पंचायतों, पालिकाओं, निगमों को, आयकर कस्टम एक्साइज, केंद्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर, राज्यों का विक्रय कर, वृत्तिकर, संपदा संपत्ति कर आदि सबसे ज्यादा चुकाता है। अब मोदी का 0.5 प्रश स्वच्छता कर भी सबसे ज्यादा वही चुकायेगा, इसके विपरीत हर प्रकार की शारीरिक मानसिक प्रताड़ना भी सफाई के नाम पर मुंह बंद करके भी वही झेलता है। आखिर इस समानता के संवैधानिक अधिकार वाले लोकतंत्र में सामान्य वर्ग का हर कदम हर प्रकार से शोषण क्यों और कब तक।

नौटंकीबाज पूंजीपतियों की कठपुतली मोदी ने जिस जालसाजी और चालबाजी से धूर्त आईएएस अधिकारियों को मोटे धन का लालच देकर सत्ता हथियाई और सत्ता मिलते ही लाखों करोड़ खर्च करके विदेश यात्राओं में चारों तरफ भाड़े के ताली पीटने वालों से तालियां ठुकवाकर खरीदी हुई वाहवाही लूटी। जिसका चारों तरफ पुरजोर घोर विरोध होने लगा, जनता को अच्छे दिन के वादे की कड़वी सच्चाई का बोध होने लगा तो देश की जनता के दिलों दिमाग से अपनी नाकारात्मक छवि पर झाड़ू लगाकर व बड़े-बड़े अधिकारियों, नेताओं, अभिनेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से जनता के साथ झाड़ू लगवाकर अपने आपको परमजनसेवी प्रधानमंत्री सिद्ध करने की कोशिश की गई, जब इससे भी दिल नहीं भरा तो स्वच्छता कर थोप दिया गया। इसके विपरीत यदि सफाई के यथार्थ खर्च का पुनरीक्षण किया जाये तो ज्ञात होता है, नगर परिषदों, पालिकाओं और निगमों की कुल आय का 25 से 40 प्रश बजट केवल सफाई के नाम पर खर्च होता है। उस कुल खर्च का 50 से 70 प्रश तक हजमकर लिया जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि किसी भी सफाई से संबंधित कर्मचारी अधिकारी को एक स्थान पर 6 माह से ज्यादा न टिकने दिया जाये, सफाईकर्मी जो 15-25 वर्षों से एक ही स्थान पर टिके हैं। स्वाभाविक है कि एससीएसटी एक्ट के तहत वसूली के लिये जानबूझकर गंदगी फैलायेंगे, शौचालय के टैंक फोड़ेंगे उनमें पत्थर, ईंटे, कपड़े भरेंगे। पाइप फोड़ेंगे, रहवासियों पर गंदगी फैलाने का आरोप लगाकर उनके चालान न्यायालय में पेश करवायेंगे, उनको स्वयं गालियां बकेंगे, सरे चौराहे उनका मजाक उड़ायेंगे और यदि सामान्य वर्ग का रहवासी जवाब देगा तो एससीएसटी एक्ट की धमकी देकर, उससे पैसे मांगेंगे, पैसे न मिलने पर गालियां बकेंगे, मारापीटी करेंगे और इकट्ठे होकर थाने में उस रहवासी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचेंगे, स्वाभाविक है इस गिरोह से आम आदमी के उलझने बस की बात नहीं, हालात ये है कि ऐसे सफाई ठेकेदारों, सफाई कर्मचारी लाख-लाख रुपए की गाड़ियों पर घूमते हैं। उनकी बसें चल रही हैं। जबकि आम नागरिक रुपए 50000 की गाड़ी खरीदने के लिए भी बैंकों की लाइन में खड़ा होकर ऋण की याचना कर रहा है। ये सफाईकर्मी, ठेकेदार हर दिन रुपए 2 से 5 हजार की कमाई इसी तरह ब्लेकमेल कर वसूल रहा है, क्योंकि नगर निगमों में हर पार्षद जो करोड़ों रुपए खर्च कर चुना गया है, वो कमाई करने आया है, न कि व्यवस्था सुधारने, वो जानता है कि 100 सफाईकर्मियों में से मात्र 25 ही काम सड़कों पर करेंगे, 75 की हाजिरी के पैसे में से उसको भी हिस्सा मिलेगा।

यह सब सफाईकर्मी महिलाओं ने ही बताया कि हम 120 सफाईकर्मी हैं। मात्र पूरे मोहल्ले में 20-25 कर्मी ही आती है। जो जवान खुबसूरत है, जिनके बड़े लोगों से संबंध है उनकी आधी वेतन उनके घर दरोगा ही पहुंचा देता है, वो अपनी सेवायें बड़े साहब लोगों के घर पर दे आती हैं। उन्हें कभी सड़क पर झाड़ू लगाते नहीं देखा है। यह बात पार्षदों, दरोगा, सुपरवाइजरों से लेकर निगमायुक्त और महापौर तक सब हर जिले, तहसील, महानगरों तक में सब जानते हैं। चूंकि मोटा कमीशन और भ्रष्टाचार का धन मिलता है, इसलिए सब चुप रहते हैं।

इस भ्रष्टाचार के पोषण और कमाई के कारण ही ठेकेदारों के पोला पोसा जाता है, अन्यथा ठेकेदारों को बाहर कर जब पालिकायें और निगम सफाईकर्मियों को वेतन बांटता है, तो अचानक हर वार्ड में जाकर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, सुपरवाइजर उनकी जांच के साथ वीडियो शूट क्यों नहीं करते, फिर एक ही अधिकारी, कर्मचारी, सफाईकर्मी एक ही वार्ड में 20-20 वर्ष कार्य क्यों करता है, उन्हें हर छह माह में बदला क्यों नहीं जाता, ताकि वे सफाई के अतिरिक्त रहवासियों से संबंध ही नहीं बना सकें, या नालियों, शौचालय की टंकियों की कहानी समझकर उसमें पत्थर, ईंटे, कपड़ा या कचरा भरकर चोककर वसूली कर सकें, या रहवासियों को इकट्ठे होकर, ब्लैकमेल कर चमका-धमका सके, बेहतर होगा कि हर मोहल्ले में सड़कों की तरह कैमरे भी लगवा दिये जायें किसने कब तक कितना काम किया, नियंत्रण कक्ष से देखकर ही भुगतान किया जाये। इससे 30 से 50 प्रश धन जो भ्रष्टाचार में बर्बाद किया जा रहा है वह भी रूकेगा और सफाई की समस्या भी अपने आप सुलझ जायेगी।

ये व्यवस्थायें केवल इंदौर ही नहीं वरन् पूरे प्रदेश और देश की है। सफाई के नाम पर ऐसी व्यवस्थाओं के चलते दस मोदी प्रधानमंत्री बनकर झाड़ू उठाकर सफाई का पाठ केवल फोटो खिंचवाने और जनता को बचाने के लिए नौटंकी कर सकते हैं। पर यथार्थ सफाई कभी नहीं करवा सकते।

पंचायतों से लेकर नगर निगमों तक सभी वसूलतें हैं स्वच्छता कर

मोदी की स्वच्छता कर की वसूली बढ़ा रही महंगाई

गंदगी के हथियार से होती है अरबों की वसूली, मोदी के पहले और बाद बा देश गंदा, स्वच्छता कर या मोदी का विदेश यात्रा कर साफ सफाई पर खर्च का 80 प्रश धन, भ्रष्टाचार में इसमें भ्रष्टाचार को ही रोक ले तो 50 प्रश सफाई व्यय बचेंगे

भारत का प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने जन-धन को अपने बाप की जागीर मान 40 से ज्यादा विदेश यात्रायें की। हर विदेश यात्रा में रुपए 1 लाख करोड़ का औसतन खर्च कर चुके हैं। बदले में खुले में बहुराष्ट्रीय कं. व अपने खास मित्रों को लूटने वाले पूंजीपति राक्षसों यथा अंबानी, अडानी, टाटा, आईटीसी, बिरला को खुले में कदम जनता का रक्त पीने के लिये छोड़ दिया है। चाहे वो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, मोबाइल सेवाओं से लेकर सड़कों पर चलने तक पर भारी वसूली की जा रही है। इन सब लूट के तांडवों को छुपाने, जनता को भ्रमित करने न केवल झाड़ू स्वयं लगाकर जनता से भी लगवाई वरन् स्वच्छता कर भी थोप दिया, ताकि जनता इसी में उलझी रहे, और महंगाई के बोझ में उलझकर अपने जीवन यापन की सोचे न कि प्र.मं.मोदी को कोसे। वैसे इस रक्तपिपास दानव मोदी और उसके सारे हरामखोर मु.मं. यथा शिवराज, मप्र, मु.मं. वसुंधरा राजे राज., मु.मं. रमन छग, मु.मं. महाराष्ट्र सबने प्रधानमंत्री मोदी की हां में हां करने प्रदेश की व देश की जनता को हर तरीके से हर कदम नोंचा और प्रताड़ित किया कभी आधार कार्ड, बैंक खातों के खुलवाने, बीमा योजना में जनता से सीधे भी धन नोंचा, फिर न केवल अनाजों, दालों, खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ाकर कर लगाकर, पानी से सस्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिक रहे पेट्रोल, डीजल, ईंधन गैस पर कस्टम व एक्साइज, सेस बढ़ाकर केंद्र ने तो राज्यों ने भी लगातार वेट व अन्य कर बढ़ाकर 4 से 5 गुना कीमतों पर अपनी हरामखोरी, विदेश यात्राओं के खर्चे को वसूलने जनता को लूटा।

जबकि देश के हर नगर, महानगरों से लेकर ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी होती है, कि उनकी क्षेत्रीय नगर निगम पालिकायें, परिषदें और पंचायतें साफ-सफाई के नाम जो संपत्तिकर, सफाई करों से वसूली से नगरों, शहरों, गांवों की रहवासी बस्तियों में साफ-सफाई का प्रबंध करें, और वर्षों से कर रही है। बेशक सफाई मे खर्च होने वाली 20 से 30 प्रश की यह राशि का 50 प्रश बंदरबांट जो पार्षदों से लेकर पंचों में बंटता है में ही खर्च हो जाता है। 100 का वेतन निकलता है 10 कर्मचारी मात्र सफाई करते है। 90 प्रश सफाईकर्मी केवल कागजों पर ही काम करते है। यदि यह स्थिति 50 से 80 प्रश भी पहुंच जाये तो साफ-सफाई बेहतर तरीके से होगी, पर यह लूटपाट और भ्रष्टाचार जिसमें सभी पंचों और पार्षदों से लेकर सरपंच, महापौर, सचिव से आयुक्तों तक बंट रहा हो,यदि यह भ्रष्टाचार और जालसाजियों पर प्रभावी अंकुश लगा दिया जाये तो सफाई पर खर्च होने वाले 20 से 30 प्रश, में से मात्र 5 से 7 प्रश खर्च में ही सफाई संभव है। तो फिर स्वच्छता कर थोपने की आवश्यकता ही नहीं पढ़ेगी।

साफ-सफाई में खर्च किया जा रहे धन पर नियमित सुबह 6 बजे से बारीकी से जांच और निगाह रखी जाये, फालतू के शिगूफे घर-घर से कचरा एकत्रित करेंगे, ठेका देंगे, सब करके प्रयोगात्मक तरीके से न केवल इंदौर में वरन् देश के सैकड़ों नगरों में अरबों रुपए के वाहनों, से लेकर 4,6,8 बाल्टी युक्त प्रोजेक्ट उदय में कर्ज लेकर और जेएनआरयुएम में केंद्रीय आवंटन से सारे रिक्शे, ट्रालीयां न केवल इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, के साथ देश के सैकड़ों नगर निगम में उनका यथार्थ, अंकेक्षण वास्तविकता जाने, स्वच्छता कर से वसूली थोप दी गई, परंतु जड़ में भ्रष्टाचार और लूट का मानसिकता बदले, कितना भी धन करों से लेकर आवंटित करने पर भी होगा क्या?

नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण, भ्रष्टों को से.नि. के बाद भी नौकरी

महाभ्रष्ट-जालसाजों का अड्डा- सेवानिवृत्त मु.स. साहनी अध्यक्ष

शिवहरे, परिहार, तोमर जैसे भ्रष्टों, जालसाजों को जिन्होंने अरबों को जन-धन लुटवाया, पुनः संविदा में सेवा में, क्या मूल विभाग में इंजिनियरों का अभाव है पर भ्रष्टों से ही कमाई होगी

मप्र का मु.मं. शिवराज एक तरफ सार्वजनिक मंचों पर घोषणा करता है कि शासकीय कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता लाई जायेगी, भ्रष्टाचार में जीरो टालरेंस अपनाया जायेगा, भ्रष्टों को हर हाल में सजा दिलवायेंगे तो दूसरी तरफ हम भ्रष्टन के भ्रष्टन हमारे की उक्ति को सत्यार्थ सिद्ध करते हुये चारों तरफ न केवल भ्रष्टोंको गले लगाता है, वरन् ऐसे भ्रष्ट, धूर्त जालसाजों को ऊंच पदों पर सुशोभित कर भ्रष्टाचार को संरक्षित और पल्लवित करता है, जिसके उदाहरण शासन के हर विभाग में, मुख्यमंत्री कार्यालय जहां पर श्रेष्ठ धूर्त, मक्कार और भ्रष्ट इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी इकबाल सिंग बैस जैसे प्रमुख सचिव, सचिव विवेक अग्रवाल और एस.एन.मिश्रा, जैसे गिद्धों की फौज बैठी हो से लेकर सभी मंत्रालयों उनसे संबंधित सभी विभागों, जिलाधीशों कार्यालयों से लेकर ग्राम पंचायत तक बैठे सचिवों की कार्यप्रणाली से मिल जाता है, जिनके यहां लोकायुक्त के छापे पड़ने पर करोड़ों की संपत्ति मिल जाती है।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तो स्थापना 1970 से लेकर सन् 2015 तक सभी मुख्य मंत्रियों, मुख्य सचिवों, प्रधानसचिवों, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष से लेकर बाबुओं, चपरासियों और उपयंत्रियों तक के लिये अपने स्तर की दुधारू गाय रही है, जिसकी जितनी क्षमतार्थी उसने उतना ही दोहन तब भी किया और अभी भी कर रहा है, हर किसी ने अपनी कमाई के लिये, हर कदम ठेकेदारों के साथ मिलकर काम कम और जासाजियां ज्यादा की। चाहे वो मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, सखलेचा,पटवा,दिग्विजय सिंह, बाबुलाल गौर या शिवराज सिंह चौहान से 32 संभागों में बैठे कार्यपालन यंत्रियों से लेकर उपयंत्रियों तक ने जमकर धन बटोरा, इसी धन बटोरने में कहीं बाधा उत्पन्न न हो, शिवराज ने भ्रष्ट साहनी को अध्यक्ष बनाकर भविष्य में भी भ्रष्टाचार से वसूली कर रास्ता साफ कर दिया, जबकि साहनी मुख्य सचिव से सेवानिवृत्त होने के 6 वर्ष से ज्यादा समय तक विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष रहकर मोटी कमाई की। बेशक हर मुख्य सचिव तात्कालीन मुख्यमंत्री चाहे वो दिग्गी दानव हो या शिव भोला धूर्त, काजल की कोठरी में बैठाकर पहले न समझ ढक्कन मुख्यमंत्रियों से उल्टे-सीधे काम करवा लेते हैं। बाद में सेवानिवृत्ति के बाद उसे ब्लेकमेल कर अपना मुंह बंद रखने के लिए ये धूर्त महागिद्ध मुख्य सचिव उससे किसी भी विभाग का पद झटक लेते हैं। चाहे वो परशुराम हो, साहनी हो या अन्य इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के सेवानिवृत्त अधिकारी, उसी के अंतर्गत अब साहनी मुफ्त की सुविधायें पाने, न.भ्रष्टाचार घाटी विकास अधिकरण का अध्यक्ष बन बैठा, वही सदस्य अभियांत्रिकीय शिवहरे जिसने जबलपुर में मुख्य अभियंता रहते हुये हरामखोर ने टर्न की प्रोजेक्ट में अपर नर्मदा जोन में अनेकों ठेकेदारों को क्षमताओं के विपरीत अग्रिम कार्यशील पूंजी और संपंत्र हेतु अग्रिम स्वीकृत कर 10 प्रश राशि आंख भींच कर राशि संभाग क्रमांक-1 नागोद जिला सतना में बांटी थीं, सं.क्रं.-1 व 7 का का.यं. विनोदिया ने भी ऊपर से लेकर अपने हिस्से की अग्रिम लेकर राशि ठेकेदार को दे दी, जबकि अपर नर्मदा जोन में बांटी गई राशि में वर्षों बाद भी एक भी टन की प्रोजेक्ट की शुरूआत तो दूर चूंकि सारी कमीशन खोरी में बंट गई कोई भी ठेकेदार न तो कार्य हेतु संयंत्र भी नहीं लाया और अधिकांश के पते नहीं है। आखिर उस अग्रिम की शासन की वसूली की तो दूर ऐसे धूर्त मुख्य अभियंता शिवहरे को अपराधों की सजा देने की अपेक्षा उसे पहले सदस्य अभियांत्रिकीय बनाया गया, फिर सेवानिवृत्ति के बाद भी उसे समय विस्तार भी दे दिया गया, बेशक स.अ.व.भि. बनने के लिए उसने रुपए 25 करोड़ भी खर्च किये तो कमाई भी रुपए 250 करोड़ की तो करेगा, दूसरी तरफ महाधूर्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी रजनीश बैस भी इस नर्मदा भ्रष्टाचार घाटी विकास प्राधिकरण की हर शाखा यथा अभियांत्रिकय, पुर्नवास, वन एवं पर्यावरण, तीनों में उन्हीं सदस्यों को बैठाया गया है, जो भारी भ्रष्ट हैं और जालसाजों से कमाई कर उपाध्यक्ष व प्रधान सचिव रजनीश वैश्य को देते हैं। समय माया लगातार सूचना के अधिकार में जानकारी प्राप्त कर लिखता रहा है कि कैसे अकेले 21 नं. संभाग सनावद सन् 2002 से लेकर सन् 2012 तक कुंडली मारे बैठे कां.यं. आरघ ने जो 1994 से उसी संभाग में सहा. यंत्री था, हर वर्ष करोड़ों रुपए बिहानी का मुफ्त में बिना काम किये महंगाई के नाम बांटे, वहीं ध्यानचंद्र, लदाराम, सन् 2002 में दिये गये रुपए करोड़ के ठेके में जो ढाई वर्ष का था, सन् 2014 तक रुपए 12.5 करोड़ से ज्यादा का भुगतान, सन् 2006 में दिये गये ठेके जो रुपए 9 करोड़ के लगभग था हरामखोर ने रुपए 27.65 करोड़ बांटे, काम अधूरा ही रहा । 16.08.11 से 29.09.11 तक पायोनियर वाटर प्रूफिंग को रु. 10.03 लाख, मे. सुमंत कम्प्यूटर एंड इंजि. वर्क्स इंदौर को 16.08.11 से 29.09.11 तक 36 बिलों से 3.88 लाख, सिटीजन इलेक्ट्रिकल सनावद की मरम्मत और रखरखाव के नाम 18.02.11 से 18.11.11 तक 50 से ज्यादा फर्जी बिलों से रुपए 26.68 लाख का के पूर्णतः फर्जी बिना निविदा, एमबी के बिना काम के ऐसे ही भुगतान हर वर्ष करोड़ों में बांटे जबकि न,तो वहां कोई मशीनरी थी, तो सुधार और रखरखाव की जरूरत नहीं थी। बाहेती फोटो कॉपी, सुप्रीम सायबर कैफे इंदौर को 8,9,10 से लेकर 32 नंबर बड़वाह ने 2001 से लेकर 2015 फोटो कॉपी के नाम पर हर वर्ष हर संभाग ने लाखों रुपए का भुगतान किया, जिसके बारे में मप्र महालेखाकार के ऑडिटरों ने स्वयं मोटा धन हजम कर कभी कोई टिप्पणी नहीं की, कां.यं. आरघ की 21 नंबर में रहते हुये उसके फर्जी जाति प्रमाण पत्र से लेकर हर वर्ष होने वाली करोड़ों की इस लूट की ढेरों शिकायतें, मु.अ. सदस्य अभि., उपाध्यक्ष से लेकर मु.मं. कार्यालय तक लगातार की गई, पर सभी भ्रष्टाचार की गंगा में गोते लगाने वाले चोर-चोर, मोसेरे-मोसेर भाई कौन शिकायत पर कार्रवाई करें, यही हाल वन एवं पर्यावरण में हुआ, जहां लाखों वृक्ष केवल कागजों पर खड़े है। जबकि यथार्थ में वहां प्राकृतिक तरीके से पनपी झाड़ियां होंगी, यहां भी रेंजर से लेकर वन मंडलाधिकारियों तक ने अरबों रुपए के पौधे खरीदी की गई, अरबों रुपए के गड्डे भरे गये। 1999 में जब तुलसीनगर में न.घा.वि.प्रा. का मुख्यालय हुआ करता था, तब एक वनाधिकारी से चर्चा का मौका मिला तो उनसे पूछा गया कि आपने होशंगाबाद जिले में प्रतिदिन 3000 पेड़ लगाके दिखाये है तो कितने मजदूर लगाये, जवाब मिला 500 मजदूर, तो उनसे पूछा गया कि ये तो बहुत ज्यादा है, तो 2000 पर आ गये, उनसे बोला गया कि ये तो आपको अभी भी ज्यादा नहीं कम लग रहा है, तो उन्होंने कम करके 1500 किये और उनको विश्वास दिलाया गया कि नहीं ज्यादा नहीं सर मैं आपके सच का कहीं दुरुपयोग नहीं करूंगा, तो बोले कम से कम 500 पौधारोपण 100 मजदूरों ने किया। इससे कम नहीं करूंगा। ये सारांश है वन विभाग के अमले का न.घा. वि.प्रा. में, अर्थात वनीकरण के नाम पर 70 से 90 प्रश का भ्रष्टाचार किया, पुर्नवास में तो न केवल इंदिरासागर, सरदार सरोवर वरन सबसे पहला बरगी और अंतिम ओंकारेश्वर में सर्वे से ही पटवारी, तहसीलदारों, सहा., उप. जिलाधीशों, संभागायुक्तों, पुर्नवास आयुक्तों ने हर कदम भारी भष्ट्राचार किये और कुल वितरण 30 से 40 प्रश इन हरामखोर धूर्तों ने हजम कर लिया, वही हाल मुख्य अभियंता, अधीक्षक यंत्री, कां.यं. सहा.यं., उपयंत्रियों जो कॉलोनियों का निर्माण और पुर्नस्थापना कर रहे थे। लो.नि.वि., न.घा. वि.प्रा. में भी 30 से 40 प्रश पैसा जो कि रुपए 3000 करोड़ से ज्यादा हजम किया, केग ने रुपए 1500 करोड़ का घोटाला अकेले सरदार सरोवर मे ही माना जब कि केग के अंकेक्षणों जो केवल कागजी चौकीदार श्वान होते हैं। केवल कागजों में नियम कानूनों में उलझन से आर्थिक अधिमियतायें पकड़कर ही आंकड़े जुटाते हैं। जबकि समयमाया ने सन् 2006 धरमपुरी से बड़वानी मार्ग के किनारों पर बनाई गई पुर्नवास बस्तियों के क्षेत्रों की 80 से ज्यादा कालोनियों जो नई बसाई जा रही थी, किस प्रकार से प्लाटों में बंदरबांट की गई, उसमें भी जमकर वसूली हुई, फिर 20 फीट खड्डा बनाकर टैंकरों से पानी भरकर कुएं बनाकर उनमें पानी आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई, सड़कों के नाम पर वहीं से काली मिट्टी पलटाकर पत्थरभर कर चूरी बिछाकर सड़के बना दी गई, उस वक्त का.लो.नि. वि. वि.या. का मुख्य अभियंता शैलेन्द्र शुक्ला जिसे सिविल इंजिनियरिंग का अ ब स द भी नहीं मालूम था। रुपए 1500 करोड़ में से रुपए 600 करोड़ जीम गया था, केग ने उन सरदार के विस्थापितों के बारे में रुपए 900 करोड़ का कागजों पर हुये घोटाले के बारे में भी लिखा है। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर हरामखोर कानून को बलाये ताक रखकर उल्टे-सीधे जवाब देते हैं। एक आवेदन में जानकारी अंतरित की भी गई तो जवाब देने वालों ने जो शुल्क मांगा, उसकी अवधि निश्चित तारीख के पूर्व करने की दी जबकि जालसाजों ने जानकारी न देने के लिए के लिये उसी तारीख के बाद ही पत्र भेजे, जब इंदौर के 36 नं. उपसंभाग में पैसे करने गये तो सहा. यंत्री ने कहा पत्र में निश्चित तारीख के पहले तक ही धन जमा किया जा सकता था, उनको समझाने की कोशिश की गई कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पर ये नहीं माने, दूसरा आवेदन दिया गया कि किस-किस को टर्न की में अग्रिम दिया गया, चूंकि टर्न की प्रोजेक्ट में दिये गये अग्रिम के बाद चूंकि अधिकांश में अग्रिम लेकर ही ठेकेदार कमीशन बांटे कर भग गया तो जानकारी कैसे दी जा सकती है। तो आवेदन को रद्द करके भेज दिया, निर्देशित किया गया कि अलग कर संभागों में पत्र भेजो। अर्थात उपाध्यक्ष से लेकर नीचे तक में भ्रष्टों का जमावाड़ा है।

दुनिया पर अमेरिकी दादागिरी का व्यवसाय आतंकवाद

पेज 1 का शेष

सामने से उसके हर राष्ट्रपति पिछले 40 वर्षों से जिसमें जिमी कार्टर से रोनाल्ड रीगन और पूर्व के बुश और वर्तमान के ओबामा तक सब पुचकारते हुए दिखते और हमदर्दी दिखाने का प्रयास करते नजर आये, इसके विपरीत यथार्थ यह है कि हम हमारा राष्ट्र और हमारी जनता को पाकिस्तानी आतंकवादियों के माध्यम से दहशत फैलाकर ये संकर प्रजाति के धूर्त अमेरिकी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चमकाते रहे, अपने हथियार बैचते रहे, हमसे कमाये सैकड़ों गुना लाभ में से 10-20 प्रश उसी लाभ के हिस्से के टुकड़े पाकिस्तान की सेना को बांटकर आतंकियों के कैंप चलाना, उन्हें हथियार देकर भारत में घुसेड़ना और हजारों निरीहों की हत्या करवाई जाती रही। अभी भी पठानकोट के आतंकी हमले में अमेरिकी सेना की दूरबीन सीरियल नं. के साथ हथियार जो अमेरिकियों द्वारा दान में दिये गये या बैचे गये पाकिस्तानी सेना को, पकड़े गये जबकि पाकिस्तान, अमेरिका, के घोर शत्रुओं चीन, उत्तरी कोरिया, की न केवल मित्रता निभाता रहा वरन् उसी उत्तरी कोरिया ने जिस हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया वह चीन और पाकिस्तान की सह, मेहरबानियों, तकनीकी, और अनुसंधान का परिणाम था, बेशक अमेरिका के लिये युद्ध भी उच्च स्तरीय बहुराष्ट्रीय हथियार निर्माता कं. का व्यवसाय है, जिसमें नाटो देशों का गिरोह भी, अपने हथियारों यथा लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों, विमान वाहक जहाजों से लेकर मिसाइलों, बमों की मारक क्षमता, उपयोगिता का परीक्षण, प्रदर्शन कर बाजार भी तैयार करता है। इस तथ्य की पुष्टि के लिये 1970 से लेकर वर्तमान तक के अमेरिका उसके नाटो गिरोह के सदस्य ब्रिटेन, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, आदि के कुवैत, ईरान-ईराक, अफगानिस्तान युद्धों के अध्ययन से जाने जा सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, पाकिस्तान आदि देशों ने ही भारत के खालिस्तानियों को तन, मन, धन से सहयोग देकर आतंकवाद की शुरूआत की थी, बाद में सरकार की कार्यवाहियों से बचकर इन खालिस्तानियों ने इन्हीं देशों में शरण ली थी। 1965 से 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्ध में भी अमेरिका ने पाकिस्तान को ही सहयोग दिया था। भारत के विरूद्ध अमेरिका और ब्रिटेन ने केवल खालिस्तानियों को पाला वरन संकर प्रजाति के इस दुनिया का शंहशाह समझने वाले अमेरिका ने अभी भी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना को सहयोग देना बंद नहीं किया, जब सन् 2000 के बाद अमेरिका की इस दोगलीनीति का यथार्थ विश्व की जनता को समझ में आने लगा तो अमेरिका ने अपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जहां 90 प्रश एशियाई कार्यरत थे जब वे सब अपने कार्यालयों में पहुंच गये तो स्वयं ही हमले को अंजाम दिया जिससे अनेकों निशाने साधे। एक तरफ वहां पर एशियाई को समाप्त किया उसमें मरने वालों में 10-5 भी अमेरिकी नहीं थे। एशियाई लोगों में दहशत तभी फैल गई, और मोटी जनसंख्या साफ हो गई, दूसरी तरफ पूरी दुनिया की सहानुभूति बटोरकर यह सिद्ध करने में कामयाब रहा कि वह आतंकवाद का जनक नहीं वरन् स्वयं शिकार है। तीसरा उस ओसामा बिन लादेन की आड़ में एशिया के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र अफगानिस्तान जो रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान, ईराक से सटा हुआ है के ऊपर आक्रमण कर दिया और अपनी सेनायें वहां बैठाकर लगातार बमबारी कर अपने शत्रुओं रूस-चीन भारत के साथ ईरान पर भी निगाह रखने, उनको चमकाने का मौका मिल गया, जबकि उस ओसामा बिन लादेन को पालने, गुरिल्ला युद्ध सिखाकर तालिबानियों को विकसित 70 से 80 के बीच अफगानिस्तान से रूसियों को खदेड़ने, रूसी समर्थक सत्ता का तख्ता पलट करने में अमेरिका ही तो था, जबकि अफगानिस्तान से 70-80 के दशक में एक तरफ रूसी सेना को खदेड़ने के साथ, उस सेना के साथ अमेरिका संकरियों को चैन नहीं पड़ा। युक्रेन और चैचन्या में धन के दम पर रूस से भी युद्ध करवाये, उसके परमाणु और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को समाप्त करवाया, क्योंकि सोवियत रूस अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी तो परमाणु, भौतिकी, रसायन, अंतरिक्ष, वैमानिकी, इलेक्ट्रानिक्स, जासूसी आदि के मामलों में कई क्षेत्रों में आगे भी था, इससे अमेरिका को कई क्षेत्रों में मुंह की खानी पड़ती थी। परंतु ओसामा जैसे चेले के माध्यम से रूस को बिखेरकर उसने अपने प्रति द्वंदिता को सदा के लिए समाप्त कर दिया, परंतु जब उसकी पाली हुई विष बेल निरर्थक होने लगी, तालिबानियों ने जब उसकी सुनना बंद कर दिया और पाकिस्तान में अमेरिका के विरूद्ध जब माहौल बनाने लगे तो उसने अपने ही विश्व व्यापार केन्द्र की ऊंची इमारतों में विमान घुसेड़कर एशियाइयों को नष्ट करने के साथ अपनी दादागिरी दिखाने अपने नाटो गिरोह के साथ अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और जानबूझकर अपने इस चेले को बचाता रहा, जो बाद में लीवर केंसर से सन् 2006 में मर चुका था, सित. 06 में फ्रांस के समाचार पत्रों ने इसे तथ्य की पुष्टिकर दी थी। मार्च 2004 के बाद से बीमारी के कारण वह किसी लोक मंच पर न ही प्रकट हुआ, न कोई वीडियो जारी किया, नव-04 में बुश ने दूसरी बार चुनाव जीतने के उसका फर्जी वीडियो जारी कर चुनाव जीता। जबकि 3 नवम्बर 2004 को वीडियो जारी होने के तुरंत बाद 4 नवम्बर 04 की समयमाया ने इस वीडियो को केवल चुनाव जीतने का चुनावी स्टंट करार देकर इसका ईमेल अमेरिकी राष्ट्रपति को व्हाइट हाऊस भेज दिया था, जिसे बुश ने नवम्बर 06 की भारत यात्रा में स्वीकार किया कि मैंने ओसामा के टेप से (दहशत फैला) चुनाव जीता था, बाद में ओबामा ने भी ओसामा के भूत से 2008 का चुनाव जीता, 2012 में नकली ओसामा को मारा फिर अमेरिकी जनता को भ्रमित कर चुनाव जीता। फ्रांस व अन्य के लिए आतंकवाद, युद्ध भी एक पेशा है। विश्वभर में अपनी श्रेष्ठता, दादागिरी और अर्थव्यवस्था चलाने का, इसलिए इनके परमप्रिय थे। वो जेहादी मुस्लिम, जिन्हें जेहाद के नाम पर रक्तपात और हिंसा के लिये उपयोग, किया पाकिस्तान को धन भी येन-केन प्रकरेण देकर आंख भींचकर धन बांटा गया। ताकि उनके सपोले दुनिया को उसते रहे आतकंवाद फैलायें और ये हथियार बैचे। दादागिरी, अब उस पाकिस्तान की फैक्ट्री के सपोले इन्हें उसने लगे, तो नष्ट करने में लग गये, जबकि भारत पिछले 40 से इन सबका सताया भी है।

साप्ताहिक समय माया

मुं.मं. शिवराज के दस वर्ष पूर्ण होने, हजारों करोड़ रुपए

झूठी आत्म प्रशंसा के रोग पीड़ित- बढ़ा भ्रष्टाच

ख्याली बीजों के झूठे आंकड़ों की खेती से कर्मण पुरस्कार, सड़कें, पानी, बिजली, रोजगार, औद्योगिकरण सब पूंजीपतियों को गिरवी कर, मोटा कमीशन डकार जनता को लूटने के लिए छोड़ा

कर व दरें बढ़ाये, भू, खदान ठेकेदारों के सामने नतमस्तक, यदि 30 प्रश भी सत्य है तो सूचना अधिकार अधिनियम-05 के अंतर्गत सारी 17 बिंदुओं की जानकारी ऑनलाइन क्यों नहीं की गई

10 वर्ष बाद भी, फिर जानकारी मांगने पर भी उल्टी-सीधी दलीलें क्यों देते है अधिकारी

मप्र में शिवराज के दस वर्ष पूरे होने की खुशी में सभी दैनिक समाचार पत्रों जो प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के हजारों करोड़ जन-धन के खर्च करके समाचार रूपी दो-चार पेज के विज्ञापन छपवाये गए, जिसमें अपनी आत्म प्रशंसा ही करवाई गई, जिस पर विपक्ष के नेताओं कांग्रेस अरुण यादव, कां. सत्यदेव कटारे व अन्य ने दस वर्षों के कार्यकाल की मु.मं. शिवराज के भाषण समाचार पत्रों, दूरदर्शनी शृंखलाओं में प्रस्तुत साक्षात्कारों को केवल झूठ का पुलिंदा बताया है। भले ही यह पूरा सच न भी हो, तो भी 70 प्रश सच है कि मु.मं. शिवराज यथार्थ जानने के बाद भी 75 प्रश से ज्यादा झूठ बोल रहे है। इसका एक सच यह भी है कि मप्र शासन में बैठे हरामखोर भ्रष्ट, जालसाज इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के व मप्र सरकार मुख्य सचिव एंटनी डिसा से लेकर सभी मंत्रालयों के प्रधान सचिव, सचिव, संचालकों, प्रमुख अभियंताओं, आयुक्तों, जिलों के जिलाधीश, सभी विभागों के जिलों के उपसंचालकों, कार्यपालन यंत्रियों, जिला अधिकारियों द्वारा अपनी उन्नति दिखा सारे झूठे आंकड़ों की लहलहाती फसलें दिखाई जा रही है। झूठे समकों की बाजीगरी से अपनी उपलब्धियों का बखान दृष्य और श्रव्य प्रचार माध्यमों के धूर्त और घोर स्वार्थी, अज्ञानी, छिछोरे, दैनिक समाचार पत्रों जो स्वयं बड़े भूमाफिया, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक अपराधी और सभी प्रकार के अपराधियों को संरक्षण देने वाला गिरोह को खरीदकर करवाया जा रहा है। जिसका यथार्थ आम नागरिक, मजदूर, कृषक ही बता सकता है। जो एक तरफ सरकारी नीतियों से छला जा रहा है, तो दूसरी तरफ सरकारी डकैती यथा बिजली, शिक्षा, ईंधन जिसमें पेट्रोल, डीजल, घरेलू व्यावसायिक गैस सड़कों पर बीओटी चाहे सड़कें कैसी भी हो हर साल बढ़ने वाली कीमतें, दरें, कर से जनता बेहाल है। अमीर और अमीर हो रहा है, भ्रष्टाचार, जालसाजी, लूट से तो वही गरीब, कृषक, मजदूर जो रुपए 5 से 15 हजार भी कमाता है, तो भी वह बच्चों के शिक्षण शुल्क, बिजली के पानी, गैस, गाड़ी के पेट्रोल, डीजल, मोबाइल, टीवी, मकान किराये के मासिक देयकों को ही पूरा नहीं कर पा रहा, तो दो वक्त के भोजन की व्यवस्था करने में ही जीवन होम हो रहा है। अब शिवराज की इस घोषणा का यथार्थ देखिए जब सत्ता संभाली थी प्रति व्यक्ति रुपए 5500 वार्षिक थी, अब रुपए 55000 प्रति व्यक्ति वार्षिक है। यदि रुपए 5000 प्रति माह भी मान ले तो शिवराज बताए कि क्या रुपए 5000 प्रति माह में दो बच्चे और पति-पत्नी कैसे जीवन यापन करेंगे। जबकि रुपए 2000 मकान किराया, 500 बिजली बिल, रु. 500 बच्चों की शिक्षण शुल्क, रुपए 500 आने-जाने का व्यय, रुपए 500 दूध, रु. 1000 में 4 व्यक्तियों का 60 वक्त का भोजन संभव है? जिसमें रुपए 30 प्रतिदिन की सब्जी, रुपए 2000 का राशन आदि में न्यूनतम खर्च होगा, अर्थात रुपए 10000 न्यूनतम खर्च चाहिए। दूसरी ओर पूंजीपतियों की रखैल भाजपा उसका प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 1920 में लागू श्रम कानूनों में, पूंजीपतियों के हित में भारी फेरबदल कर श्रमिकों के घोर शोषण का मार्ग प्रशस्त कर दिया, जब इतने सारे श्रम कानून लगे होने के बाद भी स्वयं सरकारें दैनिक वेतनभोगी कर्मियों जिसकी डिग्री, डिप्लोमाधारी इंजिनियर्स तक को न्यूनतम दैनिक वेतन देकर 20-20 वर्षों तक शोषण कर सकती है तो अधिकांश निजी क्षेत्र के व्यवसायिक, औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की कहानी तो और भी भयावह है। 10 से 12 घंटे नियमित कार्य के बाद भी माह में कोई छुट्टी नहीं और वेतन भी न्यूनतम से कम रु. 5 से 6 हजार प्रति माह, ओवर टाइम के दुगुने वेतन की कल्पना तो निरर्थक है। शासकीय पुलिसकर्मियों को ही लें। 24 घंटे में 6-6 घंटे की दो बार ड्यूटी देने के बाद भी कोई साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक अवकाश नहीं। परिणाम 40 से ज्यादात्तर उम्र के 70 प्रश कर्मी शारीरिक रूप से कमजोर, बेशक श्रम कानूनों में संशोधन और नियोक्ता के विरूद्ध सजा के हर प्रावधान को समाप्त कर आर्थिक दंड दिए जाने की व्यवस्था में मुख्यमंत्री शिवराज, उद्योग मंत्री वसुंधरा राजे, प्रधान सचिव सुलेमान आजम गढ़िया, श्रम मंत्री अंतर सिंग, सचिव, आयुक्त केसी गुप्ता की मोटी धनराशि की भेंट चढ़कर यह षड़यंत्र रचा गया। इन हरामखोर, जालसाज धूर्त गिद्धों की निगाह में इंसान मजदूर नहीं मजबूर है। अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए इसलिए उसको जानवरों से ज्यादा बदत्तर तरीके से हांका जाये, क्योंकि जानवर को भी ज्यादा परेशान किया जाएगा तो वो पलटकर सींग घुसेड़कर यमलोक भी पहुंचा सकता है, पर मजदूर तो बिना सींग वाला, कपड़े पहनने वाला वो प्राणी है जिसे उसकी भूख के नाम पर शोषित किया जा सकता है। इसलिए शासक वर्ग अपने स्वार्थों की खातिर कानून के नाम पर जिस शोषण का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उस धूर्तों शूकरों को यह समझ नहीं आ रहा है कि मनुष्य की कुंठा परमाणु बमों के विस्फोट से ज्यादा घातक होती है।

दलितों और निम्न वर्गों के घोर शोषण का ही परिणाम था कि यह राष्ट्र हजारों वर्षों से गुलाम रहा है और 99 प्रश के पट्टे पर मिली स्वतंत्रता में जिन सत्ताधीशों को सत्ता सौंपी गई वो धूर्त प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री अधिकारी अपने लालच ओर मोटे कमीशन के लिए पुनः उस जनता का शोषण करने लगे जिनके श्रम से उत्पादित सत्ता का ये सुख भोग रहे हैं। बड़ी-बड़ी ढींगे हांकने वाले प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री जिस विकास दर की बातें करते हैं और मिट्ठू मियां अपने हाथ से ही अपनी पीठ थपथपाकर झूठे कपोल कलित आंकड़ों की फसलों से जनता, विनियोजकों और दुनिया को प्रचार माध्यमों से भ्रमित करते हैं। उन सबके धरातल में सबसे प्रथम और अंतिम इकाई चाहे वो उद्योग हो या कृषि मजदूर ही होता है। जिसे न ढंग की दो वक्त की रोटी मिलती है, न ढंग के वस्त्र और न ही छत, फिर भी वह सड़कें, भवन निर्माण औद्योगिक उत्पादन, कृषि में अपने आपको न्यूनतम पाकर भी लगा रहता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना विश्वभर में मजदूरों के इसी शोषण और नियोक्ताओं की निर्ममता को दंडित करने के लिए की गई थी जिसे 1920 में भारत की तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने स्वीकार कर हस्ताक्षर किए थे, जो कि गुलामों पर भारत में राज कर रहे थे, इसके विपरीत हमारी ही चुनी गई सत्ता के धूर्त, मक्कार मंत्रियों और श्रम व उद्योग विभाग के प्रधान सचिव, सचिव आयुक्तों ने नियोक्ताओं के पक्ष में, नियोक्ताओं पर केवल आर्थिक दंड की व्यवस्था के लिए न केवल कई अधिनियमों की धाराओं को हटा दिया, कई धाराओं में संशोधन भी कर दिया।

ये है जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई भाजपा के मुख्यमंत्री की करतूत, जबकि पूर्व से ही न केवल निजी वरन् सरकारी क्षेत्रों में श्रमिकों का घोर शोषण किया जा रहा है। 25-30 वर्ष की दैनिक वेतन भोगी के रूप में इंजीनियरों, कम्प्यूटर ऑपरेटरों, बाबुओं, उद्यानिकी की पौधशालाओं, लो.नि.वि., लो.स्वा.सां., जल संसाधन विभाग, कृषि पौधशालाओं, स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग जैसे अनेकों विभागों में कार्य करवाये जाने के बाद भी वे न तो कुशल की श्रेणी में आये न नियमित किये गये तो निजी क्षेत्रों में किस तरह से अकुशल और कुशल श्रमिकों से बड़े-बड़े पदों पर कार्य लिया जाने के बाद भी उन्हें न तो नियमित वेतन मिल रहा है न अन्य सुविधायें अर्थात श्रमिकों के दम पर कृषि, निर्माण कार्य, सारे सभी प्रकार के उद्योगों से लेकर मंत्रालय तक चल रहे है। अर्थात जिनके दम पर दो वक्त के भोजन से लेकर, सारे नेता, अधिकारी, उद्योगपति इठला रहे है, उन्हीं का चारो तरफ शोषण कानूनी तरीके से किया जा रहा है। उसी मजदूर को न दो वक्त का भोजन, न तन पर वस्त्र, न रहने को मकान, समानता और समृद्धि का झूठा और मक्कारी पूर्ण राग अलापा जा रहा है।

सड़कें- इस जालसाज मुख्यमंत्री शिवराज ने 33000 किमी सड़कें बीओटी के अंतर्गत सौंपकर वाहन चालकों की जेब पर चहुं दिशा डकैती डाली है। हर प्रकार के वाहन विक्रय पर केंद्रीय कस्टम और एक्साइज के 75 प्रश से 100 प्रश करों के बाद भी 12.5प्रश राज्य का वैट, 7 प्रश सड़क कर पंजीयन के साथ 35 प्रश तक पेट्रोल, डीजल, ईंधन पर वसूलने के बाद भी रुपए 2 से 10 रु. प्र. किमी सड़कों पर टोल के बाद भी सड़कें स्तरहीन, गड्ढों युक्त, कदम-कदम मर्गा अवरोधक युक्त होने से रुपए 2 से 10 तक वाहन टूट-फूट, मरम्मत शुल्क खर्च करना पड़ रहा है। जबकि बीओटी की हर सड़क पर बैंकों द्वारा दिग गए धन की जमानतदार मप्र सरकार है, जिसका भुगतान सरकारी माध्यम से जन-धन से ही किया जावेगा, यह जमानतदारी रुपए 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। मप्र सड़क विकास निगम का प्र.सं., प्र. सचिव, लो.नि.मं. से मुख्य मंत्री सब ने मिलकर रुपए 2 करोड़ प्रति किमी परियोजना की स्वीकृति से पूर्व ही हजम कर 4 गुना तक का प्राक्कलन झूठे आंकड़ों और यातायात दिखाकर बैंकों से ऋण स्वीकृत करवाया, यथार्थ मप्र सड़क डकैती विकास निगम की लूट में मुख्यमंत्री भी हिस्सेदार है, इसलिए उसे सीआरएफ, मंत्री, राज्य सड़क व केंद्रीय निधि से भी भारी आंवटन दिया जाता है। जबकि वहां छंटे हुए लो.नि.वि. के महाभ्रष्ट और मूढ़ इंजिनियरों की फौज बैठाई।

आबकारी- प्रदेश की 90 प्रश ठेकों को निलामी में दिए जाने के बाद हर देशी-विदेशी शराब के ठेके पर बिकने वाली कुल शराब का 10 प्रश राजस्व ही सरकारी खाते में जाता है। 30 प्रश पुलिस आबकारी के अधिकारी विनियोजन के तथ्यों से स्पष्ट हो जाती है।

स्वास्थ्य के नाम पर रुपए 4.32 लाख करोड़ के बजट मे से रुपए 2 लाख करोड़ की बंदरबांट निजी, चिकित्सा महाविद्यालयों, निजी नर्सिंग होम्स को गरीब जनता के बीमारों की झूठी बिमारियों बढ़ा-चढ़ा कर खर्च दिखाकर पहले जिलाधिशों के माध्यम से आंकड़े भिजवाकर, फिर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से स्वीकृत करवा कर जिन निजी चिकित्सालयों को पूरे प्रदेश में धन आंवटित कर गरीबों की गंभीर बिमारियों के नाम धन बांटा जा रहा है। उन निजी चिकित्सालयों के पास न तो वे सारी सुविधायें है, न चिकित्सक, फिर भी गंभीर शल्य चिकित्सायें इन निजी नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल, निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में धड़ल्ले से इलाज के नाम पर लूटा भी जा रहा है, खुले में बड़ी कंपनी की दवाओं के परीक्षण में भी वसूली की जा रही है। इसके दूसरी गरीब बीमारी राज्य सहायता निधि का 50 प्रश पैसा, जिलाधीश कार्यालय, सीएमएचओ से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंच रहा है, बेशक इन सभी निजी चिकित्सालयों में सरकारी डॉक्टर्स, चिकित्सालयों के अध्यापक, प्राध्यापक ही 90 प्रश शल्य चिकित्सायें कर अपनी मोटी वसूलियां करते हैं। इसलिए सरकारी अस्पतालों में ये एप्रिन के गिद्ध, डॉक्टर्स, स्टॉफ, चिकित्सा सामग्री, औषधियां व सुविधायें, निजी नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स में मोटे कमीशन पर मोटी वसूली के नाम पर उपलब्ध रहती है। सरकारी चिकित्सालयों में 25 से 50 प्रतिशत मोटे कमीशन पर खरीदी भोपाल में बैठा मंत्री और संचानालय ही करके भेजता है। सीएमओ, सिविल सर्जन भी अपने कमीशन व कमाई के लिए समय बाधित दवाएं, इंजेक्शन, सामग्री आधी खरीदकर पूरे बिलों का भुगतान करते आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में अर्थात रुपए 4.32 लाख करोड़ मात्र एक लाख करोड़ खर्च होता है, स्वास्थ्य विभाग सें चलने वाली 12-14 योजनाओं में से केवल 5-4 का ही यथार्थ में काम होता है। बाकी काम पर सारी योजनाओं का पैसा कागजी बाजीगरी हजम कर लिया जाता है।

उद्योग व्यापार- पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की पूर्ण रखैल की तरह मुखेरा जन पार्टी केवल पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, भूमाफियाओं के लिए सारे नियम-कानून और आम जनहितों की बला ताक पर रखकर अपने मोटे कमीशन और अपने काले धन को दो गुना-चौगुना करने के लिए नाच रही है। रुपए 10-15 करोड़ की हर विनियोजक सभा में खर्च कर देश-विदेश के उद्योगपतियों को बुलाया गया। जनता को बड़े-बड़े सपने दिखाए गए, 10 से 25 प्रश

करोड़ रुपए के जन-धन से विज्ञापन

भ्रष्टाचार, जालसाजियां, महंगाई

कीमतों पर जमीने बांटी गई, श्रम कानूनों, भू कानूनों, आबकारी, वेट आदि सबमें बदलाव किए गए, सरकारी चरनोई, नजूल, वन भूमि, अवैध कब्जों की जमीनों पर अवैध निर्माणों को मोटा धन डकारकर वैध बनाया गया। इस प्रकार अपने भूमाफिया नेताओं, कॉलोनाइजरों, उद्योगपतियों से मोटा कमीशन हजम किया जा रहा है। दूसरी और जब तक उद्योग विभाग औद्योगिक केंद्रीय विकास निगमों में बैठे घोर, धूर्त, मक्कार, भ्रष्टों का जमावड़ा रहेगा, जो छोटे-छोटे से पदों पर बैठकर करोड़ों रुपए के मालिक है। औद्योगिक विकास भी संभव नहीं होगा, बस जमीनों का खेल।

खनिज- मप्र का खनिज विभाग सरकारी डकैतों का अड्डा है। चाहे वो रेती, पत्थर से लेकर कोयला, हीरा तक हो 90 प्रश राजस्व की चोरी स्वयं कलेक्टर, उसके अंतर्गत जिला खनिज अधिकारी, निरीक्षक हो सभी मिलकर कुल खनिजों की चोरी करवाते है। 20 से 30 प्रश की रायल्टी नगद हजम कर लूटने की पूरी छूट दी जाती है। मूल्यवान खनिजों के दम पर ही मंत्री शुक्ला आज अरबों रुपए का मालिम है और बड़ा डकैत होने के साथ विभागीय मंत्री भी है। प्रदेश में बिकने वाला 90 प्रश कोयला भी पूरे प्रदेश में चोरी का ही बिक रहा है। जिसमें कोल इंडिया और वेस्टर्न कोल फील्ड के अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हैं। यही हाल रेती, गिट्टी व पत्थर की खदानों से लेकर अन्य बहुमूल्य खनिजों का भी है। जिसमें वन विभाग के क्षेत्रों की सभी खदानों में रेत, गिट्टी, पत्थर की चोरी स्वयं बीट गार्ड से लेकर रेंजर और डीएफओ तक करवाते हैं। जिससे सरकार को 18 से 20000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का नुकसान होता है। ये है शिवराज सरकार का स्वच्छ प्रशासन, फिर खर्च चलाने के लिए हजारों करोड़ का ऋण लिया जा रहा है।

क्या इसी का नाम खुशहाली है, जहां प्रदेश की 40 प्रश जनता को दो वक्त की रोटी भोजन की व्यवस्था भी नहीं, बकवास है, समृद्ध और खुशहाल मप्र का ढोंग

कृषि कर्मण पुरस्कार भी केवल झूठे और फर्जी आंकड़ों की कारियों द्वारा भल ही कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को मोटा धन भेंट कर आपने कृषि कर्मणा पुरस्कार प्राप्त कर लिया हो, पर सच यह भी है कि कर्ज, मौसम और ओलावृष्टि या अतिवृष्टि के कारण फसलें व उत्पादन बिगड़ने के कारण प्रदेश भर में हर वर्ष हजारों किसान आपके कृषि विभाग के प्रधान सचिव, सचिव, संचालक, जिलों के उपसंचालकों, तहसीलों के सहा. संचालकों से लेकर गांवों के कृषि विस्तार तक न केवल लापरवाह, भ्रष्ट और जालसाज हैं। वरन हर काम जिसमें अनुदान की पात्रता है बिना पैसे लिये काम नहीं करते, फिर ऑनलाइन खाद, बीज, कीटनाशक के फर्जी, नकली, स्तरहीन, सामग्री विक्रेताओं को बिना स्थल निरीक्षण किये, उनकी योग्यता सामग्री व उसकी गुणवत्ता उत्पादकों को स्तर आदि के फर्जी प्रमाणपत्रों के सहारे अनुज्ञाप्तियां बांटी जा रही है, जिससे क्रेता, कृषकों को न्यून स्तरहीन उत्पादन से घोर मानसिक, आर्थिक और सामाजिक यंत्रणाओं का शिकार हो आत्महत्याओं को मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ उत्पादन बिगड़ने से मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ने से कभी प्याज रुपए 5 प्रति किलो, लहसून 10 प्रतिकिलो तो कभी प्याज रुपए 100 प्रति किलो, तो लहसून 200 प्रति किलो बिक जाता है। यह हाल दलहन, तिलहन, अनाजों, साग सब्जी, मसालों की फसलों का भी हैं

मप्र शासन और केन्द्रीय कृषि मंत्रालय और उद्यानिकी द्वारा लगभग रुपए 80000 से 90000 करोड़ विभिन्न योजनाओं, मिशन जिसमें कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई, खाद, बीज, कीटनाशक, ग्रीन हाउस, बैल जोड़ी आदि की खरीदी में अनुदान के रूप में बांटा जाता है, परंतु शासन के सैकड़ों जतन के बाद भी कृषि प्र.स., सचिव, संचालक, उपसंचालक तक 30 से 40 प्रश तक पैसा डकार जाते हैं। फिर प्रधान सचिव राजेश राजौरा जिस पर पूर्व से ही लोकायुक्त जांच लंबित थी। प्र.स. कृषि बनते ही चारों तरफ लूट का तांडव मचा दिया, अपनी कमाई के लिए सैकड़ों करोड़ अलग योजनाओं में मिले। अपना मनचाहा हिस्सा न मिलने से आवंटित ही नहीं किये गये। भ्रष्टों जिसमें उ.स.कनेरिया, एक नेमा, दुबे, जैन व अन्य कई को भ्रष्टाचार के आरोपो में निलंबन किया और मोटी रकम डकारकर किसी को 15 दिन में किसी को माह दो माह में पुनः नियमित नियुक्ति पर बैठा दिया। प्रदेश के हर जिले में बलराम तालाब, खेत का पानी खेत में, निर्मित जलाशयों का निर्माण कागजों पर अरबों रुपए का अनुदान हड़प लिया गया, जांच में उ.सं. नेमा के सिहोर के कार्यकाल में 1200 तालाबों में से 803 तालाब चोरी हो गये थे। देवास में भी 389 तालाब गुम गये, यह हाल इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास से लेकर हर जिले में हुआ, ऐसे हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार किसानों की आत्महत्याओं के बाद भ्रष्ट कृषि कर्मणा पुरस्कार खरीदकर मिट्टूमियां, तारीफों की झूठी और खोखली डींगे हांकता है।

प्रशासनिक चुस्ती और पारदर्शिता का केवल खोखला दिखावा है, जैसा कि ये कहता है कि हर सरकारी कार्यालय में समय पर उपस्थिति के लिए इलेक्ट्रानिक अंगूठा छापने की मशीनें लगा दी गई हैं। 98 प्रश विभागों में अभी तक मशीन का कोई अता-पता नहीं है। 2 प्रश जिन विभागों, स्कूलों कार्यालयों में मशीनें लगाई गई थी, उनमें पानी डालकर अधिकांश मशीने नष्ट कर दी गई है। हर जगह भ्रष्टाचार बढ़ा है। स्थानांतरण, पदोन्नति में बिना पैसे कोई काम मु.मं., मंत्रालयों से लेकर मुख्यालयों तक में कहीं नहीं होता। सभी विभागों में सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर हर कदम जालसाजीपूर्ण जवाब, उल्टी-सीधी जानकारी, अनाप-शनाप शुल्क लेकर भी नहीं दी जाती। ये है डकैत की प्रशासनिक चुस्ती और पारदर्शिता।

खेत का पानी खेत में व बलराम तालाब योजना- इस योजना के अंतर्गत बनाए गए पूरे मप्र में प्रति जिले में औसतन 2000 तालाब पिछले 10 वर्षों में बनाये गये, इसमें 25 प्रश, 33 प्रश व 50 प्रश तक अनुदान का प्रावधान है। जो उपसंचालक कृषि और सहा. संचालक उद्यानिकी की जिले के किसानों को बांटा गया। यहां पर एक ही तालाब पर कृषि ने भी अनुदान दिया और उसी पर उद्यानिकी ने अनुदान स्वीकृत कर सरकार से वसूली की। यहां घोर भ्रष्टाचार किया गया। अकेले सीहोर जिले में जब उ.सं. नेमा हुआ करता थ कुल 1200 तालाब में से 830 तालाब चोरी हो गए थे, इसी प्रकार देवास में 800 तालाब में से 389 तालाब चोरी हो गए, अर्थात तालाब कागजों पर ही बनाये गये, फर्जी खातों, फोटो आईडी से स्वीकृत हुए, कागजों पर बने और अनुदान हजम कर लिया गया, यदि कृषि और उद्यानिकी दोनों के बनाये कुल तालाबों की संख्या यदि 2 लाख है. अर्थात पिछले 10 वर्षों में दोनों ने हर जिले में 2000 तालाब भी बनाये तो 51 जिलों में 2.04 लाख तालाब होने चाहिए, यदि भौतिक सत्यापन किसी स्वतंत्र जांच संस्था से करवाई जाये तो लगभग 50 हजार तालाब कागजों पर बनाकर ही अनुदान हजम कर लिया गया है, ये है खरीदे हुये कृषि कर्मणा पुरस्कार का सच।

किसानों की क्षतिपूर्ति- इंदौर जैसे जिले में किसी भी किसान को एक पैसा भी अनुदान नहीं दिया गया, फिर जिन जिलों में अनुदान दिया गया, वहां कृषि विस्तार अधिकारी, पटवारी से तहसीलदार तक ने 25 से 40 प्रश धन वसूलने के बाद ही महाभ्रष्ट हो जो धन लेकर स्थानांतरण और पदस्थापना करता है। भ्रष्टाचार की जांच लंबित और ठंडे बस्ते में डाल देता है, वहां कैसा कृषक कल्याण कृषि विकास।

शिक्षा- विद्यालयों के भवनों के निर्माण से विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं मिल जाती, या बच्चों को घेरकर विद्यालयों में धकेल देने से बच्चे शिक्षित नहीं हो जाते, वहां जब तक अच्छे शिक्षक मन से बच्चों को नहीं पढ़ाते जबकि 70 प्रश प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक जिन्हें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का वेतन संविदा पर नियुक्त कर दिया जाता हो, फिर वर्ष में 270 दिन के सत्र 70 दिन के अवकाश घटाकर भी 150 दिन भी शिक्षण न हो, शिक्षक 9 माह में 6 माह सरकारी जनगणनाओं, जन सर्वेक्षणों, सरकारी अभियानों में ही उलझाये रखा जाता हो, तो 3 माह में क्या खाक पढ़ायेगा, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षक, फिर 9वीं तक परीक्षा नहीं होती सीधे उत्तीर्ण करो तो 10वीं पहुंच कर उससे नाम भी न लिखते बने तो दोष किसका इस धूर्त सरकार और उसके अधिकारियों का, शिक्षक दोषी क्यों? फिर शालाओं में उपस्थिति भोजन के लिए होनी है, पढ़ने के लिए नहीं।

निजी स्कूलों में विशुद्ध लूट का तांडव होता है, 70 प्रश स्कूलों में शिक्षक में योग्यता क्यों मिलेगी, जब वह निजी स्कूलों के शिक्षकों को रुपए 3 से 5 हजार वेतन मिलेगा, फिर क्यों 90 प्रश स्कूलों के शिक्षक अलग से शिक्षण शुल्क लेकर घरों में पढ़ाते हैं। इस बहाने जो बच्चे घर पढ़ने आते है उन्हें कुछ आता जाता न भी हो तो भी उसे अच्छे नंबरों से पास कर दिया जाता है। फिर अनु. जाति, जनजाति के बच्चों की 50 प्रश छात्रवृत्ति स्कूल संचालक कई प्रकार से हड़प जाते है। यह भी लंबे समय से लोकायुक्त में लंबित है, इन्हीं जालसाज, भ्रष्ट, धूर्त निजी स्कूल संचालकों के साथ ही स्वयं शिक्षा विभाग ने ताकि उनका भ्रष्टाचार, जालसाजी न खूल जाए और सरकार भी पूरे देश में बदनाम न हो। 5वीं, 8वीं की परीक्षायें नहीं होने दी इसके पीछे बेशक विदेशी ताकतें भी नहीं चाहती कि भारतीय बच्चे पढ़कर, परीक्षायें पास कर उच्च शिक्षा ग्रहण कर उनके देशों में नौकरियां करने पहुंचे, ये है शिक्षा की उपलब्धियां। गरीबी रेखा के ऊपर वालों को राशन नहीं फिर भी मप्र देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसकी बढ़ोत्री दर राष्ट्रीय सकल विकास 6.8 से कहीं ज्यादा 7.8 प्रश की केवल कागजों पर है, किसान कर्ज से, बेरोजगार रोजगार के लिए चारों तरफ आत्महत्या कर रहा है और ये हरामखोर जालसाज जन-धन के पैसे खर्चकर टीवी, वेबसाइटों पर हजारों करोड़ लुटाकर अपनी वाहवाही करवा रहे हैं।

मप्र लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग- हत्या के अपराधी को बोलबाला

■भ्रष्ट मंत्री, प्र.स. अभि. ने वसूली के लिए विभाग किया बर्बाद

■हरामखोरों से जानकारी मांगने पर, जालसाज प्रधान सचिव अश्विनी राय तक पत्र अंतरित करने की अपेक्षा, साफ मना कर देते हैं

■पूरा मुख्यालय पर आपराधिक जालसाज प्र.अ. डामोर का कब्जा, नीचे बैठे अधिकारी परेशान सारे विरोधियों को आरोप पत्र

मप्र लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में बैठी मंत्री कुसुम महदेले को बच्चे को लात मारने के अपराध से सरकारी भ्रष्ट अधिकारियों ने यथार्थ पर लीपापोती कर भले ही साफ पाक बरी कर देने से वो भ्रष्ट साफ पाक नहीं हो जाती। दूसरी ओर इस घटना से इस मंत्री की मानसिकता और इसके अंतर्गत कार्यरत मंत्रालयों, यथा लो.स्वा.यांत्रिकीय, उद्यानिकी एवं वानिकी, पशुपालन विभागों को भ्रष्टाचार का बोलबाला है ही, परंतु इस मंत्री के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी विभागों में निष्क्रियता और निकम्मेपन के कारण ऊपर बैठे संचालकों, सचिवों, प्रधान सचिवों के भ्रष्टाचार का नेत्रहीन कानून चल रहा है। मंत्री को मात्र अपने मोटे कमीशन से मतलब है। विभाग में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या परेशानियां है। आवश्यक कार्य के लिए धन का पर्याप्त आवंटन हो रहा है या नहीं, आवंटन के उपरांत उस धन का क्या उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग हो रहा है या अनुपयोग होकर आवंटन की निरस्त हो रहा है। इससे मंत्री को कोई लेना-देना नहीं, पशुपालन उद्यानिकी एवं वानिकी में तो अधिकांश खरीदी, कार्य, कागजों पर दिखाकर 60 प्रश धन विशुद्ध भ्रष्टाचार में ही समाप्त हो जाता है। इसका सीधा संबंध जनता से नहीं होता। इसके विपरीत मप्र लोक स्वा. यांत्रिकीय का सीधा संबंध पूरे प्रदेश के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था से होता है। इस तकनीकी कार्य विभाग में जिस अपराधिक प्रवृत्ति का जिसके ऊपर अनेकों हत्याओं के आरोप थे, अपनी अपराधिक मानसिकता के चलते पूरा विभाग में उसी शैली में कार्य कर रहा है। जो उसके इशारों पर नाचते हैं। उनको मनचाही पदस्थापना, कमीशन पर आवंटन उनके सभी भ्रष्टाचारों पर अनेकों शिकायतों के बाद भी जांच तो दूर पूछताछ भी नहीं की जाती, जो इसके इशारों पर नहीं नाचते,या उसकी कार्य शैली का विरोध करते हैं। उनको भारी प्रताड़ना, जांच, वेतन न देना तक के साथ उनकी जांच, अधिकारी विहीन करना, अखबारों में बदनामी करना, आदि जो अधिकतम किया जा सकता है किया जाता है, जैसा कि यांत्रिकी खंड इंदौर के का.यं. चैतन्य रघुवंशी के साथ इस जालसाज ने पिछले वर्ष किया, जिसके विरोध में का.यं. की न्यायालय की शरण लेना पड़ती है। उच्च न्यायालय इंदौर हस्तक्षेप के बाद पुनः पदभार दिया गया।

इस डामोर की अपराधिक मानसिकता से प्र.स. अश्विनी राय भी डरता है। इस कारण सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर जानकारी देने की अपेक्षा यहां वहां अंतरित कर बचने की कोशिश करता है। अन्यथा यह शूकर स्पष्ट लिखकर कि हमसे संबंधित नहीं। आखिर जनधन से लाखों रुपए प्रतिमाह का वेतन व अन्य सुविधाओं के साथ करोड़ों रुपए की रिश्वत डकारने वालो सत्ता तुम्हारी जागीर नहीं, अपनी जिम्मेदारी से कब तक बचोगो। सूचना अधिकार अधि. का उद्देश्य था। पारदर्शिता लाना, पर जहां तरफ हर शाख पर गिद्धों का बसेरा हो, वो सूचना के अधिकार अधि. 05 की मूल धाराओं का उल्लंघन कर उस भ्रष्ट, जालसाज इकबाल अहमद के दिये निर्णयों को देलीले देने में, प्र.स. अश्विनी राय, कार्यवाहक प्र.अ. डामोर, इंदौर परिक्षेत्र का प्रभारी मुअ सोनगरा, इंदौर वृत्त का अं.यं. मिश्रा तक बैठा जालसाजों का गिरोह आवेदन तक अपने अधीनस्थों को नहीं भेजता, जबकि वसूली में सारे हरामखोर भारी विशेषज्ञ हैं। फाइलें अटकाना, आवंटन बिना कमीशन जारी न करना, स्वीकृति, आदेश, स्नानांतरण, स्थाईकरण, पदस्थापना, सब में बिना वसूली कोई काम नहीं होता, जनता को पेयजल मिले न मिले, इनको पर्याप्त भ्रष्टाचार का धन अवश्य मिलना चाहिए, स्वाभाविक है मंत्री को भी पाइप लाइन का पैसा अवश्य पहुंचता है। इसलिए मंत्री को यथार्थ में विभागों से नहीं उनके धन से मतलब है। फिर 2 वर्ष से ज्यादा समय से मंत्री रहने के बाद भी, उसे अभी भी यह नहीं मालूम होगा कि किस विभाग में कौन सा काम होता है। उसमें कौन-कौन सी योजनाएं है किसमें कितना धन केंद्र और राज्य से आता है। क्या लक्ष्य हैं, क्योंकि इन सबका का लक्ष्य जनहितों की आड़ में, जनधन से येन-केन प्रकरेण अपना, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए जन-धन बटोरना है।

साप्ताहिक समय माया

म.प्र. लोक भ्रष्टाचार निर्माण विभाग

धन दो, आवंटन, प्रभार, जालसाजियां सब लो कदम-कदम लूट

प्रदेश में 21 संभागों में प्रभारी का.यं., बिना भू अधिग्रहण के 3 मी. सड़क पर 5 मी., 7 मी., 9 मी. चौड़ाई की सड़क का भुगतान, अरबों की शासकीय संपत्तियों, भवनों, भूमियों जो लो.नि.वि. के अधीन हैं, बाले-बाले बेच दी गई, वर्षों से किराया नहीं नेताओं, अधिकारियों, दबंगों का कब्जा, मु.अ., अ.यं. इंदौर ने आईआरसी में मोटा कमीशन हजम किया, धूर्त, भ्रष्ट, जालसाज प्र.अ. धन के लिये सबकुछ करेगा

म.प्र. लोक निर्माण विभाग में हर कदम भारी भ्रष्टाचार होता रहा है, परंपरायें भ्रष्टाचार और जालसाजियों की बदस्तूर जारी हैं। वर्तमान की मुखेरा जन पार्टी उर्फ भाजपा को मुख्यमंत्री शिवराज भले ही सार्वजनिक मंचों और जनधन से हर वर्ष अरबों रु. अपनी तारीफें छपवाने और विज्ञापनों के माध्यम से अपने आप को महान मुख्यमंत्री होने, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की घोषणायें करें, इसके विपरीत हर विभाग में घोर भ्रष्टाचार फैला हुआ हैं और स्वयं ही भ्रष्टाचार से धन कमाता है और भ्रष्टाचारियों को पालता हैं। सभी मंत्रालयों में बैठे प्रधान सचिवों, सचिवों, प्रमुख अभियंताओं, संचालकों, आयुक्तों से लेकर नीचे उपयंत्रियों, बाबुओं तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त, जहां जिसको जैसे मिल रहा है लूटने में लगा हैं, फिर चुने हुये मंत्री तो बेचारे करोड़ों का दांव लगाकर चुनाव जीत कर कमाने के लिये ही आते हैं। यदि वो भ्रष्टाचार से नहीं कमायेंगे, तो अपने कार्यकर्ताओं को अगले चुनाव में खिलायेंगें कहां से? फिर लोक निर्माण मंत्री सरताज सिंह तो पूर्व से ही होशंगाबाद, इटारसी के लकड़ी और वन माफिया रहा हैं। तो लो.नि.वि. में भी कम से कम 4-5 वर्ष की मोटी कमाई की जुगाड़ के लिये प्र.स. प्रमोद अग्रवाल जो बड़वानी के एसडीओ से वसूली के टेप कांड में लपेटे में आना सिद्ध करता है कि कैसे उच्च पदस्थ हरामखोर प्र.स. सीधे ही 6 सीढ़ी नीचे से धन खींच रहा था, फिर यदि 21 सहा. यंत्रियों को 20-25 वर्ष बाद भी पदोन्नतियां न देकर संभागीय यंत्री का प्रभार देना वह भी सारे घोर भ्रष्टों को केवल पहले रु. 25 से 50 लाख लेकर बाद में रु. 5 से 10 लाख की रायल्टी पर बैठाया ही इसलिये गया कि बिना भू अधिग्रहण के ही 3 मी. सड़क पर 7,9, 15 मी. सड़क चौड़ीकरण कर का कार्य की डीपीआर 15 से 25% अधिक की भेजो, बिना दोनों तरफ नालियां, 30 फुट की चौड़ाई पर वृक्षारोपण आदि के बिना कार्य करवाओ, बिना चंद्राकार, सड़क बनवाओ, ताकि सड़कों पर पानी भरे और शीघ्र खराब हों, तो फिर पेंच भराई का पैसा मांगो, लो, कागजों पर काम करो और पैसा हजम कर जाओ, उसमें से हमारा हिस्सा हमें पहुंचाओ। इंदौर के सं.क्र. 1 व 2 में भी ऐसे कार्य हुये हैं। फिर सं.क्र. 2 का हरामखोर जालसाज प्रभारी माथुर ने तो ठेकेदारों से 70% अग्रिम बिल लेकर बिना कार्य के ही भुगतान कर दिये, धन हजम करने के न्यायालयीन प्रकरणों में, जबकि सरकारी प्रकरणों में, सरकारी वकील, सरकार की तरफ से मुकदमों की पैरवी न्यायालयों में करता है। 18/5/15 को वकील को रु. 25000/- को भुगतान किया, इसी दिन वकील डी.के. जैन को रु. 10,000/- का भुगतान किया। 15/4/15 को जोशी प्लांटेशन को सुपर कारीडोर पर रु. 24000/- का पेड़ लगाने के लिये फर्जी भुगतान किया, जबकि ये कार्य नगर निगम इंदौर वि. प्राधिकरण के जिम्मे था, 18/4/15 को श्री एससी त्रिवेदी को रु. 5000/-, श्री दिनेश हार्डिया को रु. 5000/- श्री परोड को रु. 7000/- सभी उच्च न्यायालय वकीलों को भुगतान किया गया। 18/5/15 को वकील देवेन्द्र जैन को रु. 10,000/- के दो भुगतान 8 व 9 नं. से किये गये। एयरपोर्ट से सुपर कारीडोर 8 लेन सड़क फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिये सूर्या कंस्ट्रक्शन को रु. 72,30,191/- के भुगतान में से 10% काटकर रु. 65,07,161/- का भुगतान किया गया, जबकि कार्य पूर्णतः स्तरहीन था। 20/6/15 को वकील मोतीलाल को रु.10000/- को वृत्ति शुल्क का भुगतान किया, इसी दिन जूम दुनिया को विशेष उप सं. के फोटो कॉपी के एक ही तारीख के तीन बिलों का अलग नं. से 30/6/14 से 28/2/15 से 23 बिलों का भुगतान रु. 52553/- का वित्तीय वर्ष 15-16 में किया गया, जबकि इन बिलों का भुगतान 14-15 में या तो कर दिया गया था। फिर भुगतान किया गया, सूत्रों के अनुसार इस धूर्त माथुर ने गैंग से कार्य करवाने के लिये लाखों रु. का गिट्टी डामर खरीदा, बिलों का भुगतान हुआ और वह भी बिना कार्य किये। दूसरे ठेकेदार से उठवाकर उसके बिलों में खरीदी दिखाकर पूरा भुगतान हजम कर गया, इसने चप्पे-चप्पे पर भ्रष्टाचार किया, ये तो एक संभाग की कार्यशैली हैं, बेशक माथुर को रु. 30000/- की रिश्वत लेते दबोचने के बाद भी वह लगातार कार्यालय में बैठकर फर्जी बिल पास करने, पुरानी तारीखों में पत्र व आदेश जारी करता रहा, बाद में अपना दाग धोने प्र.स. प्रमोद अग्रवाल ने उसे सागार स्थानांतरित कर दिया। इसी तरह से प्रदेश के 51 जिलों के 70 से ज्यादा संभागों में कार्य किया जा रहा है और अरबों रु. हजम किया जा रहा है। जिसमें अ.यं., मु.अ., प्र.अ., सचिव, प्र.स., मंत्री से लेकर मु.मं. तक हर किसी की हिस्सेदारी है।

सूचना के अधिकार में तीन आवेदन इंदौर के तीन संभागों यथा सं.क्र. 1, 2 व वि.यां को दिये गये थे, सं.क्र. 1 से 4 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई थी, 1 बिन्दु की बिना बिन्दुवार शुल्क का पत्र दिये, राशि मांगी गई, जो जमा की गई, बदले में कितनी संपत्तियां हैं। मात्र उसकी जानकारी दी गई, जबकि उससे प्राप्त आय, यथा किराया, पट्टे का किराया, दूसरा कितना बाकी है। किस-किस पर आदि से संबंधित जानकारी नहीं दी गई, अपील की गई, दूसरे में सं.क्र. 2 में पत्रोत्तर आत्यधिक विलंब से दिया, समयावधि समाप्त होने पर, तीसरा सं. वि. यां में भ्रष्ट का यं. चटर्जी ने जानकारी की अपेक्षाकृत पूर्ण तरीके से हरामखोर ने जानकारी आत्याधिक होने और कार्यालय में उक्त जानकारी चिन्हित करने के लिये लिखा जो पूर्णतः बचने के लिये अर्थहीन व बकवास था, तीनों की अपील अ.यं. जैसवाल जो कि महाभ्रष्ट व जालसाज तो हैं ही जिसने सहा.यं. रहते हुए भारी लूटपाट की, बचने के लिए म.प्र. औद्योगिक केन्द्रीय विकास निगम में का.यं. बन गया। हर कार्य में 40 से 50% धन हजम किया और जब घड़ा भर गया तो पुनः लो.नि.वि. में आ गया, कुछ दिन रहने के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पदस्थ हो गया, जब वहां हल्ला मचा भारी भ्रष्टाचार के कारण ये धूर्त वहां से वापिस लौट गया, कुछ दिन लो.नि.वि. में रहने के बाद लगभग रु. 25 लाख से ज्यादा खर्च कर का.यं.सं.क्र. 1 बन गया, 6 माह लगभग गुजरे ही थे कि न्यायालयीन फैसले के कारण वरिष्ठतम क्रम में आने से अधीक्षण यंत्री सन् 2010 से इंदौर मंडल में डटा है। जब इसने अपील की सुनवाई की तो मात्र सं.क्र. 2 के का.यं. माथुर जो इस महीना देने में आनाकानी करता था। उसको भर निःशुल्क देने का आदेश किया। इसके विपरीत इस जालसाज शूकर ने का.यं.सं.1 और का.यं. (वि यां) चटर्जी की अपीलों को खारिज कर दिया क्योंकि वो इसे महीना देते हैं। वही हाल धार, झाबुआ और अलीराजपुर के संभागों के मामले में भी किया। इसकी जालसाजी की मिसाल देखिये मांगलिया के कोने से बायपास टोल के पास की 4 लेन कांक्रीट सड़क को बनते हुए 7 वर्ष से ज्यादा समय हो गया। उस त्रेहन को बार-बार समय वृद्धि दी जा रही है, जबकि उस ठेके को समाप्त करने के लिये लगातार वर्षों से लिखा जा रहा है। पर्याप्त धन न मिलने पर ये भी ठेका समाप्ति के लिये लिख चुका है परन्तु मुख्य अभियंता श्रीवास्तव ने पुनः धन लेकर ठेका समाप्ति रद्द कर दी। वि.यां. संभाग इंदौर में 8 जिलों यथा इंदौर अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, खंडवा, खरगोन, झाबुआ जिलों के 800 से ज्यादा सरकारी विभागों के भवनों, चिकित्सालयों, विद्यालयों, यह विद्यालयों 5000 से ज्यादा सरकारी आवासों के विद्युत व्यवस्था, यांत्रिकीय मशीनों यथा चिकित्सालयों आदि में आने वाले रु. 200 करोड़ के आवंटन में से मात्र 20% की राशि तक का न्यूनतम भ्रष्टाचार होता है। 25 से 200% तक की ज्यादा कीमतों जबकि 6 आदिवासी जिलों में भारी भरकम राशि 1000 से ज्यादा छात्रावासों के लिये एक जिलों में औसतन 2500 तक छात्रावासों आंगनवाड़ी केन्द्रों, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर मा. विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों तक के भवन होते हैं। हरामखोरों से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर हर समय एक ही रोना रोते हैं। बजट ही नहीं, क्या करोगें जानकारी लेकर। वही हाल उज्जैन के वि.यां.का.यं. का भी है, जिसके पास आगर, देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, उपसंभाग हैं। वर्तमान में रु. 1 अरब से ज्यादा का सिंहस्थ का विद्युत लाइनें बिछाने, ट्रांसफार्मर्स लगाने, लाइट फिटिंग करने, मेला क्षेत्र, सरकार नियंत्रित महाकाल व अन्य मंदिरों, सड़कों की लाइटिंग व्यवस्था में 50% से 200% अधिक कीमतों की सामग्री खरीदी जाकर जमकर वसूली की जा रही है। सिंहस्थ संभाग का महाभ्रष्ट का.यं. केलकर जिस पर मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में रु. 85 लाख वसूली का प्रकरण होने के साथ अनेकों जांचें लंबित होने पर भी रु. 50 लाख से ज्यादा का सौदा कर बैठाया गया, यही कहानी म.प्र. के अधिकांश संभागों में भ्रष्टाचार की है। पर जब प्रमुख अभियंता अखिलेश अग्रवाल ही भ्रष्ट हो, फिर प्र.स. प्रमोद अग्रवाल भी सीधे सहा. यंत्री से वसूलीकर रहा हो, हर आबंटन में 2 से 5% धन मुख्यालय में ही बांटना पड़ा हो, जहां प्र.अं. अग्रवाल अपने खास महाभ्रष्ट मु.अ.आर के व्याप्त जिसे अनेकों बार भ्रष्टाचार के आरोपों जिसने सन् 2004-05 में देवास टोल पर प्रतिदिन रु. 60 से 80,000 रु. की हेराफेरी में जो लगभग 4 माह से ज्यादा की गई, निलंबन रोका गया हो, रा.रा. इंदौर संभाग में सहा. यंत्री रहते करोड़ों की जालसाजी में बचाया हो, अब उसे प्रमुख अभियंता पद पर पदोन्नत करने के लिये उससे वरिष्ठ मुख्य अभियंताओं को आरोप पत्र देकर पीछे धकेला गया हो, जो भी का.यं., अ.यं., मु.अ. धन नहीं देता है। उसको पहले आरोप पत्र दिये जाते हैं। फिर लोकायुक्त जांच के लिए लिखा जाता है। धन मिलने पर जांचे समाप्त कर महीना बांध लिया जाता है। हाल ही में इंदौर में संपन्न भा.स.कां. की 18 से 22 दिस. को हुई सभा में भी कुल आवंटन 10% धन प्र.अ., प्र.स. मंत्री में बांटा गया। इसलिये बड़े भुगतानों में 25% तक के अधिक बिल लगाये गये, जिसमें परिसर, टेक्सी, भोजन, साड़ी बेग खरीदी में भी 25% से 200% तक के बिल लगाये गये। प्रति व्यक्ति चाय का ही बिल रु. 250/- जोड़कर, ऊपर के साथ इंदौर मुख्य अभियंता श्रीवास्तव, अ.यं. जैसवाल, का.यं. माथुर, चटर्जी, राणे व अन्य ने मिलकर बंदरबांट की। अधिक जानकारी के लिये लॉग ऑन करें www.samaymaya.com/mppwd म.प्र. सड़क डकैती निगम में भी लूट का तांडव चल रहा है। बीओटी की सड़कों पर कहीं भी त्रिवर्षीय पुनर्निर्माण तो कहीं किया ही नहीं जा रहा, अधिकांश सड़कें चाहे वो इंदौर-उज्जैन ही क्यों न हो, गड्ढे भरने के अतिरिक्त ऊपर से बनी हुई। सड़कों पर वाहन 60 कि.मी. से ज्यादा गति पर चलाने पर दचके लगते हैं। यह हाल पूरे प्रदेश की सड़कों का है। प्र.स. प्रमोद अग्रवाल ने का.यं. बौरासी को मोटी रायल्टी वसूलने के लिये एक साथ तीन पद सौंप रखे हैं, मंडल इंदौर सं.क्र. 1 व 2 के साथ इंदौर का वृत्त कार्यालय भी उसी का सौंप रखा है ताकि दोनों के साथ उज्जैन संभाग की वसूली में सभी हिस्सा पहुंचाये। म.प्र. सड़क डकैती निगम के उज्जैन संभाग में बैठे सं.प्र. राकेश जैन, जिसके पास 7 जिलों की 1000 कि.मी. से ज्यादा सड़कें बीओटी की जिनसे रु. 10 लाख प्रतिमाह मिलता है। ताकि खराब सड़कों की रिपोर्ट ऊपर न भेजे। सिंहस्थ उज्जैन में बनाये गये सिंहस्थ की सड़कों उन पर लाइटिंग आदि में विद्युत कं. के खंभों को ही पोतकर पुनः लगाकर उस पर 2 से 3 गुना कीमत की लाइटिंग में करोड़ों रु. हजम किया गया। उज्जैन से निकलने वाली हर सड़क बीओटी ठेकेदारों की हैं। डकैत निगम और व उसके ठेकेदार स्तरहीन सड़कों पर भी मिलकर जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं।

समाप्त करो छुट्टियां शनिवार की, बंद करो जन-धन की बर्बादी

पेज 1 का शेष

परंतु प्रदेशभर में शिक्षा विभाग में तो स्कूली और उच्च शिक्षाओं 7 दिन का ही अवकाश घोषित था, परंतु पुलिस, स्वास्थ्य विभाग को छोड़ 90 प्रश छोटे जिलों, तहसीलों और गांवों में तो ताले ही नहीं खुले थे, जो कि पूर्णतः अवैधानिक होने के उपरांत भी मुख्यमंत्री कार्यालय की सीएम हेल्पलाइन से लेकर सभी मंत्रालयों तक ने इन अघोषित अवैधानिक अवकाशों पर मुंह में दही जमा रखा था, फिर जब कार्य इकट्ठा करना पड़ता है तो भी सारे कर्मचारी- अधिकारी चिल्लाते है, तो फिर शनिवार की स्थाई छुट्टी जबकि महीने के दूसरे और तीसरे शनिवार अर्थात वर्ष में 52 में से 24 छुट्टी रहती ही है। जबकि जनहित में हो ना यह चाहिये कि यदि दूसरे व तीसरे सप्ताह में यदि अन्य कोई छुट्टी पढ़ती है तो शनिवार का अवकाश स्वमेव समाप्त माना चाहिए।

भाजपा अपने आपको बड़ा राष्ट्रभक्त होने का जो ढोंग करती है जन से धन को नोंच कर जो कर्मचारी व अधिकारियों को वेतन के रूप में बांटती है वह यह जानती है कि जब साढ़े दस बजे के कार्यालयों के समय पर अधिकांश कर्मचारी अधिकारी 11 बजे से पहले नहीं पहुंचते और जिसमें 70 प्रश महिला कर्मचारी-अधिकारी साढ़े ग्यारह से लेकर 12 बजे तक कार्यालय पहुंचती है फिर 1 बजे से जो भोजनावकाश चलता है तो वह 3 बजे तक चलता ही रहता है। बेशक पुरुषों में भी डेढ़ से लेकर ढाई बजे तक अधिकांश विभागों में यही चलता है। मंत्रालयों, मुख्यालयों में भी यह भोजनावकाश प्रदेश के वल्लभ भवन से विंध्यांचल, सतपुड़ा के अतिरिक्त अधिकांश मुख्यालयों से लेकर तहसील, विकास खंडों तक चलता रहता है। फिर महिलाओं का जलवा तो न केवल निराला वरन 12 बजे तक पहुंचने, 1 बजे से 3 बजे तक लंच मनाने और 4.30 बजे चले जाने के बावजूद, किसी अधिकारी कर्मचारी ने कोई बात इस संबंध में कोई बात की, तो सीधे ही छेड़छाड़ का आरोप लगा देना, अगर आरक्षित वर्ग की हुई तो छेड़छाड़ के आरोप के साथ एट्रोसिटी में भी शिकायत कर दी जाती है, जिससे सामान्य वर्ग के अधिकारी कर्मचारी की जिंदगी को न केवल बदत्तर बना दिया जाता है वरन् ये धूर्त कामचोर महिलायें पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों, कलेक्टर, कमिश्नरों, मंत्रियों-संत्रियों की छवि को पलभर में अपनी मक्कारी के चलते चौपट कर देती है। उसके घर की अपनी बीवी, बेटी की निगाहों में भी कहीं का नहीं छोड़ती। हर साल पूरे देश में हजारों प्रकरण होने के बाद भी इन हरामखोर नेताओं को अपने वोटों की खातिर अपनी वाहवाही के लिए कुछ भी उल्टे-सीधे निर्णय लिए जाते रहते हैं।

आम आदमी व्यापारी, मजदूर, किसान 365 दिन के वर्ष में पूरे 365 दिन काम करे उससे हर कदम-कदम पर करों के रूप में उसका हिस्सा छुड़ा लिया जाये और स्वयं ये धूर्त सत्ताधीश 365 दिन में से 180 दिन भी काम न करें तो भी 365 दिन का पूरा वेतन, भत्तों, कारों, बंगलों का पूरा सुख भोगें। आम आदमी, व्यापारी, उद्योगपति, कृषक, मजदूर, हर दिन चाहे दिवाली, दशहरा जैसे त्यौहारों हो 10 से 15 घंटे काम करने के बाद भी चोर, जबकि उसके द्वारा दिये हुये करों से सरकारें चलाई जाती है। सत्ता में बैठे गिद्ध जनता को हर कदम-कदम हर तरह से लूटते हैं। जन-धन, प्राकृतिक और मानव निर्मित स्त्रोतों को कानूनों को, अपनी जागीर समझ दोहन करते है। आखिर क्यों? सत्ता में पहुंच गये तो दूसरे के हितों का भी ख्याल रखों।

पेट्रोल-डीजल पर 80 प्रश कर वसूलने के बाद भी सरकारें घाटे में चिल्लाती है

जीएसटी से तो दिवालिया हो जायेगी केन्द्र व राज्य सरकारें

18 प्रश जीएसटी से तो वेतन भी नहीं बंट पायेगा सरकारी कर्मचारियों को, फिर अकेले मोदी को हर विदेश यात्रा के लिये भी विश्व व एशियन विकास बैंक से लाखों करोड़ का कर्जा लेना पड़ेगा... आखिर पूंजीपतियों अडानी, अंबानी, टाटा, आईटीसी व अन्य के लिये संविधान बदल क्यों नहीं सौंप देती डकैतों को पूरा देश

भारत का प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सत्ता में रहते, पूंजीपतियों को लाखों-करोड़ का कमीशन डकार, जिस जीएसटी को लागू करने के लिये इतने बेचैन और उतावले हुये जा रहे हैं। जब विपक्ष में बैठते थे, तो सन् 2007 से उसका लगातार 2014 तक अर्थात 7 वर्ष तक घोर विरोध करते रहे, क्योंकि इन्हें मोटा कमीशन नहीं मिला था, अब जब सत्ता में बैठे है तो येन-केन प्रकरण उसे लागू करने में हर दांव खेल रहे हैं। अब छोटे व्यापारी और जनता के हितों का ख्याल नहीं आ रहा है।

दूसरी ओर वर्तमान में अकेले पेट्रोल, डीजल, ईंधन गैस पर ही केंद्र सरकार कस्टम व एक्साइज ही 35 प्रश, 2 प्रश, सड़क, शिक्षा, 2 प्रश स्वास्थ्य व दो अन्य कार्यों अर्थात 11 प्रश उपकर वसूल रही है। वहीं 32 प्रश वेट मप्र सरकार, लगभग इतना ही देश की अन्य राज्य सरकारें भी वसूल रही हैं। इसके बाद भी मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही राज्य सरकारा को कृषि, महिला बाल विकास, लो. स्वा. यां., ग्रामीण विकास, लो.नि.वि., जल संसाधन, उद्यानिकी, वन, गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक, सुरक्षा पेंशन, शिक्षा, नगर निगमों, पालिकाओं, पंचायतों आदि अनेकों विभागों को मिलने वाली अनेकों योजनाओं के मदों में भारी कटौती कर दी गई है। जिससे प्रदेश सरकार ही करीब रुपए 1.20 लाख करोड़ से ज्यादा के न केवल कर्जे में डूब गई है वरन् विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, भा. जीवन बीमा निगम व अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गये कर्जों की किश्तों व ब्याज का भी भुगतान नहीं किया जा सक रहा है। हालत ये हैं कि सरकार को नियमित खर्च चलाने के लिए भी बाजार से ऋण, ऊंची ब्याजदरों पर लेना पड़ रहा है। कई विभागों में भुगतान का संकट भी चल रहा है। जबकि पेट्रो क्रूड की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 वर्ष में ही 120 डॉलर से घटकर मात्र 25 डॉलर पर आ चुकी है। अर्थात कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 प्रश रह गई, इस हिसाब से भारत में पेट्रोल को रुपए 80 से घटकर रुपए 16 बिकना चाहिए था, परंतु बिक रहा है रुपए 65 प्रति ली. यदि जीएसटी लगाया गया तो अधिकतम 20 प्रश कर और राज्य और केन्द्र लगा सकते हैं। अर्थात पानी रुपए 20 प्रति ली. से सस्ता पेट्रोल रुपए 12 प्रति ली. ही बेचा जा सकता है। जबकि वास्तविकता यह है कि 160 ली. प्रति बैरल जो अभी 25 डॉलर प्रति बैरल जिसमें 20 प्रश वैमानिकी ईंधन 30 प्रश पेट्रोल 30 प्रश डीजल 10 प्रश मिट्टी का तेल व 8 प्रश अन्य पेट्रो निक्षेप प्राप्त होते हैं। अर्थात रुपए 150 में 160 ली. में 30 ली. वैमानिकी ईंधन कीमत 80 रुपए ली. रुपए 2400 रुपए 48 ली., पेट्रोल कीमत रुपए 3120 48 ली. डीजल रुपए 55 प्रति ली. कुल रुपए 2640, मिट्टी का तेल 167×15 रुपए 240 रुपए 8400 जबकि 8 प्रश में अन्य पेट्रो उत्पादों में ग्रीस व अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। बेशक इसमें केन्द्र व राज्य सरकारों के कस्टम, एक्साइज, राज्यों के वेटकर भी शामिल हैं। अर्थात रु. 1750 रुपए के पेट्रोल पर रुपए 8500 रुपए कमाने वाली सरकारे जब जीएसटी लागू नहीं हुआ तब भी विदेशों, विश्व बैंक, एशियन बैंक, घरेलु वित्तीय संस्थानो से लाखों करोड़ कर्ज ले रही है। यदि जीएसटी लागू कर दिया तो 20 प्रश अधिकतम कर के हिसाब से रुपए 350 का ही करारोपण कर सकती है। पर जीएसटी लागू करने के बाद भी केन्द्र व राज्य सरकारें कम से कम पेट्रोल, डीजल, ईंधन गैस पर करों से डकैती डालना बंद नहीं करेगी, न कर सकती हैं। अन्यथा केन्द्र व राज्यों की सरकारे लोकसभा व विधानसभा में बैठे व उनके मंत्रालयों को ही वेतन नहीं बांट जायेंगे, देश में फैले सभी मंत्रालयों के विभागों में बैठे सवा करोड़ कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन की तो बात ही बहुत ही दूर, जबकि तीनों सेनाये उनके सैनिकों, अधिकारियों के वेतन के साथ सैन्य छावनियों से लेकर उनके हथियारों यथा थल सेना की गाड़ियों, टैंकों व अन्य गोला बारूद आदि वहीं वायु थल व जल सेना के कर्मियों के वेतन के साथ जहाजों अड्डों, बंदरगाहों, की व्यवस्था व रखरखाव ही नहीं किया जा सकेगा। सैन्य उपकरणों की खरीद और विकास की बात तो बहुत दूर, अर्थ के बिना सब व्यर्थ हो जाएगा।

आखिर इस रक्त पिपासु दानव मोदी ने सत्ता में पहुंचते ही अपने पूंजीपति मित्रों को न केवल देश में जनता को लुटवाने कभी गैस का अनुदान खातों में जमा करवाने के नाम, बीमा करवाने, राशन को पूरी कीमत में बैंचकर अनुदान बैंकों में भेजने, आधार कार्ड से डाटा एकत्रित कर विदेशी कंपनी, देशी कं. से लेकर राजनीतिक पार्टियों को डाटा बैंचने और स्वयं मोबाइल नं. पर भ्रमित करने वाले संदेश भेजने, टिवी को डिजिटल बनाने के नाम रुपए डेढ़ लाख करोड़ लुटवाने के साथ ही रुपए 250 प्रति माह रुपए 70 हजार करोड़ वसूलने, हर कार्य ऑनलाइन करने के बहाने रुपए 500 प्रति कनेक्शन के हिसाब से 50000 करोड़ मोबाइल कं. से लुटवाने और अंबानी, टाटा, बिरला, भारती, वोडाफोन, वीडियोकॉन से लुटवाने की व्यवस्था में यह हरामखोर कांग्रेस से आगे निकल गया, सर्वोच्च न्यायालय के बार-बार रोकने के बाद भी यह गिद्ध जनता को नोंचवाने के लिए आधार कार्ड को स्कूलों कॉलेजों से लेकर सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों तक के बिना आधार कार्ड के स्कूल वाले विद्यार्थियों के नाम काटने की धमकी देते हैं तो सरकारी कर्मियों को वेतन नहीं दिया जाता है। इस आधार कार्ड का उद्देश्य ह कि हर व्यक्ति की कमाई से लेकर खर्च तक सारा डाटा इन बहुराष्ट्रीय कं. के पास हो ताकि न केवल सरकारें वरन् बड़े-बड़े गिद्ध छोटे व्यापारियों, उद्योगपतियों को कैसे बर्बाद कर हर माल और सेवा पर अपना कब्जा कर उन्हें आसानी से नोंच सकें और गुलाम बना सकें। जीएसटी वैसे भी बहुराष्ट्रीय कं. का न केवल जनता को वरन् भ्रष्ट सरकारों के मंत्रियों, अधिकारियों, कर्मचारी श्वानों को टुकड़े डालकर गुलाम बनाकर अपनी तरह से नचाना, सरकारों को दिवालियां बनाना, फिर उन्हें कागजी टुकड़ों रूपी मुद्रा से घी पिलाकर राष्ट्र के प्राकृतिक व मानव निर्मित लाभकारी संसाधनों पर कब्जा जमाना हैं, जो कि विश्व व्यापार संगठन के गिरोह की मूल अवधारणा है।

जिसने न केवल ग्रीस जैसे देशों को दीवालिया बनाया वरन् मेक्सिको जैसे देश की जनता जो जागरूक थी, सरकार को भ्रष्ट मानसिकता व बेबसी के विरूद्ध बिगुल फूंककर इन विदेशी कं. को खदेड़कर बाहर कर दिया, फिर इन बहुराष्ट्रीय कं. की नींच और नोचू मानसिकता की बदौलत अमेरिका, जापान जैसे देशों में भुगतान संकट खड़े कर दिये, फिर कांग्रेस जहां अंग्रेजों की अवैध औलादे की तरह देश को इन बहुराष्ट्रीय कं. का गुलाम बनाकर देश को लूट खसोंट कर बर्बाद करना चाहती थी। वहीं ये देशी मुखेरा जन पार्टी का ये प्र.मं. मोदी जिसमें 45-48 की उम्र तक चाय बेची जिसे न वित्त, न अर्थशास्त्र, न देश के बारे में ज्ञान है, न ही भविष्य की राष्ट्र की समृद्धि व उन्नति का, उसके रक्त में गुजराती रक्तिय अणुओं और परमाणुओं में एक ही बात बसी है, कि अपनी चवन्नी की कमाई के लिये, अपने सहयोगी भले 40 या 400 कमाये और जनता का 4000 भी जाये तो सब चलेगा, फिर एक ठेले पर चाय बैचने वाले को क्या चाहिए अच्छा पहनना, खाना, घूमना, फिरना और अपनी वाहवाही और ताली ठुकवाना। भले ही जनता चीत्कार कर रही हो, उस पर महंगाई की मार हो, चारों तरफ बेरोजगारी हो, चारों तरफ नोंच-खसोंट और भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा हो, उसकी बला से उसने तो रुपए 40 लाख करोड़ अपनी यात्राओं पर खर्च कर दिये, हर विदेश यात्रा में अडानी, अंबानी, टाटा व अन्य के लिये व्यवसायिक सौदे किये, तो फिर जीएसटी किस खेत की मूली है। विपक्ष जो बिकने को तैयार है। खरीदकर जीएसटी पर सहमति ले लेंगे, देश व देश की जनता जाए भाड़ में।

कांक्रीट जंगल खड़ा करने से नहीं बनेगी स्मार्ट सिटी

पेज 12 का शेष

ताली पीटने सूटेड-बूटेड भांडों की आपूर्ति की हो, स्मार्ट सिटी में रहने वालों को, सांस लेने और सड़कों पर पैदल चलने का भी कर या कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि मोदी की प्रिय तिकड़ी अ,अं,टा अर्थात अडानी, अंबानी, टाटा वसूलेगी, स्मार्ट सिटी वासियों को इसके स्मार्ट आधार कार्ड दिये जायेंगे, जो नागरिकों के सीने से चिपके रहकर हर सांस का हिसाब रखने के साथ नागरिकों की हर हरकत पर नजर रखेंगे, जिसमें उर्ध्व और अधो वायु अर्थात मुंह से डकार लेना या पिछाड़ू से वायु गमन भी प्रदूषण फैलाने का अपराध माना जायेगा, स्मार्ट सिटी में ईमेल से शादी होगी और जी मेल से थ्रीडी क्लोन प्रिंटर्स से बच्चे बाहर आयेंगे। स्मार्टसिटी वासियों को वस्त्रों की आवश्यकता भी नहीं होगी। क्योंकि वस्त्रों को धोने में समय और पानी की बहुत बर्बादी होती हैं। साथ ही पहनने संभालने में भी बहुत समय बर्बाद होता है। इसे गरीबी और अमीरी, धर्म, जाति आदि जानने में दिमाग उलझता है। स्मार्ट सिटी के बाशिंदे स्मार्ट होंगे तो इन सब फालतू की झंझटों से दूर, वस्त्रहीन अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले अपने काम से काम रखने वाले होंगे। स्मार्ट सिटी में मुद्रा के लेने-देने की अपेक्षा सारे काम मोबाइल पर लेन-देन से हो जायेंगे, आदि-आदि।

यदि स्मार्ट सिटीज हर नगर और महानगरों के आजू-बाजू विकसित करने में धन मिल हो गया है, तो कुछ तो करके दिखाना होगा भले ही रु. में 10 पें या 10 % काम को धरातल पर उतारने के लिये कृषकों के मुआवजे में ही रु. 500 करोड़ समाप्त हो जायेंगे। दूसरी जो जिन किसानों से जमीनी छीनी जायेगी। वह कांक्रीट जंगल बनने से जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जायेगी, जिससे बनने में लाखों वर्ष लग गये। कांक्रीट जंगल खड़ा करके सदा के लिये बर्बाद कर दिया जायेगा, साथ ही किसानों को बेरोजगार ठीक है कि क्षतिपूर्ति के रुप में धन बांट दिया जायेगा, स्वाभाविक है, भूमि के मुआवजा बांटने में नेताओं, अधिकारियों और कर्मचारियों में भी करोड़ों की बांदरबांट होगी, साथ स्मार्ट सिटी में नये निर्माणों में सड़कें, सेतु, नालियां, बगीचे, पानी की टंकियां आदि के निर्माण में हजारों करोड़ के खर्च में से सैकड़ों करोड़ शासन में बैठे गणों को हजम करने का नया मौका हाथ आयेगा, अभी इसकी तैयारी में नगर निगम विकास प्राधिकरण और जिलाधीश व संभागायुक्त कार्यालयों में बैठे इंजीनियरों और अधिकारियों को हर काम में जो चौगुनी से लेकर हजारों गुना तक हो सकती हैं, मार्जिन से मोदी वसूली शुरु हो चुकी है।

सूचना के अधिकार में इंदौर विकास प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी में जिस भूमि की गुणवत्ता जांचने के जीएसआईटीएस मात्र रु. 250/- वसूलता है, उसके नजी स्तर पर जांच करवाकर रु. 30,000/- के बिलों तक का भुगतान किया गया है। जिसे समय माया ने बिल नं. के साथ छापा था। तो पाठक अंदाज लगा सकते हैं कि किस प्रकार बीआरटीएस की तरह स्मार्ट सिटी के नियोजन और स्थापन में लूट्मार की जायेगी। फिर नगर निगम में कागजों पर ही काम करने, बिल भुगतान करने न करने पर पार्षदों, नेताओं के गुंडों द्वारा मारपीट करने, इंजीनियरों, अधिकारियों को आत्महत्या करने तक विवश किया जाता हो, पैसा हड़पने के लिये 6 इंची की नालियों की पाइप लाइन डाली जाती हो, एक स्थान से टाइल्स उखाड़कर दूसरे स्थान पर लगाने और पैसा हजम करने की प्रवृत्ति ही गणों की है तो नई स्मार्ट सिटी की कल्पना की जा सकती है कि वो कैसी होगी, अगर गण ही ईमानदार होंते तो अभी तक हर गांव, नगर, महानगर अपने आप ही स्मार्ट सिटी हो जाता, यहां तो देश का प्रधानमंत्री मोदी भी सत्ता संभालते ही जनधन पेंशन, गरीबों को सस्ते अनाज, मनरेगा में ग्रामीणों को रोजगार, किसानों को अनुदान जैसी अनेकों योजनायें या तो बंद कर देता है या उनमें इसलिये कटौती कर देता है, ताकि वो अपनी विदेश यात्राओं में लाखों करोड़ रु. आसानी से खर्च कर सके, इस खर्च को निकालने के लिये यह दानव रेलवे, सड़कें, विद्युत मंडलों, शासकीय शिक्षण शालाओं, शासकीय चिकित्सालयों आदि के भवन संसाधन, शासकीय माल गोदामों, विभागों तक की कमान अपने पूंजीपति मित्रों, अडानी, अंबानी, टाटा की तिकड़ी को सौंपकर गिरवी कर शासकीय कं. की मोदी हिस्सेधारी बेचकर मोदी और मुखेरे गिद्ध मंत्रियों की फौज धन इकट्ठा करती है। तो स्मार्ट सिटी की कल्पना, स्थापन में ये राक्षसगण स्वयं धन से कितने स्मार्ट हो जायेंगे अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए ये रक्तपिपासु दानव सभ्यजन और गण नहीं चाहते, यदि जन सभ्य हो गये तो वे इन राक्षस गणों की दाल नहीं गलेगी, भ्रष्टाचार और जालसाजी से चुनाव नहीं जीत पायेंगे, सत्ता को अपने बाप की जागीर समझ उसमें लूट खसोट नहीं कर पायेंगे।

हेलमेट लगा, सीधा दौड़ और मौत के मुंह में घुस

पेज 12 का शेष

फिर हर दो पहिया वाहन चालक की दुर्घटना को हेलमेट से जोड़कर अपनी नाकामियां छुपाने और हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं का आदेश जारी करने वाले स्वयं तो जन-धन से एसी कारों में घूमने वाले जिलाधीश, आयुक्त आदि के साथ उच्च न्यायालय, के न्यायाधीश भी एक साधारण मनुष्य की भांति हेलमेट पहनकर 4-6 घंटे सड़कों पर घूमना क्यों नहीं चाहता, जबकि वह उनकी सुरक्षा के लिए ही माना जाता है। यथार्थ में हेलमेट पहनने के बाद उसके सिर पर जो एक डेढ़ किलो का वजन के साथ इसके सुनने की क्षमता भी समाप्त कर देता है। जो सड़क पर चलते समय आगे, सामने, दायें-बायें से आने वाले वाहनों की आवाज सुनकर बचने के लिए वाहनों को रास्ता देने के लिए अतिआवश्यक है, क्योंकि सड़कें सार्वजनिक है।, उन पर चलते समय न केवल स्वयं को वरन् अन्य आगे-पीछे दायें-बायें चलने वालों को सुरक्षित रखना भी अतिआवश्यक है साथ ही समाज और समय के लिए आवश्यक है। पर जब हेलमेट पहनने कानों को बंद करने के साथ ही अपनी सुरक्षा ही नहीं होगी तो दूसरे की सुरक्षा का कैसे ख्याल रखा जा सकता है। जबकि 30 प्रश गाड़ियों में नंबर प्लेट, 50 प्रश घटिया वाहन चालक चलती गाड़ियों में मोबाइल से बात करते पूरा यातायात बिगाड़ते, कानून की धज्जियां बिखरते चलते हैं। 25 प्रश 4 पहिया वाहन चालकों को वैध चालन अनुज्ञप्तियां ही नहीं है। उन्हें यातायात विभाग और पुलिस क्यों नहीं पकड़ती, क्योंकि पकड़ते ही वो वर्दी उतरवाने की धमकी देता है, अपने आका से फोन करवाता है।

साप्ताहिक समय माया

पेट्रोल, बिजली, सड़कों, नये करों से जनता से वसूली

जनता से लूट, पूंजीपतियों को मत लुटाओं दानव मोदी

लाखों करोड़ हर विदेश यात्रा पर खर्च और जनता पर चहुंदिशी महंगाई की मार

राष्ट्र में जितना 60 वर्षों में कांग्रेस ने देश को खोखला और जनता को परेशान नहीं किया जितना डेढ़ वर्ष में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन और भारतीय प्रशसकीय सेवाओं के अधिकारियों को लालच देकर जालसाजी से सत्ता हथियाने वाली पूंजीपतियों की कठपुतली भाजपा और उसके प्रधानमंत्री महाधूर्त रक्त पिपासु दानव मोदी ने कर दिया, पूरे देश की जनता महंगाई, उसके आधार कार्ड, बैंक खाते, आदि की अनिवार्यता से त्राहि-त्राहि कर उठी, उसे दिल्ली, बिहार के चुनाव में बुरी तरह हराकर उसे आइना दिखाया गया, पर वो धूर्त नौटंकीबाज मोदी और उसका खास दायां हाथ शार्गिद अमित शाह मानने वाला नहीं। जीएसटी के लागू करने में भी रुपए 2 से 5 लाख करोड़ का सौदा अंबानी, टाटा, आईटीसी, बिरला, अडानी से हो चुका है, ताकि जो अभी लाखों करोड़ का विक्रय कर, एक्साइज, केन्द्रीय विक्रय कर, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि पर जो ये लाखों करोड़ का केन्द्र व देश की राज्य सरकारों को चुकाते हैं। उससे इन धूर्त दानवीय पूंजीपतियों को एक वर्ष में ही रिश्वत में दिये गए जीएसटी को लगने से करों की बचत अरबों करोड़ में हो सके और राज्यों की सरकारों को करों के भुगतान से मुक्ति मिल जाए जिसकी किसी भी बहाने छूट की घोषणा केन्द्र सरकार से करवाकर उन सभी प्रकार के करों से मुक्ति मिल जायेगी।

मोदी ने सत्ता संभालने से लेकर अभी तक हर जनता के उपयोग की वस्तु पर न केवल कर बढ़ाये वरन खाद्य वस्तुओं पर धूर्त पूंजी राक्षसों यथा अंबानी, टाटा, वालमार्ट, बिरला, इंडियन टोबेको का., अडानी, हिंदुस्तान या युनि लीवर जैसी अनेकों बहुराष्ट्रीय कं. को खुले बाजार से गेहूं, दाले, तिलहन,चावल जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं को बिना खरीदी की सीमा और स्टॉक की सीमा तय किये बिना ही मुक्त व्यापार की छूट देकर पहले अच्छे माल को खाड़ी व युरोपीय देशों में निर्यात से मोटी कमाई करवाई, साथ रु. 60-70 किलो दाल बैचना शुरू किया, बाद में धीरे-धीरे कीमतें बढ़ाकर यही तुअर दाल रुपए 200/- से प्रति किलो से ज्यादा पर पहुंच गई जिससे आम आदमी की दाल-रोटी छिन गई और दाल भी देश के 60 करोड़ गरीबों के घर सप्ताह या महीने में एक बार बनने लगी। ये थे इस दानव के अच्छे दिन, जबकि दाल पैदावर कम से कम 14-15 में सामान्य थी।

पेट्रोल, डीजल, गैस आदि की कीमतें भी मोदी की सत्ता संभालते ही किस्मत से 120 डॉलर से घटकर 40 डॉलर प्रति बैरल फूड पर आ जाने के बाद भी इसने रुपए 80 प्रति लीटर के पेट्रोल को मात्र रु. 80 से घटाकर रुपए 65 प्रति लीटर अर्थात लगभग रुपए प्रति लीटर जो कि मात्र 18 प्रश ही कम हुआ, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें 70 प्रश तक कम हो गई थी। फिर भी गैस, पेट्रोल और डीजल पर अनुदान देने का रोना बंद नहीं हुआ, दूसरी और लगातार पेट्रोल, डीजल, ईंधन वायु पर लगातार कस्टम, एक्साइज, राज्यों के मूल्य सहकर,वाणिज्यिक कर या बिक्री कर जो कि मप्र में 32-32 प्रश होने के साथ ही 2 प्रश शिक्षा, 2 प्रश सड़क निर्माण, 2 प्रश स्वास्थ्य, 2 प्रश अन्य उपकर या सेश अर्थात 72 प्रश करारोपण कर जनता को लूटा ही जो रहा है। जबकी जनता को निजी क्षेत्रों के स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में प्रति वर्ष लगभग रुपए 50 लाख करोड़ गंवाने पड़ते हैं, तो फिर 2 प्रश शिक्षा का सेस हर सेवा, ईंधन पर वसूलने का औचित्य क्या है, जब लोकतंत्र में शिक्षा एक जैसी और निःशुल्क नहीं है। साथ ही देश के आधारभूत विकास की मूल जड़ शिक्षा पर पूर्णतः सफेद पोश डकैतों, माफियाओं और बाजारू चरित्रहीन प्रवृत्तियों का कब्जा है, जिसमें लोकतंत्र के लूटेरे शासकीय तंत्र के भ्रष्टों और जालसाजों का न केवल खुला संरक्षण होने के साथ जिसकी नियत ही विदेशी आकाओं के इशारे पर नाच पहली से 9वीं कक्षा तक परीक्षाओं को समाप्त कर देश की युवा पीढ़ी को नकारा कमजोर और ज्ञानहीन बनाने पर तुली रहकर देश के भविष्य की बर्बादी पर तुली हो, तो 2 प्रश शिक्षा कर से देश की वसूली क्यों की जा रही है। जबकि लोकतंत्र में शिक्षा मौलिक अधिकार और निःशुल्क होनी चाहिए।

यही हाल 2 प्रश सड़कों के विकास का सेश वसूला जा रहा है, जबकि 90 प्रश राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर 40 प्रश तक प्रति किमी बीओटी शुल्क देना पड़ रहा है, तो 2 प्रश सड़क विकास सेस की लूट क्यों, जबकि 72 प्रश ईंधन पर, 12.5 प्रश विक्रय कर, 60 से 90 प्रश कस्टम एक्साइज, 7 प्रश सड़क कर वाहनों के पंजीयन पर ही वसूल लेती है, जो बुरी तरह से खराब गड्ढे युक्त होने पर भी टोल टैक्स वसूल कर भी जीवन यात्रा का सकूनभरी यात्रा नहीं मिलती। वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं और सड़कों पर 40-60 किमी की गति से भी नहीं चलाये जा सकते फिर भी 2 प्रश सेस क्यों? राज्यों के सड़क डकैती विकास निगम क्यों चलाये जा रहे हैं। केवल डकैती के लिये 2 प्रश स्वास्थ्य सेस, जिससे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या एनआरएचएम चलाया जा रहा है। जबकि 90 प्रश स्वास्थ्य सेवायें गावों से लेकर शहरीय निजी स्तर पर गिद्ध डॉक्टरों के चंगुल में है व सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का वेतन भत्तों को छोड़कर 70 से 80 प्रश डॉक्टरों अधिकारियों से लेकर, सचिवों और मंत्रियों तक डकार लिया जाता है। तो जनता से ईंधन, विद्युत, संचार व अन्य सेवाओं में 2 प्रश कर की वसूली क्यों की जा रही है। प्राप्त समाचारों और जानकारी के अनुसार झाबुआ और अलीराजपुर में रिलायंस के अंबानी को शहर व गांवों के सरकारी चिकित्सालयों को सौंपने के आदेश जारी किये जा चुके हैं। स्वा. मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा। सरकारी चिकित्सालय महाविद्यालयों को भी निजी कंपनियों को सौंपने की तैयारी की जा चुकी है।

ऑनलाइन लाइसेंस अनापत्ति, पंजीयन जालसाजों और अपराधियों को संरक्षण

ऑनलाइन की आड़ में ऑफलाइन मोटी कमाई- जनहितों की उपेक्षा व शोषण

आधारभूत संरचना, कंप्यूटर सामग्री क्रय, साफ्टवेयर निर्माण में अरबों रु. का मोटा कमीशन हजम, अपनों को ठेके, कमाई के अवसर व लूट, दूसरी तरफ ऑनलाइन श्रम विभाग, कृषि, खाद्य एवं औषधि, उद्यानिकी, औद्योगिक स्वा. एवं सुरक्षा, वाणिज्यकर, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य, ग्रामीण यांत्रिकीय, जल संसाधन संपत्तियों का क्रय-विक्रय आदि में ऑनलाइन के नाम पर पूर्व में ऑफलाइन। अरबों रु. का खेल, फर्जी आंकड़ों, दस्तावेजों से ही औपचारिकतायें पूर्ण कर बिना भौतिक सत्यापन के भी जारी किये होने पर जनता के साथ लूट बढ़ेगी

म.प्र. का मु.मं. शिवराज यथार्थ में मिट्ठू मियां कागजी खेतों पर झूठे आंकड़ों की फसलों से अपनी उपलब्धियों का जो बखान करने और प्रचार माध्यमों को जन-धन लुटा कर अपनी झूठी प्रशंसा छपवाकर, जो श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगे हैं। उसके पीछे की धूर्तता और कमीशन खोरी की लंबी और गहरी क्षति जनता ो ही भुगतनी पड़ रही है। दूसरी ओर जालसाजों, ठगों की जो कंप्यूटर सामग्री आपूर्ति करते हैं व साफ्टवेयर की कार्यप्रणाली तैयार करते हैं। उनो 10 से 100 गुना तक भुगतान कर मंत्रालयों में बैठे धूर्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारियों दोनों हाथों से मोटी क्रीम हजम करने में लगे हैं।

मिट्ठू मियां मु.मं. शिवराज और उनके आईटी मंत्री, सचिव व संबंधित विभाग के प्रमुख यथा आयुक्त, प्रमुख अभियंता, संचालक आदि मिलकर अरबों की खरीदी में करोड़ों का कमीशन डकार रु. 20,000/- का कंप्यूटर रु. 50,000/- में, रु. 6 हजार का मॉनिटर रु. 18,000/- में, रु. 6000/- का प्रिंटर रु. 30,000/- से 32000/- में रु. 1500/- का इनवर्टर रु. 18000/- में, रु. 20 से 25 लाख का साफ्टवेयर रु. 5 से 500 करोड़ तक खरीदे जाते हैं जैसा कि ई रजिस्ट्री कांड में हुआ, विप्रो से रु. 500 करो के सौदे में सीधा रु. 450 करोड़ हजम किये गये। और पूरे म.प्र. के हर कार्यालय में जो संभागीय, जिलों से लेकर तहसील और ग्राम पंचायतों तक पहुंचा दिये जाते हैं। जिसमें जनधन का अरबों रु. बर्बाद किया जाता है। अकेले म.प्र. के वाणिज्य कर विभाग में ही रु. 20 हजार का कंप्यूटर रु. 2 लाख में और जो साफ्टवेयर रु. 25 लाख में भारत सरकार के उपक्रम डीइटीसी ने मात्र सालभर में बना दिया था, जिसकी कार्यक्षमतायें भी बेहतर थी। टीसीएस ने एक तरफ 10 गुना ज्यादा पर कंप्यूटर ट्युलिप के नाम से आपूर्ति की वहीं रु. 5 करोड़ लेकर 8 वर्ष बाद भी ढंग का वेट के लिये साफ्टवेयर नहीं बना पाई, उसमें पिछले 6 वर्षों से सुधार कार्य ही चल रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार महाधूर्त जालसाज इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी अनुराग जैन ने टीसीएस से लगभग रु. 200 करोड़ हजम कर प्रदेश के सभी विभागों में कम्प्यूटराइजेशन में जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति 10 गुना ज्यादा कीमतों पर साफ्टवेयर के नाम पर 10 से 50 गुना ज्यादा कीमतों पर आपूर्ति करने का ठेका देश और दुनिया की महाभ्रष्ट और जालसाज कंपनी टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज को सौंप दिया गया। अकेले म.प्र. वाणिज्यकर विभाग में सूचना के अधिकार में प्राप्त जानकारी से ज्ञात हुआ कि कैसे सन् 2008 में रु. 20,000/- का कम्प्यूटर रु. 2 लाख में और एक लाख का साफ्टवेयर 7-8 वर्ष बर्बाद करने और वाणिज्यकर के उपायुक्त से लेकर सहा. आयुक्त व अन्य 25 कर्मचारियों और अधिकारियों के समूह का उपयोग करने के साथ हर सप्ताह 5-7 अन्य होशियार अधिकारियों की सेवायें लेने के बाद भी यह साफ्टवेयर तरीके से तैयार नहीं किया जा सका, जबकि उसमें रु. 25 करोड़ से ज्यादा की बर्बादी इस टीसीएस ने कर दी, इसके विपरीत टीसीएस के विरुद्ध मंत्रालय से लेकर मुख्यालय त कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं।

इसका दूसरा पहलू यह भी है कि ऑनलाइन टिन नं. लेने में व्यापारी और उसके कर सलाहकार कागजी खानापूर्ति कर ऑनलाइन टिन नं. लेने के बाद धड़ल्ले से जालसाजियां कर करोड़ों के माल की बिक्री उस टिन नं. पर करने के बाद जब विभाग का कोई निरीक्षक या सहा. वा.कर अधिकारी वहां पहुंचा जिसके पते पर पंजीयन क्र. आवंटित था, वहां ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया, जबकि कर सलाहकारों के अनेकों बार अधिकारियों से बहस करते देखा गया कि आप तो तत्काल टिन नं. जारी करने पर हस्ताक्षर करो? सब कुछ सही हैं, जबकि वास्तविक सत्यापन किये बिना टिन नं. जारी नहीं किये जाने चाहिए।

यही हाल कृषि विभाग में भी खाद, बीज, कीटनाशक विक्रेता, उत्पादक लायसेंस के भी हैं, बिना दुकान और फैक्ट्री मालिक की योग्यता, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर के अधिकृत विक्रेता के रुप में मान्य किये जाने की वास्तविकता जाने की अनुज्ञाप्ति जारी समय सीमा में जारी करनी होती है। जब तक विभाग का अधिकारी, कर्मचारी, सत्यापन के लिये पहुंचे तब तक किसानों को माल बेचकर विक्रेता गायब हो जाता है, चाहे फिर खाद-बीज, कीटनाशक पूरा स्तरहीन होकर किसान की फसल बिगड़ जाये और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जायें, यही कारण है कि हजारों किसान आत्महत्या करके मर चुके हैं। भ्रष्टाचार रोकने की आड़ में भारी जालसाजियां भ्रष्टाचार हो और किसान आत्महत्या कर लें वह चलेगा, आवश्यकता इस बात की है, कि आवेदन ऑनलाइन करने के बाद तत्काल किसी भी कृषि अधिकारी को भेजकर हर तथ्य वास्तविक सत्यापन के बाद ही लायसेंस जारी किये जायें।

खाद्य एवं औषधि में भी ऑनलाइन, दस्तावेजी सबूतों से परे. क्षेत्र में जाकर यथार्थ को आंकलन और सत्यापन के बाद ही लायसेंस जारी होने चाहिये, यदि ऑनलाइन प्रेषित दस्तावेजों, दुकान, फैक्ट्री, कर्मचारियों व अन्य स्थिति का भी सत्यापन किये बिना खाद्य व औषधियों के विक्रेता उत्पादक की अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जानी चाहिये, क्योंकि खाद्य एवं औषधि दोनों ही आत्यधिक संवेदनशील एवं सीधे ही मानव स्वास्थ्य को तत्काल प्रभावित करते हैं। बेशक स्टाफ की भारी कमी साधनों के अभाव में नमूने लेने, निरीक्षण करने, जांच रिपोर्ट समुचित कार्यवाही भारी भ्रष्टाचार के कारण भी नहीं हो पाती हैं। इसलिये अनुज्ञाप्ति धारी सारे अपराध करने के बाद भी बच निकलता है। इसलिये आवश्यक हैं कि अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व ही हर तथ्य की ठोस व बारीक जांच की जायें, क्योंकि ऑनलाइन मैं सभी दस्तावेज फर्जी लगाकर भी आसानी से औपचारिकता में पूरी कर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेना, बहुत आसान हो गया है।

श्रम गुमास्ता, फैक्ट्री संचालन हेतु पंजीयन भी ऑनलाइन करने में उपरोक्तानुसार फर्जी दस्तावेजों से पंजीयन करवाये जा रहे हैं और औपचारिकतायें पूर्ण कर उद्योगपति, शोरुम मालिक शासकीय सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। जबकि अकेले इंदौर में 90% व्यापारिक संस्थान अपने कर्मचारियों की न केवल न्यूनतम दैनिक मजदूरी रु. 251/- प्रतिदिन अकुशल और कुशल को रु. 350/- प्रतिदिन तक का भुगतान तो दूर कुशल, प्रशिक्षित श्रमिकों तक को रु. 150/-, 200/- तक मजदूरी में कार्य लिया जा रहा है। यहां तक कि म.गा. मार्ग पर, कासलीवाल होंडा के वर्कशाप में प्रशिक्षित मिस्त्रीयों को जो सुबह 9 से शाम 7-8 बजे तक कार्य करते हैं। मात्र रु. 5000/-, 6000/- प्रतिमाह वेतन बिना छुट्टियों के दिया जा रहा है। जब शिकायत की गई सहा. श्रमायुक्त ऊदे को तो जांच की खानापूर्ति कर मोटी रकम लेकर लौट गया।

निष्कर्ष यह है कि ऑनलाइन पंजीयन में जिस भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश की गई, उसके विपरीत जालसाजों और भ्रष्टों की पौबारह हो गई, क्योंकि मैदानी सत्यापन से पूर्व ही जनता को मूर्ख बनाकर व्यापारी, उद्योगपति, उत्पादक ने अनुज्ञप्ति दिखाकर वसूली की और रफूचक्कर हो गया।

इसलिये आवश्यक है कि समयसीमा को यथार्थ और दस्तावेजों का पूर्ण सत्यापन कर ही टिन नं., खाद, बीज, कीटनाशक, खाद्य एवं औषधि, श्रम, उद्योगों के संचालन के संबंधित म.प्र. औद्योगिक स्वा. एवं सुरक्षा आदि द्वारा म.प्र. प्रदूषण मंडल द्वारा अनापत्ति आदि जारी किया जाना चाहिये।

मप्र महिला बाल विकास

90% आंगनवाड़ियों का धन हजम अधिकांश कार्यक्रम कागजों पर

जानकारी मांगने पर न तो पूरा जवाब देते हैं, पैसा जमा करने पर आधी-अधूरी जानकारी

मप्र शासन का मु.मं. शिवराज महिलाओं और बच्चों के लिए घोषणायें तो बहुत सारी करते हैं। पर यथार्थ में मैदानी क्षेत्रों में उनका कितना पालन हो पा रहा है, इस पर नियंत्रण की भारी कमी और निठल्ले व भ्रष्ट शास. कर्मचारियों और अधिकारियों के चलते अधिकांश योजनायें कागजों पर पूरी होकर जन-धन हजम कर लिया जाता है। यही हाल अधिकांश योजनाओं, परियोजनाओं का होता है। इसमें महिला बाल विकास भी एक ऐसा ही विभाग है, जिसमें पूरे प्रदेश के 51 जिलों में चल रही सरकारी डायरी के अनुसार 92,230 आंगनवाड़ियों में जिसमें औसतन 100 बच्चों के अनुसार 92,23,000 बच्चों को भोजन की व्यवस्था होनी चाहिये, ताकि पोषण के शिकार न हो बच्चे, दूसरी ओर महिलाओं को जो भी गर्भवती हों उनको भी शासन की तरफ मिलने वाला पौष्टिक आहार से लेकर विटामिन और आयरन की गोलियां आदि तक देने की व्यवस्था होती है। पर यथार्थ यह है कि 90 प्रश आंगनवाड़ियों में 90 प्रश तक बच्चों और गर्भवती महिलाओं की संख्या केवल पंजियों में रहती है। उनके नाम का आहार का पैसा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी और एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी तक ही डकार जाते हैं। निःसंदेह यह पैसा पाइप लाइन से आयुक्त एकीकृत बाल विकास सेवा से मंत्री और मुख्यमंत्री तक जाता है। स्वाभाविक है कि केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त राशि का 90 प्रश बंदरबांट और भ्रष्टाचार में ही हजम हो जाने के कारण यथार्थ में गरीबी और भुखमरी के शिकार गांवों के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता।

सूचना के अधिकार में जिला कार्यक्रम अधिकारी देवास से इसकी जानकारी मांगी गई जिसमें 4 बिंदू थे, कि वर्ष की हर तिमाही में कितना आंवटन प्राप्त हुआ, आंगनवाड़ियों का निरीक्षण अधिकारी श्रीमती सुनीता यादव है, जो अनेकों बार चक्कर लगाने के बाद भी कभी भी कार्यालय में नहीं मिली, स्वभाविक था अनेकों बार जि.का.अ. से मिलने के प्रयास निष्फल होने के उपरांत कार्यालय में बैठे कर्मीयों से ही चर्चा की गई। भेजे गये पत्र में पूछा गया कि जब 4 बिंदुओं बिंदु के किस समयावधि में कितने दस्तावेज होंगे। तो अपने पत्र से एक मुस्त 160 दस्तावेजों के जो पैसे जमा करो, आपको इससे क्या मतलब है कि हम क्या देंगे, फिर पूछा गया कि जब आवेदन में स्पष्ट लिखा गया कि बिंदूबार व समयावधि सूचना दें कि किस बिंदु और समय के हिसाब से दस्तावेजों की जानकारी भेजने की अपेक्षा आप पूरा जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आपने हर बिंदू की अगर जानकारी के दस्तावेज गिने हैं जो जानकारी देने में क्या तकलीफ है। वहां बैठे बाबुओं ने बत्तमीजियों के साथ दिये उत्तरों से वह इसके बाद मालूम पड़ा कि खरीदी के मात्र 12 बिल, 1858 आंगनवाड़ियों की वर्षभर की मात्र 13 निरीक्षण प्रतिवेदन पूछा गया कि 12 बिलों से 1858 की पूरी खरीदी हो गई, जिसमें करोड़ों रुपए व्यय हुआ है। 13 पन्नों में 1858 आंगनवाड़ियों का निरीक्षण पूरा हो गया तो फिर बत्तमीजी दिखाने लगे और कहा गया कि आपसे जो बने कर लेना फांसी पर चढ़ा देना, यह सब घटनाक्रम यह बताने के लिये काफी है कि महिला बाल विकास का किस प्रकार 90 प्रश पैसा हजम किया जा रहा है। यदि हर जिला कार्यक्रम अधिकारी व बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी से लेकर आयुक्त और मंत्री की बारीकी से जांच की जाये तो आंगनवाड़ियों की कार्यकर्ता और संचालिका से लेकर जिले के जिलाधीशों, मु.कां.अ.जि. पंचायतों का सारा पैसा बिना कुछ किये घरे हजम किया जा रहा है। करोड़ों रुपए के दाल, दलिया, पोहे, बिस्कुट अन्य खाद्य सामग्री की आपूर्ति कुछ विशेष फर्मों से ही की जाती है। जिसके बिलों भर का भुगतान होता है। औसतन 100 बच्चों की आंगनवाड़ियों में पिछली निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 प्रश में एक भी बच्चा नहीं पाया गया, 50 प्रश में उसे 5 बच्चे, 30 प्रश में 6 से 10 बच्चे, 10 प्रश में से ही 10 से ऊपर बच्चे ग्रामीण आंगनवाड़ियों में और शहर की आंगनवाड़ियों में तो कुछ बच्चे केवल झुग्गी बस्तियों के आसपास की और मजदूर क्षेत्र की आंगनवाड़ियों में ही कहीं-कहीं 10-20 बच्चे पाये गये।

जितनी आंगनवाड़ियों पूरे प्रदेश में चल रही है। 7 करोड़ की आबादी में से 92 लाख बच्चे अगर 92,230 आंगनवाड़ियों में जाते हैं तो 1 से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या ही नहीं है, प्रदेश में फिर क्या 80 प्रश शहरीय आबादी 30 प्रश ग्रामीण आबादी के बच्चों के नाम फर्जी दर्ज कर रखे हैं। आखिर इस हरामखोर शूकरों के विभाग में 30 प्रश आंगनवाड़ियों के बाद भी जांच क्यों नहीं की गई, धूर्त मोदी सरकार को नहीं चाहिये कि इस रुपए 1 लाख करोड़ से ज्यादा के हर वर्ष के इस भ्रष्टाचार को रोकने पूरे देश के राज्यों के मु.मं., मु.सं. को कहे, ऐसी सभी भ्रष्ट आंगनवाड़ी संचालिका से लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस फर्जीवाड़े में पकड़कर जेल में डाले। व वास्तविक जरूरतमंद बच्चों को पौष्टिक आहार बैंक खातों के माध्यम से सीधे बच्चों के माता-पिता को उपलब्ध कराये।

33% महिला आरक्षण, बना दो सभी सरकारी कार्यालयों को अय्याशी के अड्डे

पेज 12 का शेष

चुनावों में ये खुलकर धांधलियां जालसाजियां करें, हारों को जितवां दे, जीते को हरवा दे, महिला अधिकारी कर्मचारी चुपचाप हर आदेश मानेंगी और पालन करेंगी इसलिए 33 प्रश आरक्षण देना जरूरी है।

इसके विपरीत वर्तमान में महिला कर्मचारी और अधिकारियों से न केवल चपरासी, बाबु, अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी तक सब परेशान होते है। वरन् उनकी काम चोरी मक्कारी, जालसाजियां, भ्रष्टाचार, झूठ बोलने आदि का दंड भी उस विभाग के हर कर्मचारी-अधिकारी को भुगतना पड़ता है। महिला कर्मचारियों से लेकर आईएएस स्तर की महिला अधिकारियों का कोई कार्यालयीन निश्चित समय नहीं होता। 99 प्रश महिलाएं न तो समय पर पहुंचती है वरन् 12.30 से 1 बजे तक भी पहुंचेगी, 1 बजे से लंच की दुकानदारी शुरू तो 3 बजे तक चलती है, फिर 4.30 बजे से जाने की तैयारी शुरू। यह ठीक है, कि कुछ महिलायें इसकी अपवाद हो सकती है। ये हालात लो.नि.वि., जल संसाधन, लो.स्वा.यां., जिलाधीश, आदिम जाति, अनुसूचित, पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला बाल विकास, वन वाणिज्य कर, खाद्य एवं औषधि नागरिक आपूर्ति, जिला जनपद, पंचायतों, कलेक्टर, नगर पालिका निगमों, परिवहन, आबकारी, तहसील, जिला, जनपद, पंचायतों कार्यालयों से लेकर भोपाल के मंत्रालयों, मुख्यालयों तक केन्द्र सरकार के मंत्रालयों तक वर्तमान में महिला कर्मचारी अधिकारियों के हर विभाग में रहते हैं। कोई भी वरिष्ठ अधिकारी इस लेट-लतीफी, काम चोरी के बारे में पूछताछ करें या डांटने की तो दूर कुछ कहने का प्रयास में भी उस पर प्रताड़ित करने, छेड़ने, यौनाचार का दबाव का आरोप लगाकर इस अधिकारी की न केवल नौकरी चट कर ली जाती है, वरन् उसकी पारिवारिक व सामाजिक स्थिति भी बर्बाद कर देती है। बेशक जहां भ्रष्टाचार से कमाई के अवसर होते हैं, अपने प्रिय से मिलने की बात होती है, मनचाही प्राप्ति होती है, वहां समय से पूर्व आना व 8-9 बजे तक भी रूकती है। जिसकी सत्यता की पुष्टी हर विभाग में देखी जा सकती है।

यौनाचार और शैलेन्द्र सिंग जो तात्कालीन आयुक्त वाणिज्य कर था ने वाणिज्य कर विभाग में सन् 2006 के बाद नियुक्ति कई महिलाओं से संबंधों के चलते 15 से 25 वर्ष पुराने कर्मचारी अधिकारियों को पदोन्नति में वरिष्ठता का ख्याल रखे बिना उन सभी नवसिखाड़ुओं को न केवल पदोन्नतियां भी दीं और उन्हें अच्छी कमाई और बड़े वृत्तों में भी पदस्थ किया। उनसे बाकायदा सीधे फोन पर बात करके ही पदस्थापना और स्थानांतरण किया।

जबकि अधिकांश महिला अधिकारियों ने न केवल भ्रष्टाचार किया था वरन जिन्हें रंगे हाथों भी भ्रष्टाचार करते पकड़ा था, शिकायतें लंबित होने व जांच में होने पर भी पुरूष अधिकारियों, कर्मचारियों की अपेक्षा हर कदम उदारता दिखाई। बेशक ये हालात हर शासकीय विभागों, मंत्रालयों से लेकर संसद तक हैं। आखिर क्या कारण था कि मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में हारी हुई संसद स्मृति इरानी को पिछले दरवाजे से मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग सौंपा। फिर 90 प्रश महिला, सांसद, विधायक, पार्षदों, सरंपचों को चुने जाने के बाद भी कोई विशेष परिवर्तन आया, केवल संख्या बढ़ाने के अतिरिक्त औपचारिकताएं भर पूरी की जाती है। उनकी आड़ में भ्रष्टाचार बढ़ा। जन-धन का दुरुपयोग खुलकर किया गया साथ ही इसके विपरीत लक्षित लाभ, न सरकार को हुआ और न ही जनता को।

महिलाओं को नौकरी दिए जाने में, आरक्षण दिये जाने के विपरीत उसकी वास्तविक योग्यता, कार्यक्षमता के अनुकूल नौकरी दिये जाने के विपरीत उसकी वास्तविक योग्यता, कार्यक्षमता के अनुकूल नौकरी दिये जाने पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता। बेशक महिलाओं के कार्यक्षेत्र में उतरने से पुरूष युवा बेरोजगारी बढ़ी, समाज में पतन अपराध और मूलभूत आधार परिवारों में विखंडन, यौन अपराध, कार्यालयीन कार्य पर्यावरण बिगड़ा, भ्रष्टाचार, लापरवाही, जालसाजीयां बढ़ी, जिसके उदाहरण हर कदम हर विभाग में सैकड़ों हैं।

नारी संगठन आंदोलन, आयोग सब तात्कालिक लाभ और प्रतिस्पर्धा वह भी स्वयं अपने पुत्र, पिता, पति से ही करते है। हालात ये है कि अपने ही पुत्र, पुत्रियों को उनके लालन-पालन पोषण और सबसे महत्वपूर्ण अपनी ही संतानों को सामाजिक, धार्मिक और नैतिक संस्कारों से भी वंचित कर देते है। अधिकांश अधेड़ महिलायें, स्वयं ही स्त्रीयों को बाजार में उतरकर नौकरी व्यवसाय करने को हर दृष्टिकोण से अनुचित ठहराती है। कहते है एक पुरूष नौकरी करके अपने मां-बाप, भाई-बहन, पत्नी, पुत्र-पुत्री सभी को पालता है, जबकि यदि महिला नौकरी व्यवसाय करती है और कमाई करती है तो वह अपने माता-पिता, भाई-बहनों, पति, सास-ससुर, बेटे-बेटियों सबको ताना और कटू शब्दों के प्रहार से आर्थिक रूप से सक्षमता की आड़ में प्रताड़ित करती है, जिससे पारिवारिक कलह, तलाक से आगे चलकर उन्हीं महिलाओं के पति, पुत्र, पिता, ससुर आत्महत्या तक कर लेते हैं। आखिर सरकार और नारी संगठन, आंदोलन, महिला आयोग इन आधारभूत तथ्यों को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि नारी ही नारी के मर्म को बेहतर समझती है, फिर पुरूष से किस बात की और कैसी प्रतिस्पर्धा क्यों? जबकि नारी हर रूप में शास्त्रों के अनुसार पुरूष की मां की भूमिका ही निभाती है, तो फिर आरक्षण क्यों?

अफसर शिकायतकर्ता से बिना पूछे ही नस्तीबद्ध करवा रहे हैं मु.मं. ऑनलाइन

181 बकवास बन गई, खुलकर होने लगा भ्रष्टाचार

ऑनलाइन शिकायत की स्थिति जानों, शिकायत करने, स्थिति बताने का कोई विकल नहीं, ताकि जनता सच्चाई को उजागर न कर सके, वैसे अब तो फोन लगाते ही साथ शुरू हो जाती है आपकी शिकायत निराकरण हो चुका है, आप संतुष्ट हैं और बंद, नई शिकायत लेना बंद, पुलिस, शिक्षा बिजली विभागों के विरूद्ध नहीं ली जाती

दिल्ली के केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनते ही जनता के लिये जो सीएम हेल्पलाइन शुरू की थी, उसी तरीके से मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज ने भी जनता के लिये सीएम हेल्पलाइन शुरू की गई थी, जनता को कुछ राहत भी मिली थी और पूरे प्रदेश के मंत्रालयों से लेकर संभागों, जिलों, तहसीलों और ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, पालिकाओं तक हर अधिकारी कर्मचारी में हड़कंप मचा रहता था, यथार्थ में ये सीएम हेल्पलाइन पूर्णतः फोन पर कर्मचारी जो वहां ठेका श्रमिकों के रूप में सुबह 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक शिकायत लिया करते थे, परंतु अब वहां भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अब विद्युत वितरण कं., पुलिस, नगर निगमों, पालिकाओं की शिकायतें न पूरी सुनते हैं, न लेते हैं। न.घा. भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण, लो.नि.वि. लो.स्वा.यां., जल संसाधन पंचायतों की शिकायतें लेकर भी सुनी-अनसुनी कर देना मामूली बात हो गई है। जब तक शिकायत पंजीकृत नहीं होती, जब तक कार्रवाई संभव भी नहीं। 1417145 की शिकायत नगर निगम इंदौर के विरुद्धथी जिसका 4 माह बाद आज तक निराकरण तक नहीं किया गया। शि.क्र. 820796, 874313 की शिकायतों का क्या किया, महीनों बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, भोपाल में बैठे अधिकारियों ने जो जिस विभाग के थे सीएम हेल्पलाइन की पूरी टीम को खरीद लिया। जो शिकायते लिखने की तो दूर शिकायतकर्ता को ही उल्टे परेशान कर देते हैं कि वो शिकायतकर्ता ही भूल जाता है कि शिकायत क्या करना है। सीएम हेल्पलाइन नं. 181 की नौटंकियों, जालसाजियों के साथ ही पूरे प्रदेश के हर विभागों के विरूद्ध की गई शिकायतों और उसके निराकरण के नाम पर की गई जालसाजियों के विरूद्ध प्रदेश के समाचार पत्र लगातार तथ्यों के साथ प्रमाण उपलब्ध करवा रहे हैं। यथार्थ का प्रकाशन कर रहे हैं। परंतु नाम के अनुकूल सीएम हेल्पलाइन को भी भारी हेल्प की जरूरत है। पूरा स्टाफ और जिस कं. को ठेका दिया गया है उसके भी पूरा बदलने की जरूरत है, जिसमें तीन हिस्से अलग-अलग हो, जिसमें एक हिस्सा केवल जनता की शिकायतें पंजीबद्ध करें, वहीं पूरी जानकारी दूसरे को रिकार्ड किये गये टेप के साथ दें, दूसरा हिस्सा तत्काल शिकायत को उनके उच्च अधिकारियों से लेकर संबंधित को भेजने और प्राप्ति की पुष्टि और कार्रवाई पर निगाह रखें, तीसरा हिस्सा शिकायतकर्ता से संपर्क कर देखें कि निराकरण हुआ या नहीं विभाग से पूछे कि क्या किया, नहीं किया तो क्यों, सीधे मंत्रालय को सूचित कर कार्रवाई के लिए आगाह करें, शिकायतों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। सभी विभाग नीचे से लेकर ऊपर तक शिकायतों को टालो, झूठे निराकरणों की जानकारी बिना कार्रवाई के करने का अभ्यस्त हो चुका है। निराकरणों की तो दूर खुले में ऊपर के ऊपर ही शिकायतों का कागजों पर ही निराकरण 90 प्रश शिकायतों को किया जाकर इस सेवा को बहुत हल्के और मजाक में लेने लगे हैं। यदि इसमें मूल चूल परिवर्तन नहीं किया जाता तो बेहतर होगा मु.मं. इसको समाप्त कर दें। बेशक जिन खासों को ये ठेका सौंपकर मोटी कमाई करवाई जा रही है, उन्होंने करोड़ों रुपए सामने और पीछे से कमा लिये है। उनको भर थोड़ा सा बुरा लगेगा, परंतु जनता के धन की बर्बादी बचने के साथ ही जनता के शिकायत कर्ता कम से कम मु.मं. को तो नहीं कोसेंगे। बेशक वाहवाही लूटने और मंचों पर मिठू मियां अपनी शेखी नहीं बघार पायेंगे।

साप्ताहिक समय माया

कांक्रीट जंगल खड़ा करने से नहीं बनेगी स्मार्ट सिटी

स्मार्ट सिटी से ज्यादा आवश्यक है, जन-गण का सभ्य होना, भ्रष्टों की स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों रु. हजम करने के नये अवसर, जब तक जन में एक-दूसरे का सम्मान नहीं, गणों में ईमान नहीं, तब तक सभ्य शहर का दिवास्वप्न भी साकार नहीं

राष्ट्र का प्र.मं. मोदी भारत की 125 करोड़ जनता को जिस अच्छे दिन का सपना दिखाकर सत्ता में आया, उस मोदी ने जनता के खून पसीने की कमाई में से वसूले करो और पेट्रोल, डीजल, ईंधन, गैस को तीन गुना से ज्यादा कीमतों पर बेंचकर कमाये गये धन में से रु. 40 लाख करोड़ से ज्यादा अपनी 40 से ज्यादा विदेश यात्राओं में खर्च कर दिये हों, वो जनता की भावनाओं से खेलकर उन्हें अभी भी दिवास्वप्न दिखाने में ही जुटा हुआ है। कभी सफाई अभियान चलाने के लिये स्वयं झाड़ू उठाता हैं, तो कभी लाखों रु. प्रतिमाह का जनधन से वेतन पाने वाले और करोड़ों रु. भ्रष्टाचार में हजम करने वाले गणों से झाड़ू लगवाकर जनता को भ्रमित कर उलझाये रखता हैं, ताकि उसकी चालाकियों पर जनता की नजर न पड़े। स्मार्ट सिटी की संकल्पना भी उसी का एक हिस्सा हैं, बेशक धन खर्च करके कांक्रीट जंगल खड़े किये जा सकते हैं। उसकी आड़ में जनों द्वारा चुने गये और परीक्षायें उत्तीर्ण करके चुने गये गण अपनी जेबें भरेंगे। उससे स्मार्ठ सिटी की संकल्पना कभी साकार रुप नहीं लेगी, जब तक जनों के मन में सभी जन के प्रति सम्मान, समर्पण की भावना जागृत नहीं होगी। जनों के प्रति जन का सम्मान एक-दूसरे की सुख समृद्धि और गणों के ईमानदारी से जनसेवा का कार्य संपन्न करने के साथ ही स्मार्ट सिटी की संकल्पना स्वमेव ही साकार हो जायेगी, अर्थात सबका सभ्य होना ज्यादा जरूरी है।

भारत की आजादी के 68 वर्ष बाद भी शहरीय और ग्रामीण आबादी के विकास के लिये हर सरकार ने काम किया, परन्तु जहां गण चुने और नियुक्त किये गये सभी घोर भ्रष्ट हों, भ्रष्टाचार में रुपये का 50% पैसा भी निश्चित लक्ष्य की प्रगति करने में सक्षम न हो, जहां सारी योजनाओं, नियोजन के उद्देश्य में जनकल्याण के नाम पर स्वकल्याण, स्वकमाई कर धन अगर देश के कानूनों के कारण बदनामी से बचकर चलने के लिये विदेशों में जमा करें चुने और चुनकर आये गण वहां स्मार्ट सिटी की कल्पना और उसमें केन्द्र व राज्यों के जन धन का निवेश केवल शिगूफा, जनता को बहलाने का और धन हड़पने का नया तरीका हैं।

इस संबंध में म.प्र. लोक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता सतीश गर्ग से जब चर्चा के दौरान यह पूछा गया कि आखिर स्मार्ट सिटी की कल्पना का प्रारुप और उद्देश्य क्या है। उन्होंने भी जो दलीलें दी, जो निरर्थक थीं स्पष्ट हो गया कि केवल खोखली कल्पना है। जैसे कि एक नया शहर बसाया जायेगा, स्वाभाविक है भूमाफियाओं को लाभ पहुंचाया जायेगा, कृषि भूमि किसानों से येन-केन प्रकरेण छीनी जायेगी और कांक्रीट का जंगल खड़ा किया जायेगा, अर्थात स्मार्ट सिटी की कल्पना में पूर्णतः कांक्रीट जंगल, जहां चौड़ी-चौड़ी सड़कें, सुगम यातायात, चमचमाते कार्यालयों, उद्योगों जहां लोगों को रोजगार की सुविधायें भी मिलें, जैसा कि श्री गर्ग ने बताया, जिसमें रु. 500 करोड़ सरकार खर्च करेगी, आगे यदि हम ये मान भी लें पूरी स्मार्ट सिटी वाई फाई होगी, पूरी बिजली सौर ऊर्जा से बनेगी व मिलेगी, ईंधन गैस पाइप लाइन से मिलेगी, भोजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोजन के स्थान पर स्मार्ट टेबलें मिलेगी, या भोजन भी पचा पचाया ही मिलेगा, जो ब्ल्यू टुथ, रिमोट, वाइफाइ,वायरलेस, जीपीआरएस से सीधा पेट में पहुंच जायेगा, बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, बच्चे गर्भ में से ही अभिमन्यु की तरह ज्ञान प्राप्त करके या घर बैठे-बैठे या खेलते ब्ल्यू टुथ, रिमोट, वाइफाई, वायरलेस, जीपीआरएस जीएसएम की स्मार्ट तकनीक से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी के बाशिंदे होंगे। स्मार्ट सिटीज में गर्मी के दिनों में कश्मीर और कुल्लू मनाली की तरह शीतलता का एहसास होगा और शीत ऋतु में जैसलमेर की तपती रेगिस्तानी गर्मी का अहसास होगा, स्मार्ट सिटीज में बरसात नहीं होगी, बरसात और स्मार्ट एक-दूसरे के दुश्मन है। सारी स्मार्ट नेस को बरसात बर्बाद कर देती है। सड़कों पर पानी भर जाता है, वाहन चलने से पानी व कीचड़ उछलता है, चेहरे का मेकअप उतर जाता है। भवन चूने लगते हैं। इसीलिए स्मार्ट सिटी में बादलों को आने के पूर्व ही स्मार्ट सिटी के ऊपर से हटा दिया जायेगा स्मार्ट सिस्टम से, फिर सड़कों पर गर्मी में कश्मीरी मौसम के लिये एयर कंडीशनर और सर्दी में हीटरो की व्यवस्था भी बरसात के कारण ध्वस्त होने की संभावना रहेगी, पानी की स्मार्ट व्यवस्था में सीधे बादलों से वाई-फाई, ब्ल्यू टूथ रिमोट, जीएसएम से भवनों के ऊपर बनी टंकियों में सीधो पानी आपूर्ति की जायेगी, उसमें अडानी, अंबानी, टाटा या किसी विदेशी कं. को रिचार्ज का ठेका दिया जायेगा, जिसने सपनों के सौदागार प्र.मं. मोदी की विदेश यात्रा में सबसे ज्यादा चंदा दिया हो और मोदी की सभा में मोदी की वाहवाही करने नारे लगाने,

(शेष पेज 9 पर)

जनधन से एसी कारों में घूमने वाले भ्रष्टों को जन को कष्ट देना आनंदित करता है

हेलमेट लगा, सीधा दौड़ और मौत के मुंह में घुस

सत्ताधीश चाहे मंत्री, मुख्यमंत्री, इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के प्र.स. से लेकर जिलाधीशों तक सारे हरामखोर, घोर भ्रष्ट और जालसाज नहीं चाहते कि दो पहिया वाहन चालक उनके कुकर्मों, जनशोषण अरबों के भ्रष्टाचार और डकैती की तरफ अंगुली उठाये, इसलिए उसे हेलमेट पहना सीधे दौड़ने के लिए मजबूर करो ताकि उसके कान बंद हो जाए और वह दांये-बायें पीछे से आती मौत ही आहट न सुन सके, इन सबसे बच भी जाए तो हेलमेट के वजन से सिर और रीढ़ास्थि में दर्द और विकृति उत्पन्न होने से भी शीघ्र मौत हो जाये, भारतीय लोकतंत्र पूर्णतः लूट तंत्र और कष्ट तंत्र बन चुका है। जिनको जनता चुनकर भेजती है वो सत्ता में पहुंचते ही जनता को लूटने और उनकी तरफ कोई अंगुली न उठाये इसलिए उसको पर्याप्त इतने कष्ट पहुंचाने के लिए जनहितों के नाम स्वहितों को संरक्षित करने के लिए कानून तक बना देते है। ताकि वे उन कष्टों और परेशानियों में उलझा रहे और उनके कुकर्मों की तरफ अंगुली उठाने की हिम्मत तो दूर सोच भी न सके, उसमें न्यायालय भी जो पूर्व राष्ट्रपति के. आर. नारायणन के अनुसार न्याय का मंदिर नहीं जुएं के अड्डे हैं का यथार्थ

सिद्ध करते हुए उन धूर्त, गिद्ध सत्ताधीशों जिन्होंने उन्हें उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों पर पदासीन किया है, बिना जनहितों की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए उनकी हां में हां करते हुए आग में घी डालने का कार्य भी करते है। हेलमेट के प्रकरण में भी यही हुआ और हो रहा है। पुलिस प्रशासन और नगरीय निकाय अपनी जालसाजियों भ्रष्टाचार और जन-धन की लूट जिसमें हर वर्ष रुपए 2 से 5 अरब डकार लिए जाते हैं। परंतु जनता को स्वच्छ, सरल और सुगम सड़कें और यातायात व्यवस्था नहीं दे पाते हैं। जिसमें स्वाभाविक है दो पहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। प्रशासनिक बत्तमीजी, लूट और भ्रष्टाचार, जालसाजी जिसमें 11 किमी सड़क निर्माण बीआरटीएस में जो कि एक प्राचीन सार्वजनिक मार्ग था, जिसमें रु. 1200 करोड़ का जन-धन बर्बाद किया जिसमें से मात्र रुपए 600 करोड़ का काम हुआ और रुपए 600 करोड़ इंविप्रा., इंदौर नगर निगम जिलाधीश व अन्य ने भी डकारे, मात्र 25 बसों के 50 फेरों के लिए बाकी 2 लाख से ज्यादा दो पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को जानबूझकर इन मक्कार गिद्धों ने मौत से अठखेलियां करने के लिए छोड़ दिया, यहां तक इन गंदी मानसिकता के शूकरों ने तो अपनी कमजोरियां छुपाने, पलासिया चौराहे से एलआईजी चौराहे तक पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ तो क्या इंचभर जमीन पैर रखने के लिए नहीं छोड़ी और न ही इन धूर्त यातायात पुलिस, नगर निगम, इं. वि.प्रा. वालों ने कहीं ये संकेत पटल भी नहीं लगाया कि पैदल चलने वाले एलआईजी चौराहे से पलासिया चौराहे तक पलासिया की तरफ जाने वालों के लिए मार्ग की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसलिए जान जोखिम में डालने में न डाले। जब पैदल चलने वालों को फुटपाथ नहीं है तो दो पहिया वाहन की क्या बिसात है,

(शेष 9 पर)

जहां अधिकांश महिला कर्मचारी है, वहां के कार्यालयों को ही देख लेते

33% महिला आरक्षण, बना दो सभी सरकारी कार्यालयों को अय्याशी के अड्डे

एक तरफ महिलाये ही रोती है कि उनके बेटे महिलाओं की भर्तियों के कारण बेरोजगार है, फिर महिला कर्मचारी 12.30 तक आती है 4 बजे चली जाती है। तलाक और अतिरिक्त संबंधों को लेकर समाज बर्बाद हो रहा है। 3 माह के अवकाश को 6 माह किया जाना, महिलाएं काम कम गप्पे ज्यादा लगाती है, काम या विलंब से आने का कहने, पूछने पर छेड़छाड़ का आरोप, भ्रष्टाचार और सूचना के अधिकार में जानकारी न देने बलात्कार का आरोप लगाने से भी नहीं चूकती

मप्र के महाभ्रष्ट और भ्रष्टों के परमप्रिय मु.मं. शिवराज को कायम रखने, अपनी महानता, दरियादिली दिखाने के लिये बिना भविष्य की बर्बादी और दुष्परिणामों की समीक्षा किये, मंच पर खड़े होकर वरदान देने घोषणावीर अवश्य बन जाते हैं। भले ही वो घोषणायें पूरी हों न हो, घोषणायें पूरी करने में भले ही घोर जनधन की बर्बादी हो, शासन-प्रशासन ध्वस्त हो जाये उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी सैकड़ों घोषणाओं में से एक घोषणा जिसमें सरकारी कार्यालयों में 33 प्रश महिलाओं को आरक्षण देकर नौकरी देने की बात कही गई है, जो कि भारतीय संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है कि किसी को भी लिंग और जाति आधारित कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा तो फिर 33 प्रश के आरक्षण की व्यवस्था गैर संवैधानिक नहीं है, फिर जब महिलायें पुरुषों के साथ परीक्षा देकर हर सरकारी विभाग में नौकरी हथिया रही है तो लिखित परीक्षा उर्त्तीण करेगा उसे नौकरी मिलेगी और पर्याप्त संख्या में नौकरियां हर क्षेत्र, हर विभाग में मिल रही है। अब इंजीनियरिंग विभाग से लेकर लड़ाकू विमान तक सब तो कर रही हैं बेशक युवा पुरूषों में न केवल घोर बेरोजगारी और कुंठा बड़ी है, जिसके परिणामस्वरूप समाज में विखंडन, अपराध, अनैतिक व्यवसाय बढ़ा है, इसके जिम्मेदार भी ये धूर्त और मक्कार नेता हैं।

शासकीय कार्यालयों में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के प्राथमिक स्कूलों से लेकर महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक, प्राथमिक स्वा. केंद्रों से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालयों तक महिलाओं, पुरूषों के अनैतिक संबंधों को लेकर हर दिन किसी नई चर्चाओं से सुर्खिया बटोरते हैं। बेशक इसको लेकर मीडिया में ज्यादा हल्ला नहीं मचता पर रोमांस तो स्त्री-पुरुष का साश्वत सत्य है, किसी भी काल और युग में न रूका है, न रूकेगा, भले ही विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हो या हजारों रोगियों की जान चली जाये, सरकारी स्कूलों, शिक्षण संस्थानों, चिकित्सालयों, चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वच्छंद यौनाचार का खुला बोलबाला है, तो निजी शिक्षण संस्थाओं, चिकित्सालयों में तो नौकरी, वेतन छुट्टीयां तक देने में प्राथमिक शर्त है। 90 प्रश महिलाओं को इससे कोई गुरेज भी नहीं क्योंकि अपनी कमनीय काया ही उनका सबसे बड़ा अचूक हथियार है, जिससे वो अपनी हर इच्छा पूरी करती है। चाहे वो फिल्म, टीवी की चकाचौंध और लोकप्रियता का क्षेत्र हो या राजनीति यथार्थ महिलाओं की उपस्थिति का अनादिकाल से अनादिकाल तक एक जैसा रहा है और रहेगा। क्योंकि काम पृथ्वी पर जीवन का आधार है, इसीलिए शास्त्रों, वेदों पुराणों, धर्म शास्त्रों ने शादी और उससे समाज के सुचारू संचालन की जो व्यवस्था की है, वह जितनी पुरातन काल में मानव जीवन के नियमन के लिए आवश्यक थी उतनी ही वर्तमान और भविष्य में भी आवश्यक रहेगी। पर ये भाजपा के बड़े शास्त्रों के ज्ञाता, व्याख्यान देने वाले हमारे मु.मं. शिवराज को समझ नहीं आता। शायद उनका पावन उद्देश्य भी यही है कि शासकीय कार्यालय पूर्णतः अय्याशी और रोमांस के अड्डे बन जायेंगे तो कम से कम उनके भ्रष्टाचारों, जालसाजियों पर कोई अंगुली नहीं उठा सकेगा, वो भर्ती, वेतन, स्थानांतरण, नियुक्ति, पदस्थापना पदोन्नति से लेकर, सभी वैध-अवैध कार्यों, कानूनों को बदलने, संशोधन करने, शोषण आदि के कानूनों आदि को आसानी से थोपकर अपनी मनचाही आवश्यकताएं पूरी करेंगे।

(शेष पेज 11 पर)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958, इंदौर कार्यालय- मोबा. 9425125569

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.